General Budget ? Demands for Grants ? Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

माननीय अध्यक्ष : अब सभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों की संख्या 43 और 44 को चर्चा एवं मतदान के लिए लिया जाएगा।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभापटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभापटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप आपस में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने आपको अलाउ किया है? आपस में कोई भी चर्चा नहीं किया करो।

प्रस्ताव पस्तुत हुआ:

?कार्य-सूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 43 और 44 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों के भुगतान के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाए।?

Demands for Grants, 2024-2025 in respect of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying submitted to Lok Sabha

(Amount in Rupees)

No. of Demand	**Name of Demand**	**Amount of Demand for Grant Submitted to the House**	
		Revenue	**Capital**
43	Department of Fisheries	2597,44,00,000	19,00,00,000
44	Department of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	4693,57,00,000	237,67,00,000
TOTAL		**72,91,01,00,000**	**2,56,67,00,000**

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर 20 ? सुश्री सयानी घोष जी।

क्या आप पहली बार चुनकर आई हैं?

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर) : जी सर।

प्रो. सौगत राय (दम दम) : सर, ये बहुत अच्छी हैं। आप इनका भाषण सुनिये। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनको बीच में मत टोकना और सलाह मत देना। आप पीछे की सीट पर चले जाइये।

? (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं जादवपुर लोक सभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं। मैं अपनी लीडर ममता बनर्जी जी, अभिषेक बनर्जी जी और जादवपुर लोक सभा क्षेत्र के सारे वोटरों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया तथा इस सदन में भेज कर बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह सदन है। सदन में इन नेताओं को, उन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता है। आप डिमांड फोर ग्रांट्स पर बोलिये।

? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : सर, यह संदेश ? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, आप मंत्री महोदय को यह सलाह क्यों नहीं देते? ? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : सर, मैं जादवपुर लोक सभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहां पर जिता कर भेजा और यह पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रणनीति तथा धोखेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें। क्योंकि हाल ही में नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी, जो देश की एकमात्र महिला मुख्य मंत्री भी हैं, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया। वह बंगाल के ? (व्यवधान) अरे, अभी तो शुरुआत है। यह तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बोलना चाहती हूं कि वे बंगाल के हक के लिए यहां पर सवाल उठाने आई थीं, वे बंगाल के लोगों की बात रखने यहां पर आई थीं, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से इस सदन में उपस्थित, वहां जो सदस्य बैठे हैं ? (व्यवधान

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नीति आयोग या बाहर की किसी भी घटना को सभा में अवगत नहीं कराएं। हम डिलीट करेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो।

? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : सर, एक लाइन? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।

? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का ... * का काम किया गया है और उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया गया। आगे जाकर बंगाल के लोग आपकी पार्टी का माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा।? (व्यवधान)

सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस सदन और इस देश की थर्ड लार्जेस्ट अपॉजिशन पार्टी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी आगे हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेगी, चाहे वह चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश का मुद्दा हो या 700 से ऊपर आन्दोलनजीवी किसानों की मौत हो? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, इसलिए मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है, आप उसी विषय पर बोलें।

? (व्यवधान)

सुश्री सयानी घोष : सर, मैं उसी पर आ रही हूँ।

सर, नीट के घोटाले से लेकर जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेकर रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस मुझे यही आपसे कहना था।

Respected, Sir, *Maa Maati Manush* is the Magna Carta of the governance of West Bengal and our party and I feel truly honoured that today I have been given the opportunity to talk on a Ministry which is intrinsic to the *Maa Maati Manush* of the country. हमारे किसान अपने मवेशी को, अपनी फसलों को माँ की तरह पूजते हैं। वे जिस खेत में हल चलाते हैं, उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the Government?

Sir, Indian agriculture supplies around 58 per cent of India's livelihood and as a principal source of income for half of the population accounts for 17 to 18 per cent of the country's GDP. About 70 per cent of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? अगर इसका जवाब आप देश के किसानों से पूछेंगे, तो वे आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पर अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई।

Sir, the exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current Government and wholesale fodder inflation hovering between 25 per cent to 28.6 per cent in the last two to three years is at a 9-year high.

सर, किसान खुद क्या खाएंगे? वे अपने परिवार के लोगों को क्या खिलाएंगे? अपनी गाय-भैंस, भेड़-बकरियों को क्या खिलाएंगे? ऐसी ही वारदात होती है, जो गरीबी से जूझते हुए किसान को अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने पर मजबूर करती है और अंत में वे अपनी खुद की जान ले लेते हैं।

सर, पिछले 10 सालों में 1 लाख 12 हजार किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 10 साल में, इस देश में हर दिन एवरेज़ 30 किसान अपनी जान ले लेते हैं। इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वह राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया, वह फकीर की तरह।

सर, ये गौ-रक्षा की भी बहुत बातें करते हैं। देश के लोगों को यह पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India. The Union Minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha, ?Yes, the country is deficit in fodder?. So, it means that cows are dying without food in Government-owned *goshalas*, especially the BJP ruled States. About 74,000 cattle had died at Panjrapole in Surendra Nagar and Banaskantha districts of Gujarat in the last three years. About 200 cows were found dead in Shivpuri district of Madhya Pradesh. Around 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh, and 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP Government in Rajasthan.

सर, फॉडर क्राइसिस था, पहले खाना ही नहीं मिला। फिर खाना मिल भी जाए, तो इतना महँगा है कि किसान खरीद नहीं पा रहा है। फॉडर इंफ्लेशन है। खाना मिल भी जाए, तो पशुओं की बीमारी है। इनसे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या क्या किया?

The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal, Husbandry and Food Processing presented its Report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several States, and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन माता की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नम्बर एक है।

India is contributing almost 24.46 per cent of global milk production, but since the Government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned this country from being the largest producer of milk to an importer of milk.

In the last 10 years, due to stagnation in milk production, the gains of the White Revolution have been systematically white-washed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on highways, protesting against meagre remuneration for their produce. The price of one litre of milk, on the other hand, has increased by a massive 55 per cent in the past 10 years. It was Rs. 36 per litre in 2014 and now it is Rs. 56 per litre in 2024. When this Government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees two per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP.

आम आदमी के उपयोग में आने वाले दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर पांच परसेंट की जीएसटी है। क्रीम, कंडेस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12 परसेंट की जीएसटी, और अमीरों के हीरों पर सिर्फ डेढ़ परसेंट की जीएसटी है। सरकार उनको रिलीफ देती है, जो विदेशों में जाकर मिल्क शेक और लात्ते कॉफी की चुस्कियां लगाते हैं। यह सरकार उनको रिलीफ नहीं देती, जो आम आदमी दो पैकेट दूध खरीदने से पहले दस बार सोचता है।

सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि ?संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे?। India ranks second in egg production in the world, लेकिन अंडे का फंडा यही है कि भारत के बच्चों की किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं है। मिड-डे-मील के चलते हफ्ते में अगर एक-दो अंडे मिल भी रहे थे, तो कहीं धर्म के नाम पर, तो कहीं महंगाई के चलते, उसे बंद करने की मांग उठ रही है।

Sir, more than 50 per cent children, under the age of 5, suffer from chronic malnutrition in the country and roughly 17 per cent children are under-weight and yet, most BJP-ruled states do not serve eggs in the Mid-Day Meal Scheme. This is the example of ? poshankaal? in India.

सर, अंत में मैं मच्छी पर आना चाहूंगी। आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन हम क्या करें, हम तो मच्छी-भात वाले बंगाली हैं, हमको तो बोलना ही पड़ेगा। We should not to forget that 2.8 crore fisherfolk are employed directly in catching fish in the country and millions are employed in the value chain of selling fish, and aquaculture.

-

-

13.13 hrs (Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

India stands third in the world in terms of fish production, contributing eight per cent to global fish production and ranks second in aquaculture production. The PM talks about Blue Revolution, but this Government has allocated only 0.045 per cent funds out of the total Budget for the flagship scheme Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). Even after this meagre allocation, they did not did not utilize 39 per cent of the funds and in 2023-24, they did not utilise 24 per cent of the funds allocated.

Madam, भले ही सरकार को ?मणिपुर? शब्द से अलर्जी हो, but the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the State has led to endangering the fish species in India's largest freshwater body in Manipur - the Loktak Lake.

Madam, the Government has to generate employment opportunities, investment in areas such as exports, post-harvest processing, and import substitution. It has to deal with adversities like over-fishing, depleting fish stocks, pollution, disease outbreak, destruction of habitat and climate change.

Madam, my own Parliamentary Constituency has assembly constituencies like Baruipur, Sonarpur and Bhangar which are heavily dependent on these sectors for livelihood. The main crops grown are wheat, rice, vegetables, fruits, oilseeds, pulses, cotton and jute, and animal husbandry is mostly practised by women through self-help groups in South 24 Parganas. They rear a wide range of domestic animals, including cattle, poultry, goats particularly the Black Bengal Goat, and the Pekin Duck. I take extreme pride in saying that in the last five years of the TMC Government, the CM Mamata Banerjee has allocated a massive amount of Rs. 76,680 crores to agriculture and its allied sectors for their development.

Madam, the Government of West Bengal has achieved remarkable success in implementation of the State?s scheme, namely, Banglar Dairy under which the State-owned company is providing financial incentive at the rate of Rs. 11.5 per litre of raw milk directly to the bank accounts of primary dairy farmers through Milk Unions. Banglar Dairy procured 3.55 crore kilograms of milk in 2023, for which Rs. 109 crores were paid to dairy farmers through Direct Benefit Transfer. And, 47,900 fresh Kisan Credit Cards have been issued in the last three years for animal husbandry. Up to 30th November 2023, Rs. 393 crores were sanctioned to the marginal animal rearers in the rural areas.

Bangla Shasya Bima scheme is a fully State-funded scheme for crop insurance. A total of 1.28 crore farmers were enrolled under the scheme during 2023-24. Seventy lakh farmers got claim settlement worth Rs. 247 crores. A total of 76,049 farmers are getting pension amounting to Rs. 1,000 per month under the Jai Bangla Scheme.

Sufal Bangla scheme was introduced in 2014 for ensuring remunerative prices for agricultural produce, integrating about 80,000 farmers and procuring about 100 metric tonnes of perishables daily. The annual turnover of this project is now Rs. 106 crores. Seventy-seven new stores have been opened in financial year 2023-24. A total of 186 Krishak Bazars, sub-market yards are running successfully and providing excellent marketing infrastructure for aggregation and ease of marketing access. And to be mentioned, West Bengal has one of the largest cold storage capacities in the country, at more than 87 lakh metric tonnes, with 620 cold storages. New investment of Rs. 239 crores is upcoming in this sector this year with an employment opportunity for nearly 20,000 people. ?अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के चार झोंके अगर इधर से भी गुजर जायें तो? ।

Now, coming to the demands of pending funds from the Government of India to West Bengal on animal husbandry and welfare, 50 per cent of the Central share, that is, Rs. 12.72 crore for the financial year 2023-24, being the recurring expenditure for Mobile Veterinary Units is pending with the Government of India. The Government of West Bengal requested for sanctioning additional 126 MVUs for 2024-25. However, it was regretted citing want of funds. The proposed Central share of Rs. 49.93 crore for financial year 2024-25 for Assistance to States for Control of Animal Diseases has not yet been released by the Government of India. Despite repeated persuasion, the Department of Animal Husbandry and Dairying has not released the Central share of Rs. 10 crores for financial year 2024-25 for various ongoing national livestock mission schemes, including the project for the establishment of Buck Semen Station at Haringhata. यह तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाल का, अभी अन्य मिनिस्ट्रीज की बात करें तो पता नहीं कहाँ पर जाकर यह खत्म होने वाला है ।

महोदया, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया है, उससे बड़ी तालिका यह बनेगी कि 10 साल में क्या-क्या कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। वर्ष 2014 में जो किसान यह सोचकर कि मोदी है तो मुमकिन है और अच्छे दिन के ख्वाब देखकर बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वह बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है, शायद अभी वह किसान है भी नहीं। इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बड़ा बलवान भी होता है। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं: ?shomoy gele shadhon hobena? इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी और 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। मैं यही बोलकर अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।

CUT MOTIONS

(TOKEN)

THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF FISHERIES (PAGE 154) BE REDUCED BY RS. 100. **(43)**

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL): I beg to move:

Need to provide incentives to the fishermen community in the form of insurance and interest subvention scheme. (37)

(सांकेतिक)

कि पशुपालन और डेयरी विभाग शीर्ष के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 156) में 100 रुपए कम किए जाएं। **(44)**

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में डेयरियों के उपयुक्त संचालन के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (13)

किसानों को उनके दूध उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता। (14)

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (15)

*m16 **श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :**

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (16)

SHRI VISHALDADA PRAKASHBAPU PATIL (SANGLI): I beg to move:

Need to formulate an effective policy to subsidise dairy industry for sustainable milk production in the country. (19)

Need to formulate a policy of fixing milk prices so that the milk producers get fair and remunerative price or a revenue sharing model for the processed dairy items across the supply chain. (20)

Need to introduce the Swaminathan formula or C2+50% formula for the dairy sector to ensure milk producers not only get a remunerative prices but also secured profits. (21)

Need to allocate more funds to increase appointments of veterinarian and set up Primary Veterinary Centres in Sangli, Maharashtra. (22)

Need to allocate more funds to maintain health of poultry industry which gets impacted due to adverse climate change events such as heat waves. (23)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

तीन वर्ष से कम आयु के नर मवेशियों की बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता। (24)

नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता। (25)

मवेशियों में गांठदार त्वचा (लम्पी स्किन) रोग जैसी बीमारियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता (26)

दुधारू पशुओं के लिए केंद्र दवारा प्रायोजित पशु बीमा योजना) शुरू किए जाने की आवश्यकता। (27)

राजस्थान में ऊंट प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता। (28)

राजस्थान में मवेशियों/पशुओं में विषाणुजनित रोगों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने की आवश्यकता। (29)

नागौरी बैल की विश्व प्रसिद्ध नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता। (30)

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु दौड़ पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता। (31)

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move:

Need to provide subsidy for improving farm infrastructure and for reducing congestion in farms which impacts cattle health and increases rate of spread of diseases. (38)

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD : I beg to move:

Need to control the rise of fodder prices in the country which has resulted in rise of milk prices. (41)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : महोदया, धन्यवाद।

आज देश का ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 11वाँ बजट एनडीए सरकार ने पेश किया है।? (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : महोदया, देखिए उधर पंचायत चल रही है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण।

? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, उधर भी पंचायत चल रही है। उधर तो और भी बड़ी पंचायत चल रही है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूँ कि आप चर्चा को सुनिए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्लीज बैठिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूँ कि कृपया आप लोग बैठिए।? (व्यवधान)

दुष्यंत सिंह जी, आप बोलिए।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां) : सभापति जी, यह एक हिस्टोरिक मूमेंट है क्योंकि इस सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया है। देश के 140 करोड़ नागरिकों ने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को तीसरा मौका दिया है। जब प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2014 में शपथ ली थी, उस समय उन्होंने किसान भाइयों की इनकम बढ़ाने की बात कही थी। किसानों को सिर्फ खेती से ही इनकम न हो बल्कि एनिमल हसबेंडरी से भी इनकम प्राप्त हो, इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने काम किया है। किसानों की इनकम बढ़े, इसके लिए

वर्ष 2019 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्र रूप से एनिमल हसबेंडरी, डेयरी और फिशरीज मंत्रालय का गठन किया। प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व द्वारा भारत के मिल्क प्रोडक्शन में 51 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 5.5 परसेंट दूध उत्पादन से आता है। आज लगभग 9 करोड़ लोग इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। मछली के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने ब्लू रेवोलूशन की बात कही है। मछुआरों की आय दोगुनी हो, इसके साथ-साथ कोल्ड चेन इनफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है। किसानों का उत्पाद सही ढ़ग से और सही समय से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए रोड इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। ?जय जवान, जय किसान? हमारे देश की शान है और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए बहुत काम किए गए हैं। 21वीं पशुधन गणना चल रही है और दिसम्बर तक यह गणना पूरी हो जाएगी।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसकी झलक इस बजट से दिखाई देती है और इसके संदर्भ में आज हम एनिमल हसबेंडरी, डेयरी और फिशरीज पर चर्चा कर रहे हैं। पशुपालन द्वारा पावर्टी एलिविएशन भी हो रहा है। मैं राजस्थान से जीत कर आया हूं। मैं अपने मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में ज्यादातर जनसंख्या पशुपालन से अपनी जीविका चलाती है। यहां एक परसेंट पानी है और एक परसेंट पानी के साथ लोग पशुओं के साथ काम करते हैं। पशुपालन का पावर्टी एलिविएशन में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी है। आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन से ब्रीड की इम्प्रूवमेंट करने का काम किया जा रहा है और इसमें आगे ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। आज कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम की जरूरत है, जो डेयरी को सपोर्ट करे, पशुओं में जो रोग होते हैं, उनमें रोकथाम हो, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो कम प्रोडक्शन होता है, उसमें बढ़ोतरी हो। इसके साथ-साथ दूध से बच्चों की बोन डेनसिटी, उनकी ग्रोथ, न्यूट्रिशन में वृद्धि होती है। वर्ष 2014 से लेकर आज तक मिल्क प्रोडक्शन 57.7 परसेंट करके हमने दिखाया है। इसमें वर्ष 2014 में 146 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता था लेकिन आज 2024 में 230 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यह छह परसेंट की एनुअल ग्रोथ है। मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रप्रदेश आदि राज्य सरकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में लगभग छह परसेंट इसकी हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ लोगों को नौकरी मिल रही है। दूध उत्पादन में लगभग 23 परसेंट की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में हम देश और विदेश में नम्बर एक पर हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के करकमलों द्वारा और उनकी नीतियों के द्वारा हम ऐसा करने में सफल हुए हैं।

आज पर कैपिटा दूध की उपलब्धता 459 प्रतिदिन हो रही है, जो वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है। हमारे क्षेत्र में जो लाइवस्टॉक हैं, उनमें बोवाइन में 303 मिलियन कैटल्स, 74.26 मिलियन शीप्स, 148 मिलियन गोट्स, और 851 मिलियन पॉल्ट्री हैं।

महोदया, अभी मेरे से पहले वक्ता अंडों के बारे में बोल रहे थे। अंडों के उत्पादन में हम दूसरे रैंक पर है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की नीतियों के कारण हुआ है कि वर्ष 2021-22 में अंडा उत्पादन 129.60 बिलियन हुआ है। इसमें 8 प्रतिशत का इज़ाफा हुआ है। यह इज़ाफा केवल इसमें ही नहीं हुआ है, बल्कि मीट प्रोडक्शन में भी हुआ है। इसके संबंध में नीतियां कैसे बनीं, मैं इसके बारे में छोटा विवरण देना चाहता हूं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे 80 मिलियन फार्मर्स के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) शुरू किया। वे चाहते हैं कि हमारे यहां जो स्वदेशी नस्ल हैं, उनकी जेनेटिक अपग्रेडेशन करने के साथ-साथ, मिल्क एन्हांसमेंट के साथ-साथ उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। आज हम देख रहे हैं कि वर्ष 2025-26 तक 2400 करोड़ रुपये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत लोगों को दिए जाएंगे। पहले वर्ष 2013-14 में भैंस का दूध उत्पादन 1648.7 किलोग्राम प्रति पशु था, अब वर्ष 2021-22 तक हमने इसको 2048 किलोग्राम प्रति पशु करके दिखाया है।

नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हम लोगों ने दूध उत्पादन की राशि 9.95 लाख करोड़ रुपये करके दिखायी है। माननीय प्रधान मंत्री जी को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम भी शुरू किया है। इसमें नए लैब्स खोले गए हैं। इसके साथ-साथ नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेन्टर्स की बात रखी गयी है। इसमें सेक्स-सॉर्टेड सीमेन रखने की कोशिश की गयी है और यह भी कोशिश की गयी है कि इसमें 90 प्रतिशत प्रोडक्शन फीमेल काभ्स का हो। इसके साथ-साथ 592 डिस्ट्रिक्ट्स को आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन से जोड़ने का काम किया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्रालय ने ?मैत्री? का काम शुरू किया है। इसमें ब्रीड मल्टीप्लीकेशन, प्रोजेनी टेस्टिंग, जीनोम सेलेक्शन और गोकुल ग्राम की बात रखी गयी है। इतना ही नहीं, आज लोगों को नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें डेयरी को-ऑपरेटिव्स को जोड़ा गया है और प्राइवेट सेक्टर को भी इससे जोड़ा गया है। इसमें फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे गए हैं और ई-गोपाला एप्प के द्वारा लोगों को जोड़ने का काम किया गया है।

महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्रालय के द्वारा नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट का काम किया गया है। इसमें ?स्ट्रेंथेनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी ऑफ मिल्क? की बात रखी गयी है। इसमें प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बात रखी गयी है। इसमें प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की बात रखी गयी है। इसमें मिल्क क्वालिटी की टेस्टिंग और इसके अपग्रेडेशन करने की फैसिलिटी की बात की गयी है। इसमें 1568 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है, जिसमें जाइका की भी राशि है। इसमें कई

प्रोजेक्ट्स हैं, जिनसे हमारे राज्यों को बहुत लाभ हुआ है। इसमें 185 प्रोजेक्ट्स के द्वारा 28 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों को लाभ देने का काम किया गया है। इसमें लगभग 15,000 डेयरीज़ को को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ से जोड़ा गया है। इसमें 23,790 डेयरी सोसायटीज़ को ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट का काम दिया गया है।

महोदया, सरकार की यह कोशिश है कि मिल्क में एडल्ट्रेशन न हो। इसमें सरकार ने ध्यान देने का काम किया है। डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को दिसम्बर, 2017 में क्रेडिट किया गया था। इसमें मॉडर्नाइज्ड मिल्क प्रोसेसिंग और चिलिंग वैल्यू एडीशन के लिए हम लोगों ने बात रखी थी। इसको एनडीडीबी के द्वारा जोड़ने की बात रखी गई थी। इसमें मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क चिलिंग, मिल्क ड्राइंग कैपेसिटी और वैल्यु एडिशन की बात रखी थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 में एफपीओ के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का काम किया है। एफपीओ के माध्यम से जोड़ने के साथ-साथ सॉफ्ट लोन देने की बात रखी गई थी। जब कोविड-19 आया था, तब 2003 करोड़ रुपये इसमें आउटले किए गए थे। इस तरह से सभी लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया गया था।

आज लाइवस्टॉक हेल्थ मिशन के द्वारा हमारे क्षेत्र में 2,465 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें 64 रिवाइज़ एस्टिमेट्स से ज्यादा हैं और इसका ऑब्जेक्टिव एनिमेल को हेल्थ रिस्क से बचना है। वैक्सीनेशन के द्वारा पशुओं को फुट एण्ड माउथ डिसीज़ से बचाने की जरूरत है। अभी मेरे से पहले वक्ता यहां लम्पी के बारे में बोल रहे थे। मैं उस प्रांत से आता हूँ, जहां लम्पी ने हमारे क्षेत्र को तबाह कर दिया और पूरे क्षेत्र को खराब कर दिया। राजस्थान में उस वक्त श्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तब एनिबल हस्बेंडरी मंत्रालय द्वारा लम्पी वायरस को देखा गया और उसके लिए डोज़ दिए गए, परंतु उस वक्त की राज्य सरकार ने इसमें पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां लम्पी से दिक्कतें बढ़ गईं। आज हमें यह बात बोलने की ज़रूरत है कि इन योजनाओं के द्वारा सब्सिडी भी दी गई है। पोल्ट्री फार्म के लिए 25 लाख रुपये और भेड़ पालन के लिए लगभग 50 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है। हमारे फोडर यूनिट्स के लिए भी 50 लाख रुपये दिए हैं। इसको सिडबी से जोड़ने का काम किया गया है। इसके साथ, एनिमन हस्बेंडरी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत से जोड़ने के लिए एफपीओज़ के द्वारा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया गया है। पूरे राजस्थान में पशुओं की जो नस्ल हैं, जैसे गायों की नस्लें ? राठी, गीर, थारपारकर, कंकरेज़ और भैंसों की नस्लें ? मुर्रा, ज़फरेदी, बडावरी, बकरियों की नस्लें ? मारवाड़ी, शेखावटी, जकराना, और भड़ों की नस्ले ? चोखला, नाली, जैसलमेरी और सुनाडी और हमारे प्रांत का मेन एनिमल कैमल है। आज आरसीडीएफ के द्वारा लोगों को जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। राजस्थान में इस क्षेत्र में बड़े अच्छे काम हुए हैं। मिल्क, ब्रीड और अलाइड एक्टिविटीज़ को जोड़ने का काम किया गया है।

मुझे कोऑपरेटिव डेयरी के बारे में कुछ कहने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि कोऑपरेटिव डेयरी जो अमूल द्वारा शुरू किया गया है, जो कैरा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, वर्तमान में 1800 कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, जिसमें लगभ 36 लाख किसान जुड़े हुए हैं और 3.5 करोड़ लोग डेली दूध बेचते हैं। उनको 200 करोड़ रुपये की राशि डेली डीबीटी के द्वारा मिलते हैं। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है। उनका यह इकनॉमिक मॉडल, आणंद पैटर्न का मॉडल सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी लागू किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जब कर्नाटक में हमारी सरकार थी, तब वहां पर नंदिनी प्रोग्राम के नाम से डेयरी विकास में काम किया गया है। इसके साथ-साथ जब हमारे राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब 3,100 नवीन पशु चिकित्सालय उप-केंद्र खोलने का काम किया गया है। हमारे क्षेत्रों में गऊशालाओं में पशु आहार देने का काम किया गया। हमने गऊशालाओं को 1,096 करोड़ रुपये देने का काम किया। इसमें पशु नस्लों में सुधार करने का का किया गया और बीमा का काम करने का काम किया है। भाजपा सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किया है।

अब मैं मछलियों के बारे में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। इस विषय पर मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के कर-कमलों के द्वारा आज देश दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जो मछली का उत्पादन कर रहा है। इसमें ग्लोबल शेयर 8 परसेंट है। 2.8 crore people are involved in this. मुझे यह बोलने की जरुरत है। 70 सालों में 3,682 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। वर्ष 2014 के बाद इस विभाग में, माननीय प्रधानमंत्री जी के होलिस्टिक एप्रोच के साथ डेवलपमेंट एंड सोशियो-इकोनॉमिक को जोड़ने के साथ उन्होंने सोचा है। इसमें उन्होंने 30,570 करोड़ रुपये की राशि रखी है। फिशरीज एंड एक्वा डेवलपमेंट के साथ-साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने इनलैंड वाटरवेज में फिशरीज को बढ़ावा दिया है। उन्होंने मैरिन में भी लोगों को सहायता देने का काम किया है। उन्होंने फिशरमैन वेल्फेयर का काम करने का प्रयास किया है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है। उन्होंने एक्वेटिक हेल्प देने का काम किया है।

हमारे क्षेत्र में जो ऑरनामेंटल फिशिंग होती है, वह छोटी मछली होती है। उसको भी मदद देने का काम किया है। इसको देखते हुए आज पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के द्वारा हमारे तमिलनाडु में सी पाथवे बनाने का काम किया गया है। इसके साथ-साथ हमारे मेजर फिशिंग हार्बर्स चेन्नै, कोच्ची, पाराद्वीप, पेटोघाट एंड विशाखापट्नम में भी काम करने का काम किया है। आज हमारा जो फिशरिज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वह 7,522 करोड़ रुपये है। इसमें जो राशि दी गई है, वह हार्बर डेवलपमेंट, फिशिंग लैंडिंग सेंटर, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश को ट्रांसपोर्ट करने, हैचरीज और प्रोसेसिंग का काम दिया गया है। हमने इन नौ-दस सालों में अपने लोगों को काम देने का प्रयास किया है। हम थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बने हुए हैं। हमने लोगों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा से जोड़ने का काम किया है। इससे लोगों की आय बढ़ी है।

इसके साथ ही जो फिश प्रोडक्शन हुआ है, वह 81 परसेंट बढ़ा है। इनलैंड वाटर में हमने प्रोडक्शन बढ़ाने का काम किया है। हमने 10 लाख टन तक बढ़ाने का काम किया है। हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग हुई है, वह 63,969 करोड़ रुपये की है। लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया गया है। फिश प्रोडक्शन के साथ-साथ हमने श्रिम्प कल्टीवेशन में भी 267 परसेंट का ग्रोथ किया है। प्रोडक्शन एंड फिशिंग हार्बर के साथ-साथ सागर परिक्रमा यात्रा को भी जोड़ने का काम किया है। यह 8000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हमने एक्सिडेंट इंश्योरेंस से भी लोगों को जोड़ने का काम किया है। एफपीओज़ एंड कोऑपरेटिव में 2,092 फिश फार्मर्स को भी जोड़ने का काम किया है। वेसल्स कम्युनिकेशन में भी हमने काम करने का प्रयास किया है। इसमें 364 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

हमने वर्ष 2024 की बजट में भी मैन्युफैक्चरिंग और श्रिम्प की बात रखी है। इसमें मैरिटाइम प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट की बात रखी है। हमने मैन्युफैक्चरिंग, श्रिम्प और फिश पिट्स पर कस्टम्स ड्यूटी कम की है। इसे कम करने से हमारा बूस्ट ऑफ एक्वाकल्चर एंड सी फूड्स एक्सपोर्ट्स बढ़ा है। हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन ब्लैक टाइगर, ब्रूड स्टॉक एंड बर्न्स पर 5 परसेंट का डिडक्शन हुआ है। इसमें न्यूक्लियर ब्रिडिंग सेंटर में हमारे श्रिम्प में जो एनुअल राशि थी, उसमें भी इजाफा हुआ है। इससे हमारा जो उत्पादन है, उसमें 30 परसेंट कॉस्ट का रिडक्शन हुआ है। इसमें हमें नाबार्ड से 80 परसेंट प्रोजेक्ट के लिए राशि मिली है और तीन परसेंट इंट्रेस्ट सबवेंशन भी मिला है। इसमें 639 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बने हैं। हमारी जो राशि है, वह 6,523 करोड़ रुपये है, which is amounting to USD 7.38 billion, इतना ही श्रिम्प कंट्रीब्यूशन हमारे क्षेत्र से हुआ है। हमारे फ्रोजन श्रिम्प की जो राशि है, वह लगभग 40 हजार करोड़ रुपये है।

जब हम इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करते हैं तो हमें डीप सी फिशिंग के बारे में भी बात करने की जरुरत है।

हमारे यहां 100 फीट डीप में जो सोर्स हैं, वहां डीप सी माइनिंग होनी चाहिए। जो 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूजिव इकोनॉमिक जोन है, इस पर भी मुझे बात रखनी है। श्री मारौरी कमेटी वर्ष 2004 में बनी थी। इस कमेटी ने पाया था कि रिवाइवल ऑफ फिशिंग करना है, लेकिन फिशिंग का रिवाइवल उस समय हो नहीं पाया। उस समय जो फिश की मात्रा थी, वह अनएक्सप्लायटेड रह गई। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? इसमें 60 पर्सेंट सैंक्शनिंग केंद्र सरकार से होगी। हमारे क्षेत्र में वैसल्स को पैसे देने का काम किया है। इसमें अपग्रेडेशन ऑफ वैसल्स का काम किया गया है। इसमें स्टार्ट-अप्स और टेक्नोलॉजी को जोड़ने का भी काम किया गया है। मुझे यह भी कहना है कि ट्यूना फिशिंग अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ होती है। इसका 12 पर्सेंट का वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल है। मुझे इंडियन ओशन कमीशन ऑफ ट्यूना के बारे में कहना है कि इसको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जोड़ने की आवश्यकता है।

आखिर में, ऑर्नामेंटल फिशिंग हमारी सेकेंड मोस्ट पापुलर हॉबी है। वर्तमान में लगभग 18 से 20 बिलियन यूएस डॉलर का इसका मार्केट है। वर्तमान में जो फिश है, इसमें फ्रेश वाटर और मरीना वाटर फिश है। हमारे सिनारियो में जब हम देखते हैं, तो ऑर्नामेंटल फिशिंग .4 पर्सेंट है और हमारी रैंक 31 है। मंत्री जी, इसको आप देखेंगे तो इसे बढ़ाने की जरूरत है।

वर्तमान में एक्सपोर्ट 8.40 करोड़ रुपये है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यह 11 पर्सेंट की दर से बढ़ रहा है। इसको अगर बढ़ायेंगे तो लोगों को इसमें काम मिलेगा। जहां से मैं आता हूं, राजस्थान में इसकी बहुत पूछ है।

राजस्थान में महाराणा प्रताप यूनीवर्सिटी ने एग्रीकल्चर में ऑर्नामेंटल फिशिंग के बारे में बात रखी थी। इसको बढ़ाने का कम वर्ष 2006 में शुरू किया गया। इस काम में राज्य सरकार का भी योगदान जरूर मिला है। हमारे क्षेत्र में इनलैंड वाटर फिशिंग में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। झालावाड़ और बारां के क्षेत्र में इनलैंड फिशिंग की डिमांड बढ़ रही है। आपने डिस्ट्रिक्टिवाइज जो आपने योजना दी है जिसमें इनलैंड फिशिंग की मात्रा बढ़ रही है। क्या हमारे क्षेत्र में आप मदद करने का प्रयास करेंगे?

आखिर में, मुझे कहना है कि जहां एरिड कंडीशन होती है, वहां ऑर्नामेंटल फिशिंग की फास्टर ग्रोथ होती है। इसमें बॉडी आर्नामेंटल फिशिंग की कलरेज होती है। इसमें इनका रीप्रोडक्शन सही समय पर होता है। इसकी एक्सपेंडिंग कैपेसिटी बहुत हो सकती है। हमारे यहां जयपुर, अजमेर और सभी क्षेत्र में इसका लाभ मिल सकता है। हमारे यहां इनलैंड फिशिंग की 8.78 पर्सेंट 9 साल में हुई है। यह ग्रोथ 131 लाख टन्स की है। इसकी ग्रोथ इसलिए हुई कि माानीय प्रधान मंत्री जी यह सोच है। उनकी सोच के साथ-साथ 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि लाइव स्टॉक में 7.38 पर्सेंट की ग्रोथ है, फिशरीज़ में 8.9 पर्सेंट की ग्रोथ है। यह ग्रोथ तब हो सकती है, जब हम लोग इस पर ध्यान देंगे।

मैं माननीय प्रधान जी को, डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और डिपार्टमेंट के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे प्रांत राजस्थान के लिए भी अच्छी नीति बनाकर, सहयोग करके इनलैंड वाटर बेस को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में मछुआरों को काम मिल सकेगा। हमारे क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन आगे बढ़े, अपने पशुओं को भी हम आगे ले जाएं और हमारे प्रांत के सभी जिलों में इसका लाभ मिले। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद को देता हूं, क्योंकि ?मोदी है तो मुमकिन है।?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Madam, I stand before you today with immense satisfaction to participate in the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for 2024-25.

This Budget Session has seen extensive deliberations on various critical sectors, including railway, education, and health, which undeniably hold significant administrative priorities. However, I wish to draw your attention to the pivotal role of fisheries and animal husbandry in the sustenance and well-being of humankind.

The protein essential for human growth is predominantly derived from fish and milk. Our current society witnesses numerous challenges faced by fishermen and local farmers who are the backbone of this sector. Their livelihoods are closely linked to the dynamics of fisheries and animal husbandry, making them vulnerable to any environmental and economic changes.

Madam, most of the fishermen and the livestock farmers are residing either in the seaside or in the valleys. The first casualty of every disaster is the poor people. A recent example is the Wayanad landslide which has vividly illustrated how environmental changes can have devastating effects on those who depend on fisheries and animal husbandry for their survival. Tragically, the majority of the lives lost in this incident were the farmers.

Additionally, coastal floods caused by high tides are increasingly affecting the fishermen, disrupting their livelihoods. Such incidents emphasize the urgent need to strengthen the sector, ensuring it more adaptive and efficient.

After the Independence, we witnessed two major revolutions, that is, the White Revolution and the Blue Revolution, and these Revolutions have shaped India's agricultural landscape but despite several years passing, these related sectors of agriculture have not been seen as equally important as other sectors and have not reaped the rightful benefits they deserve.

Madam, India has the total coastline of 7,516 kilometres including 2094 kilometres of inland territories and 5,422 kilometres of mainland coastline. Gujarat has the longest coastline in India and my State, Kerala, has the fifth longest coastline with 590 kilometres.

Fisheries and aquaculture continue to be the important source of food nutrition and livelihood for millions. The fisheries sector significantly contributes to the national economy with a share of total Gross Value Added (GVA) at cost prices for 2021-22 estimated up to Rs. 1,48,000 crore making it 1.07 per cent of the national GVA and 6.86 per cent of the agriculture GVA.

India is the second-largest producer of fish which globally accounts for 8.92 per cent. But the Union Budget 2024-25 has provisioned only Rs. 2,616.44 crore for various Centrally Sponsored Schemes and other infrastructural development under the Department of Fisheries. Yet, adequate discourse on the rights and well-being of the fishermen is often undermined. So, today, my intention is to bring this matter to your immediate attention.

The fishermen's community has the closest association with our seas and their livelihood is deeply intertwined with the waters. The 2016 Marine Fisheries Census accounts for a total population of 3.77 million fishermen in India and a total of 3,477 marine fishing villages.

Madam, India?s per capita fish consumption has reached up to 8.89 kilograms in 2021 from 4.9 kilograms in 2005. The fish-eating population has increased their consumption by 66 per cent from 7.43 kilograms to 12.33 kilograms. Fish has become an important source of protein for the people of India. But have we really counted and acknowledged the contribution of fishermen?

The fishermen of this country face a storm of challenges. The fishermen community is the most backward section of the country. Their livelihood is seasonal and the fish they catch are highly perishable goods, rendering them with minimal short-term financial returns

only. This unsubstantial remuneration causes their bargaining power to be low and leaves it conditional upon several external factors. The stress they endure is similar to tide loan which is ever present and overwhelming.

The other factor is their health. Their health is another tragic concern. The average life expectancy of a fisherman is just 55 years compared to the average Indian?s life expectancy, which is 70.8 years. This stark disparity arises because the fishermen often work without protective gear facing the merciless sea?s dangers daily. Exposure to harsh weather conditions, long hours on unstable boats and the physical toll of their labour ? all contribute to their deteriorating health. They are living in morbid conditions in India. Lack of job security adds another layer of stress, with no assurance of income or safety nets. Yet, their sacrifices remain in the shadows and unnoticed.

Madam, another critical issue they face is the devastating erosion and damage to their homes due to sea turbulence, violent storms and rising tides. Unfortunately, the compensation provided to them in these dire situations is grossly inadequate, failing to cover the costs of repair or relocation. The Government must urgently address this disparity to ensure that adequate and timely compensation is provided to safeguard these communities.

Further, in the name of benefiting fishermen, coastal tourism is promoted by opening up our shores to luxury resorts and commercial infrastructure. It is disrupting the marine ecosystem. These constructions, far from bringing prosperity, are eroding the very foundation of the fishermen?s livelihood. The noise, pollution and restricted access to traditional fishing areas push them further into the margins. However, natural tourism, which coexists harmoniously with the environment, should be encouraged. It is imperative that we protect our shores from the aggression of insensitive tourism-related construction to ensure that the true beneficiaries are the fishermen and not just the tourism industry.

Also, the introduction of a new coastal highway in Kerala poses a threat to the livelihood and homes of our fishermen. We already have NH66 which connects Kasargod with Thiruvananthapuram via Kannur, Kozhikode, Malappuram, Guruvayur, Kochi, Alappuzha, and Kollam. The proposed coastal highway would merely replicate what NH66 already provides. Moreover, NH66 is listed for expansion into a six-lane highway. The construction of a new coastal highway would displace numerous fisherfolk, and this cannot be justified for a redundant infrastructure project.

Madam, relocation away from the sea is not a viable solution for these fishermen. Their lives, culture and livelihoods are intricately linked with the ocean. Hence, the solution is the proper implementation and strict enforcement of Coastal Regulation Zones (CRZ) norms. It cannot be overlooked any further. These regulations can provide much-needed protection to our coastal communities and the ecosystems to ensure the sustainable livelihood of our fishermen.

The tribal communities in forest gets so many Constitutional protections. The fishermen are very poor like the tribes. So, we must provide them the Constitutional protection in the form of laws.

Sir, I would like to bring to your attention another issue pertaining to the fisheries in Kerala. The once-booming shrimp industry in Kerala is now grappling with a crisis of unprecedented proportions. America used to import $ 6 million worth shrimp every year from Kerala.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRI BENNY BEHANAN: Madam, I am the first speaker from my party. Please allow me some more time.

Recently, the US has imposed a ban on the Indian shrimp imports under the guise of sea turtle conservation which is significantly affecting the livelihoods of thousands of fishermen along our coasts. While such measures aim to protect the endangered turtles, they also bring significant challenges to our shrimp industry. There is a smaller number of turtles at the Kerala shores. They might convert it to frozen shrimp and use that in the future or might export it to other countries, but the poor fishermen do not benefit rather get economically crushed because of this. Interestingly, these restrictions do not impact the shrimp producers in Andhra Pradesh as they are cultivated in inland farming. But that is not the case for the shrimp industry in Kerala. As we navigate these new regulations, it is crucial to support our fishermen and explore viable solutions to sustain our shrimp industry.

Therefore, my suggestion to the Government is that aquatic reforms have to be implemented for the benefit of the traditional fishermen in the country. They should be rescued from all the miseries.

As far as the livestock is concerned, India processes extensive livestock and poultry resources. India remains the world?s largest milk producer with the milk production reaching 209.6 million tonnes.

I will point out quickly some issues faced by the animal husbandry and dairying industry. The White Revolution, introduced by former Prime Minister Indira Gandhi, was a transformative initiative that reshaped India's dairy industry. Amul, for example, is a shining beacon of this revolution. It has become synonymous with milk and dairy products across the nation. However, despite this remarkable success, the processing of milk byproducts in India remains woefully inadequate. Even though India is the biggest milk producer, its productivity is very low. When we compare it to Switzerland and other countries, their productivity is very high. They have also started producing some byproducts out of milk. While the countries worldwide have advanced far beyond the traditional offerings like ice cream and *pedas*, India lags behind in creating a diverse array of innovative dairy products. Nations have developed extensive ranges of fortified dairy products and specialized health-oriented options that cater to evolving consumer preferences.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRI BENNY BEHANAN: Madam, I would like to conclude my speech by pointing out some more issues.

Many worship cow as a God, yet they often fail to provide these animals with the best health and shelter facilities. This hypocrisy highlights a broader issue, ?Reverence without responsibility benefits no one.? I urge the Government to sincerely look into this matter.

Therefore, it is important that this Budget should provide substantial provisions to enhance the lives of individuals who rely on fisheries and animal husbandry. Regrettably, it is with a heavy heart that I must express my disappointment that the current Budget falls short of addressing these crucial needs. It lacks the necessary steps to ensure the well-being and sustainability of those whose livelihoods depend on this sector.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको पांच-सात मिनट का अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन अब तक कम्प्लीट नहीं हो पाया।

? (*Interruptions*)

SHRI BENNY BEHANAN: Madam, I want to conclude with my last sentence.

I urge this esteemed House to recognise the significance of fisheries and animal husbandry and to amend the Budget to reflect a greater commitment to improving the conditions of our fishermen and farmers. Their contributions to our society are invaluable and it is our duty to support them in every possible way.

Thank you very much.

14.00 hrs

श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल (फतेहपुर) : सभापति महोदया, आपने मुझे पशुपालन और मत्स्यपालन के बजट पर चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर में पशुपालन और मत्स्यपालन का विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में पशुपालन का गहरा नाता है। महाभारत जैसे काव्य में भगवान श्रीकृष्ण को गायों का चरवाहा बताया गया है, जो पशुपालन की महत्ता को दर्शाता है। गोकुल और वृंदावन में गायों का पालन-पोषण भारतीय समाज के लिए आदर्श माना गया है। भारतीय परम्परा में पशुधन का महत्व इतना अधिक रहा है कि कामधेनु को मानव की समस्त इच्छाओं का पूरक माना गया है। कामधेनु को सर्व कामधुक भी कहा जाता है। इसको हमारी धार्मिक कथाओं में एक दिव्य गाय के रूप में देखा गया है, जो अपने धारक को हर प्रकार की समृद्धि और सुख प्रदान करती है।

महोदया, इसी प्रकार मत्स्यपालन का भी हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य अवतार में भगवाण विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर मानवता की रक्षा की थी। ये कथाएं न केवल धार्मिक महत्व को रखती हैं बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि मत्स्यपालन कितनी पुरानी और महत्वपूर्ण परम्परा है। पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों और मछुआरों के जीवन में न केवल आर्थिक रूप से समृद्धि लाते हैं बल्कि हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा भी हैं। आज भी ग्रामीण जीवन इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हमें इन परम्परा को संजोए रखना चाहिए।

महोदया, भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत दुनिया में सबसे अधिक पशुपालन करने वाला देश है, जिसकी कुल संख्या लगभग 535.78 मिलियन है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशु पर निर्भर हैं। पशुधन ने छोटे किसानों के परिवारों की आय में 16 परसेंट का योगदान दिया है, जबकि सभी ग्रामीण परिवारों के लिए यह औसत 14 परसेंट है।

महोदया, पशुधन ग्रामीण समुदाय के लिए दो-तिहाई लोगों की आजीविका प्रदान करता है। यह भारत में लगभग 8.8 परसेंट आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। भारत में पशु संसाधन विशाल है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन की दौर में, जहां मानसून की अनियिमितता या मौसमी विभीषिकाएं फसलों को तबाह कर देती हैं, उस वक्त ये पशुधन ही किसानों के लिए सहारे का काम करते हैं। इसके अलावा पशुधन, मत्स्यपालन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवथा की भी रीढ़ हैं। ये न केवल स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं बल्कि हमारे समाज को स्थायित्व और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।

महोदया, दुर्भाग्य है कि वर्ष 2024-25 के बजट में यह सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दे रही है। वर्ष 2023-24 में पशुपालन और डेयरी के लिए राजस्व बजट 4289.09 करोड़ रुपये से घटाकर 4283.57 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वहीं पशुधन, स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के कार्यक्रम के बजट में मामूली वृद्धि करते हुए इसे 2,349.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,465 करोड़ रुपये किया गया है। यह वृद्धि भी इस क्षेत्र की व्यापक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम पशुधन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र की जरूरतों को अनदेखा करते हैं। मौजूदा बजट आवंटन में इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी यह अपर्याप्त है।

इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में मछली योजना, पशुपालन विभाग में संशोधित बजट को घटा दिया गया था। सरकार की इस उदासीनता के चलते, उनकी इस क्षेत्र के विकास की गंभीरता को प्रकट करता है। इस क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटन की आवश्यकता है, ताकि पशुधन और मत्स्यपालन के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और देश को और समृद्ध किया जा सके।

महोदया, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। पशुओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं है। मेरी लोक सभा क्षेत्र फतेहपुर में छुट्टा जानवरों से सबसे ज्यादा किसान परेशान हैं एवं छुट्टा जानवर भी जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। उनके लिए सरकार द्वारा इस तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, ताकि उनके लिए चारे का

प्रबंध किया जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश में खासकर बुंदेलखंड का जितना इलाका है, वहां पर ये छुट्टा जानवर किसानों का तो नुकसान कर ही रहे हैं, अब वे लोगों को मार भी रहे हैं। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं कि सांड़ों ने फलाने व्यक्ति को मार दिया, सांड़ों ने उसको गिरा दिया। इस तरीके की बात सुनने को मिलती रहती है।

महोदया, छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में उनके लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था की थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छुट्टा जानवरों को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। उनके खाने के लिए मात्र 30 रुपये दिए जाते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में पशुपालन और मत्स्यपालन की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने फतेहपुर जिले के लिए कुछ मांग करना चाहता हूं। हमारे यहां पराग डेयरी के दो बड़े-बड़े प्लांट्स हैं, लेकिन पिछले पांच सालों से दोनों डेयरी के प्लांट्स बंद पड़े हैं। वहां किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए उनको चालू किया जाए। डेयरी संचालन सुव्यवस्थित नहीं है। फतेहपुर जिले में एक वेटनरी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। वह बुंदेलखंड के दोआब का एरिया है। अगर वहां एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोल दिया जाएगा, तो पशुओं की समृद्धता में बहुत बड़ा योगदान होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पशुओं की बदहाल हालत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी बातें तो बड़ी-बड़ी करती है, लेकिन वहां स्थिति बद से बदतर हो गई है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): Hon. Speaker, Vanakkam. Even though the Union Government has ignored providing the funds and schemes for the welfare of Tamil Nadu, Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Muthuvel Karunanidhi Stalin, who has learned administrative skills from Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar, has been fulfilling the assurances given to the people. I thank him for this opportunity. With the blessings of the Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, I begin my speech by thanking the voters of the Theni Parliamentary Constituency, the DMK cadre, and the leaders of coalition parties. This is my maiden speech.

Thirty-one departments of the Union Government must be discussed, but only five ministries or departments are selected for discussion in Lok Sabha. I strongly condemn the Union Government for this.

Altogether, an amount of Rs 1,20,000 crores was allocated for Agriculture, Animal Husbandry, Dairying, and Fisheries, out of which Animal Husbandry and Dairying has been allocated only a meager amount of Rs 4,000 crore. This is inadequate. Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar, who was the Chief Minister of Tamil Nadu for five terms, established the Tamil Nadu Veterinary University in 1989. Since then, seven colleges have been established under this university. The gifted son of Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar and Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy Shri M.K. Stalin has been implementing several schemes aimed at protecting farmers and promoting the growth of animal husbandry in Tamil Nadu. I urge through this august House that Rs 300 crore should be allocated for the Veterinary Science Medical Colleges under the National Livestock Mission to ensure the protection of every livestock in Tamil Nadu. The government is engaged in providing mobile medical assistance to animals at the Assembly Constituency level. However, this is insufficient. At the block-wise and panchayat union-wise levels, it should be provided for cattle, and the Union Government should allocate more funds for such schemes.

Ours is a rural area. I come from a village called Narayanathevanpatti. It is an ordinary village with many cattle. There are resources for fisheries and dairying. There is one indigenous breed called Malai Maadu which has its origin at Theni, Tamilnadu. These breeds go to the green fields of the forests for food and then return to the plain areas to rest. There is no shed for this breed. The State Government is providing assistance for these breeds, but it is still inadequate. For the development of this breed, the Tamil Nadu Government has proposed the establishment of a research institute at Theni Veterinary College. Therefore, I request the Union

Government to allocate the necessary funds for setting up this research institute. This initiative will greatly contribute to the advancement of veterinary sciences and the enhancement of breed development in the region.

Foot and mouth disease and miscarriage are the two diseases which an affect the cattle. Under the National Animal Disease Control Programme, the Union Government currently allows two vaccinations per year to control foot and mouth disease and spontaneous abortion. However, scientific research indicates that three vaccinations per year would be more effective in controlling these diseases. It is recommended that the vaccination schedule be adjusted accordingly to better manage and prevent the spread of these diseases.

The Lumpy Skin Disease (LSD) is the disease which significantly affecting cattle both southern states and northern states. It is imperative that the Union Government take immediate steps to develop a vaccine to control this disease. Currently, vaccinations meant for goats are administered to bulls as well, but this vaccine does not effectively control LSD in bulls. The Union Government, which developed a vaccine for goats, should find another vaccine for use in bulls. Only then can we protect our cattle from LSD. The invention and distribution of an effective vaccine will help protect the cattle population and support the livelihoods of farmers in the region.

The Union Government takes pride in claiming that it is protecting all the cattle, but the Union Government earns a revenue of Rs 50,000 crore by exporting beef to foreign countries. Madam, this is my maiden speech, as I have already mentioned. Beef worth Rs 50,000 crore is exported to foreign countries every year. My colleague, when speaking here, mentioned the number of livestock present in the country. There are 30 crore and 30 lakh cows, 7 crore and 40 lakh sheep, and 14 crore and 80 lakh goats in our country. Additionally, there are 90 lakh pigs and 85 crore and 10 lakh hens in our country.

14.14 hrs

(Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

The population of our country is 130 crores. How can this amount of beef be sufficient? Only when we protect our livestock can we ensure an adequate supply of animal flesh as food for humans. This should be taken care of by the Union Government.

The Union Government is spending Rs 3,000 crore on the installation of statues. This new Parliament building was constructed at a cost of Rs 2,000 crore. I place my justified demand before the Union Government to allocate funds to increase the population of livestock in the states to ensure the provision of animal flesh as food for humans.

India contributes 25 percent of the world?s milk production. Tamil Nadu stands in 11th place with a record production of 10.60 million tonnes. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin has been providing adequate funds to the Animal Husbandry Department of Tamil Nadu, which is why Tamil Nadu is securing 11th place in the country in milk production. Private milk producers are creating stiff competition by disturbing the farmers who produce milk and distribute it through cooperative milk societies. These private parties sell milk by mixing chemicals into it. A committee should be set up by the Union Government at the national level to look into these irregularities and control this sector.

You are levying GST on so many things. For branded ghee, GST is 12 percent, and for ordinary ghee, GST is 5 percent. If someone runs away to a foreign land after availing loans to the tune of Rs 16 lakh crore, you just waive off such loans, but for milking a cow, poor farmers struggle a lot. To secure farmers? livelihoods, all dairy livestock should be insured at a 100% subsidy or with a minimal premium, similar to crop insurance. Give them the needed loans. Allocate funds for providing such loans to farmers. You have not done

this. As the GST for ordinary ghee is 5 percent, the branded ghee should also have a GST of 5 percent. This will increase milk production and ensure that money reaches the milk producers. This is our intention.

Throughout India, there is a customs duty of thousands of rupees. Our Hon. Chief Minister Thalapathy, in the election manifesto of DMK, said that if the INDIA Alliance comes to power at the Centre, there will not be any toll plazas or toll fees in Tamil Nadu. People voted for him. It was a huge victory, giving 40 out of all 40 seats in Tamil Nadu and Puducherry to the DMK-led alliance. I urge that vehicles carrying milk to different places should be exempted from paying toll fees at plazas.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TAMILSELVAN THANGA: Sir, this is my maiden speech. Under the MGNREGA Scheme, we have engaged in desilting work of ponds. I am of the humble opinion that if we use MGNREGA labourers for the construction of buildings for milk producer societies, these societies will also be protected.

Another important issue in Tamil Nadu is the fishermen?s issue between India and Sri Lanka. The Indian Government is showing a partisan attitude towards the fishermen?s issue. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy has raised concerns about the arrest of Tamil fishermen by the Sri Lankan Navy, besides confiscating their fishing boats and keeping them in custody. Such boats number 174. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has provided compensation of Rs 6 lakh each to the affected families whose boats were confiscated and kept by the Sri Lankan Navy. Even today, a total of 74 Tamil fishermen are languishing in the prisons of Sri Lanka. A committee has been set up, but the Union Government has not accorded permission for the committee set up by the Tamil Nadu Government to visit Sri Lanka. The said committee, called the Indo-Sri Lanka Joint Committee, was set up in 2022. It met only once in 2022. After that, I could not understand the intention behind the meeting of this committee. The Indian army and forces managing the sea area between India and Sri Lanka, where the problem persists, should provide protection in that area and seek a solution between the two countries in this regard. But the Union Government is non-committal and uninterested. We are winning all 40 seats, and the BJP could not win even a single seat in Tamil Nadu and Puducherry. Will you punish us for making you face defeat?

What I am trying to say is this: What is called the rural economy? Dairying, fisheries, and animal husbandry constitute 30 percent of the rural economy. You should uphold this economy and protect our people. That is our intention.

Lastly, I wish to raise an issue pertaining to my constituency.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI TAMILSELVAN THANGA: Sir, just one minute. The people of my constituency gave me 5,71,493 votes in the Lok Sabha Election. I won due to the mighty leadership of our leader Shri Thalapathy M.K. Stalin. I am speaking here in this House. The Union Government should have a sympathetic approach. I must mention the long-pending demand of the people of my Theni parliamentary constituency. There should be a new rail route between Dindigul and Sabarimala. We have been hearing about this demand since our childhood. I urge the Union Government to take concrete steps to bring this new rail route to fruition and make it a reality.

Moreover, a bypass should be constructed between Usilampatti, Andipatti, Theni, and Bodi. This route covers a distance of just 100 kilometers to reach Madurai, which should only take 1 hour and 30 minutes. However, due to heavy traffic congestion, it currently takes 3 hours. I therefore urge that this bypass should be constructed immediately.

The Mullaperiyar Baby Dam should be strengthened, and steps should be taken to maintain the water level at 152 feet in the dam. Additionally, there are several traditional hill paths connecting Theni district in Tamil Nadu and Idukki district in Kerala. One of them is the Sakkanoothu Mettu path. By constructing a road on this 4 km long hill path, the Devaram area of Theni and the Udumbanchola area of Kerala can be connected. This will eliminate the necessity to travel approximately 60 km via Bodimettu.

I also urge the Government to expand the Mayiladumparai to Mallapuram Road. By constructing a road from Mayiladumparai in Theni district to Mallapuram via Usilampatti and Peraiyur in Madurai district, travel distance and time can be reduced. For a long time, people have been demanding the construction of a road between Mayiladumparai and Mallapuram. Considering this, about 19 years ago, a road was constructed for about 20 km from Mayiladumparai to Mallapuram. However, over time, this road has become damaged due to a lack of proper maintenance. The road was narrow, and no maintenance work was undertaken. Therefore, I request the government to come forward to expand this road.

Additionally, I request that the Union Government ensure that all trains passing through the Solavanthan constituency should stop at every station. This will greatly benefit the people of the region by improving accessibility and connectivity.

I conclude my speech with this demand. Thank you.

SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): Thank you, Chairman Sir. As a farmer, I am proud to participate in this discussion on the budget for the Ministry of Fisheries and animal husbandry. Animal husbandry is an important field in our state Andhra Pradesh and our state occupies an important position in animal husbandry. Let it be milk production or animal husbandry we are playing an important role. Around 70% of the area is under rural areas but we do not have adequate veterinary facilities. Transportation of animals for veterinary care is more expensive than the medical treatment. Therefore, apart from providing veterinary hospitals for animals, mobile hospitals may also be provided in rural areas. Under the leadership of our chief minister Nara Chandrababu Naidu steps are being taken to promote animal husbandry and its allied sectors. We seek support from the union government for these endeavours. In the coming 5 years, with your support our state government will promote animal husbandry. There is a need to set up polyclinics. Due to mining activities, there was depletion in grazing fields which resulted in scarcity of fodder for animals. I request the union government to extend subsidies for cattle fodder in our state. From 2014 to 2019, then Chief Minister N Chandrababu Naidu promoted veterinary care by allocating adequate funds. We expect a similar approach in the coming 5 years from our chief minister and therefore I request the minister to take steps to support and promote animal husbandry in our state.

In our country after Gujarat, Andhra Pradesh has the longest coastline with a span of 1000 kms. Fishermen are facing many difficulties in their profession and as a result they are migrating to other places. We need to provide mini jetties and ports to protect our fisheries and fishermen. At the same time, we need to provide relevant information to the fisherman to help fishing. Fishermen are facing health problems at an early age of 45 years and their eyesight is getting weak, due to harsh working conditions. Special health camps should be organised for the health benefits of fishermen. Sometimes fishermen lose lives while fishing and their families do not get timely compensation. It takes around 4 to 5 years to get that compensation. I request the Government to release compensation for the families of fishermen at the earliest. In some cases, even dead bodies are not found. The jurisdiction in which such an incident happens, FIR should be registered in English so that families of deceased fishermen can get the compensation in time. As FIR details are registered in the regional language of that particular state it is difficult to claim compensation in some cases. This matter was brought to the notice of the union government on previous occasions as well. Therefore, I request that the format for registering FIR should be in English. I request through you, additional veterinary colleges in our state which will benefit our state in ensuring health care of animals. Thank you.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : सभापति महोदय, आपने मुझे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश के किसानों की ताकत और जीवंतता, जिन्हें अक्सर अन्नदाता कहा जाता है, उनसे देश का मत्स्यपालन, पशुपालन और दुग्धपालन निकटता से जुड़ा है। समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के उत्थान के लिए सरकार का प्रयास प्रशंसनीय है। वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय को 7,138 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 27% ज्यादा है।

एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग को 2,465 करोड़ रुपये की राशि लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए आवंटित की गयी है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 64% ज्यादा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2024-25 के लिए 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 19% की कमी दर्शाती है। यह थोड़ी कम है।

20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गौवंश, 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 906 मिलियन सुअर और लगभग 851 मिलियन मुर्गियां हैं। डेयरी एकमात्र ऐसी कृषि कोमोडिटी है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोज़गार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.6 प्रतिशत का योगदान देता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि युनाइटेड नेशंस का एक अंग है, मानता है कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। दिसम्बर, 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश ने वर्ष 2022-23 में कुल 2,30,577.03 टन दूध का उत्पादन किया, जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट 3.83% है, जबकि वर्ष 2021-22 में 5.77% था। यह दूध के उत्पादन में थोड़ी कमी को दर्शाता है। इसलिए मेरा कहना है कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि विश्व में हम पहले स्थान पर बने रहें।

महोदय, देश में 53.5 करोड़ मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की पहचान की गई है, ताकि इनकी देख-रेख हो सके एवं किसानों की आमदनी बढ़े। हमारी इंडिजिनस स्पीशीज़ भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है, वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है।

भारत किस तरह अनोखे प्रयास कर रहा है, इसका एक उदाहरण ?गोबर धन योजना? है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गोबर का इकोनॉमी में बढ़ता महत्व उल्लेखनीय है। आज भारत में पशुओं के गोबर से बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारी एनडीए सरकार की कोशिश है कि डेयरी प्लांट्स अपनी जरूरत की अधिकतर बिजली गोबर से ही पूरी करें और इससे किसानों को गोबर का पैसा भी मिलने का अवसर प्राप्त हो।

मैं इस सदन का ध्यान पशुओं को होने वाली बीमारियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। जब पशु बीमार होते हैं, तो किसानों की आय भी प्रभावित होती है। इसलिए भारत में हमें पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सिनेशन पर ध्यान देना है। हमारी एनडीए सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2025 तक पशुओं को फूट एंड माउथ डिजीज़ और ब्रुसिलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने लम्पी स्किन डिजीज़ की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है।

महोदय, पशुपालन हो, मछली पालन हो या मधुमक्खी पालन हो, बीते 5 वर्षों में मत्स्य और पशुपालन से जुड़े विकल्पों पर माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है। मेरा सुझाव है कि भारत के डेयरी सेक्टर को विस्तार देने के लिए इनोवेशन एवं नई तकनीक की जरूरत है ताकि हमारे ग्रामीण इलाकों में भी इनोवेशन एवं नई तकनीकी का फायदा पहुंचे। हमें यह भी समाधान खोजना है कि ग्रीन चारे की उचित व्यवस्था कैसे सुनिश्चत की जाए और जानवरों को पोषक आहार कैसे मिले। माउथ डिजीज़ से 51 करोड़ जानवर, जैसे गाय, भैंस, भेंड़, बकरी और सुअर आदि प्रभावित होते हैं। मेरा सुझाव है कि 51 मवेशियों का टीकाकरण हो।

भारत वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वर्ष 2023-24 में 174.45 लाख टन रिकॉर्ड मछली उत्पादन दर के साथ इसकी लगभग 8 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी है। कृषि विश्वस्तर पर 2.5 बिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है। भारत में पशुधन और मुर्गीपालन के विशाल संसाधन हैं, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के उत्पादन डेटा 2020 के अनुसार, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 8वें स्थान पर है। भारत के एक्सपोर्ट का 50 प्रतिशत केवल मीट और मीट प्रोडक्ट्स के हैं।

देश में "राष्ट्रीय गोकुल मिशन", जो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया, जिससे स्वदेशी गैर-जातीय नस्लों के विकास और संरक्षण होगा, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और डेयरी में लगे 80 मिलियन किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। NABARD के द्वारा सस्ते ब्याज दर पर ऋण भी

दिया जा रहा है तथा पुनः भुगतान की अवधि वर्ष 2031-32 की पहली तिमाही तक है।

यूनाइटेड नेशन के Sustainable Development के 17 Goals के तहत हमारी सरकार ने "राष्ट्रीय पशुधन मिशन" शुरू किया है। इस योजना का फोकस रोज़गार सृजन, उद्यमिता विकास के साथ-साथ मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

भारत सरकार के Livestock Census- 2019, के अनुसार 16 प्रजातियों में पशुओं की 184 नस्लें हैं। 184 नस्लों में 38 देशी नस्लें खतरे में हैं। मेरा सुझाव है कि 38 देशी नस्लों को बचाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, मछली पालन के लिए बिहार सरकार को वर्ष 2022-23 के लिए 303.64 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जिसका बकाया आवंटन अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। महोदय, संसद के माध्यम से, मेरा आग्रह है कि इस बकाया राशि को यथाशीघ्र निर्गत किया जाए ताकि मछली पालन को राज्य में और बढावा दिया जा सके।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज, तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर के परिचालन क्षेत्र में आता है। एनडीपी-1 के तहत, जिसमें राशन संतुलन कार्यक्रम, चारा विकास और ग्राम आधारित दुग्ध खरीद प्रणाली से संबंधित तीन उप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए 5.99 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसमें 5.66 करोड़ रुपए दिये गये, शेष बकाया राशि अभी तक नहीं दी गई है। मेरा आग्रह है कि इस बकाया राशि को बिहार को शीघ्र दिलाया जाए।

वर्ष 2022 से "सागर परिक्रमा" कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत समुद्र में मछलियों को पकड़ने के लिए मछुआरों को इंटरनेशनल बाउंड्री और समुद्री क्लाइमेट की जानकारी दी जाती है। वर्ष 2024 के डाटा के अनुसार, 266 भारतीय मछुआरे दूसरों देश की जेलों में बंद हैं एवं उनके लगभग 2000 से अधिक सामानों को जब्त किया गया है। हमें यह भी संज्ञान में लेना चाहिए ।

महोदय, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर अपनी बात रखते हुए, आवारा कुत्तों एवं अन्य जानवरों के बारे में भी बोलना चाहूंगा। 'द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट-1960', जो जानवरों की सुरक्षा के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में रिट पेटिशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि, "Stray dogs can be managed by controlling their population through animal vasectomy?. इसलिए, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आवारा कुत्तों एवं अन्य जानवरों, जो कि फसल से लेकर कई तरह की क्षति पहुंचाते हैं, उनका भी समाधान निकालना चाहिए।

महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एवं भारत सरकार के सहयोग से एकमात्र वैटिनरी कॉलेज पटना में है।

मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है, इसलिए, वहां एक वैटिनरी कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि किसानों को उसका लाभ मिले और मवेशियों को जरूरत पड़ने पर इलाज हो सके।

महोदय, अंत में मैं इन अनुदानों की मांग करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

SHRI NILESH DNYANDEV LANKE (AHMEDNAGAR): Hon. Chairman Sir, first of all, I would like to thank the voters and supporters of my Lok Sabha constituency, Ahmednagar. They put their faith in me and that is why today I am here in this House. I would also like to congratulate Smt. Nirmala Sitharaman for presenting the Union Budget for 7th time.

Sir, during my Election Campaign, I met many people and knew about their pains and problems. I thank you for allowing to speak and this opportunity is provided by Parliamentary leader Smt. Supriya Sule of my Party NCP.

India is known as an agriculture dominated country. In addition, to farming activities, we also rear cattles for milk. Farmers are committing suicide at large numbers in India and we have to stop it. But, how can we stop it? To increase his income, he can start business of dairying. But the fair price should be given to dairy products.

Mahanand Dairy, which was started by farmers milk federation is being handed over to NDDB. It was started through farmers? co-operative movement in Maharashtra and this unfortunate decision has been taken by the Government which shows its mentality and apathy towards farmers. This dairy is handed over to other State and our farmers have lost the ownership of Mahanand Milk Federation.

Some suggestions have been given in the budget for dairy industry but sufficient assistance and aid should be provided to the farmers and greater budget allocation should also be made for infrastructure development. Farmers are facing the challenges like lack of infrastructure and cattle diseases.

Sir, I hail from a rural area where women work very hard for farming and cattle rearing. But the farmers get very low rates for milk and this is very disappointing.

Hence, I demand that the rates should be fixed on the basis of production cost. The production cost for cow or buffalo milk is around Rs. 40-55 per litre. So, a MSP should be fixed for milk too.

Sir, the selling price for milk is around Rs. 30-35 a litre. Rs. 5 per litre is given by Government as an aid, so it is around Rs. 30 per litre. Nowadays, farming is also incurring losses and it is profitable.

Sir, it is my earnest request to you to declare MSP for milk immediately and it should be done through the Commission for Agricultural Cost and Prices (CACP). This is very much needed to stop the loot of farmers by the traders. There should be a cap on the pricing of fodder because it has been raised exponentially during last 4-5 years. Pricing and quality of the animal feed should be checked properly.

I demand that a milk processing centre should be set up in each and every tehsil of our country. My Ahmednagar district is the largest district which plays a major role in milk production. The Union Government should open milk processing units in all the tehsils of my Ahmednagar district as a pilot project.

It would help to develop sustainable market for production of different dairy products. Through this, farmers would also get regular income and I am pretty sure about it. You can further replicate it throughout the country through a mechanism. The dairy products like cheese, milk powder, butter etc. can be produced which would help in increasing shelf life of milk. Farmers would get more income through value addition.

As you know, milk is a perishable food and it is not possible for everybody to set up a cold storage. An assistance should be given to cold storage centres to install bulk milk coolers to stop the wastage of milk.

We are one of the largest milk producers in the world but our export is very less. We should encourage milk production and try to export it which would ultimately help the farmers.

Debt for dairying is also an important issue and Government should have focused on it. The capital expenditure for this head has been reduced from Rs. 157.31 crore to Rs. 151 crore in revised estimate. NABARD provides loan for dairy business and that needs to be increased.

National Gokul Mission was a very good scheme run by Central Government. I am clueless whether it is there or not. You can start a similar kind of scheme. No special scheme for dairying is being run by Central Government. You are focusing only on poultry, goats, sheeps and piggery under National Livestock Mission. You should help for cattle rearing too. Under, the National Animal Disease Control Programme (NADCP) for the year 2023-24, only Rs. 2349 crore were allocated but only Rs. 1500 crore have been spent as per RE.

As per the National Commission on Agriculture 1996 guidelines, one veterinary doctor should be available for every 5000 cattles, but it is not being followed. Around 1,60,000 veterinary doctors are needed, but there are only 65000 veterinary doctors available.

Milk adulteration is a very serious issue and Government should take this menace seriously. Small kids and children fall prey to the diseases like cancer due to it. A strict law should be enforced to eradicate this crime. If you really want to save desi cows, special aid should be provided to farmers to look after this livestock.

Thank you.

श्री अरविंद गणपत सावंत (मुम्बई दक्षिण) : सभापति जी, मैं इस चर्चा में सिर्फ मछुआरों के संबंध में बात करूंगा और अन्य विषयों पर मेरे सहयोगी सदस्य बात करेंगे। महाराष्ट्र से 720 किलोमीटर से ज्यादा तट रेखा है। बजट में सरकार ने मत्स्य पालन विभाग के लिए संशोधित अनुमान वर्ष 2024 के बजट अनुमान में 2248 करोड़ रुपये से घटाकर 1701 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके लिए मैं दो-तीन मूलभूत प्रश्न उठाऊंगा। मुम्बई शहर में बंदरगाह एरियाज हैं। कपड़ बाजार, भाऊचा धक्का, कुलाबा आदि जगहें हैं, जहां सारे मछुआरे आते हैं। जब चक्रवात या प्राकृतिक आपदा आती है, तब उन्हें मछली पकड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे समय में उन्हें अपनी बोट सुरक्षित रखनी होती है, जिसके लिए उन्होंने एक कम्पाउंड वॉल बनाई हुई है जोकि पथरीली है। अब वहां बहुत गाद जमा हो गया है, जिसकी वजह से वॉल की ऊंचाई कम हो गई है। जब चक्रवात या तूफान आता है तो समुद्र का पानी वॉल को पार करके बोट्स को नुकसान पहुंचाता है। मेरी मांग है कि वहां एक टेट्रापोड की कम्पाउंड वॉल बनाई जाए, ताकि हमारे वहां के मछुआरों को सहायता मिले।

सभापति जी, यह समस्या भी बहुत बड़ी है कि एक लाइसेंस के नाम पर दूसरे जहाज भी फिशिंग एरिया में चले जाते हैं। सरकार ने केवल 164 लोगों को लाइसेंस दिए हैं लेकिन 1500 से 2000 जहाज उसमें घुस जाते हैं। उनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। उन्हें 12 नॉटीकल माइल्स के बाहर जाकर मछली पकड़नी है, लेकिन वे अंदर के एरिया से मछली पकड़ते हैं। 1500 से 2000 तक जहाज ऐसे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इनसे एक और परेशानी यह भी है कि वे एलईडी लाइट के माध्यम से मछली पकड़ते हैं, जबकि लाइट लगाकर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। इस पर न केंद्र सरकार कार्रवाई करती है और न राज्य सरकार कार्रवाई करती है। इस वजह से छोटे मछुआरे परेशान हैं। मेरी मांग है कि बजट में इनके लिए दी गई राशि को कम करने की जगह बढ़ाया जाए। खास कर मछुआरों के सुरक्षा क्षेत्र में जो दीवार बनाई हुई है, वह टेट्रापोड की बनाई जाए और वहां जमा गाद है, उसे निकालकर गहराई बढ़ाई जाए। धन्यवाद।

SHRI SANDIPANRAO ASARAM BHUMARE (AURANGABAD): Hon?ble Chairman, thank you very much for allowing me to speak on Demands for Grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The Union Budget 2024-25 was also presented a short time ago and we witnessed that the Government has focused mainly on farmers overall development in the budget. So, I would like to congratulate and thank our Hon. Prime Minister Narendra Modi and Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman on behalf of my Party Shiv Sena.

Sir, there are 8 districts in Marathwada region and most of them are draught-affected. The number of farmer?s suicide is very high in this area. To earn extra income, dairying would be very beneficial for farmers. But, no infrastructure for this business is available there.

Sir, the farmers in this area are facing the problem of acute shortage of fodder. They are compelled to purchase it at higher rates. So, the production cost of milk increases. To arrest the price-hike, the fodder, seeds insurance of livestock and cattle feed should be made available at cheaper rates.

Not a single cattle feed factory is there in 8 districts of Marathwada region even after ample availability of maize, jaggery, oil seeds etc. So, there is an urgent need to set up fodder factories in my Marathwada region. If it is manufactured at local level, the production cost would be minimum. At least a 50 MT per day fodder production capacity should be developed through the Government or cooperative society venture and the Government should take an initiative at this direction.

Sir, a special provision should be made for the farmers of Marathwada to procure lactating dairy cattle. I would like to request Hon. Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chauhan to provide 100% funding for procurement of lactating dairy cattle to promote dairy industry.

Sir, no frozen semen and bull research centre is available in my Marathwada. There is a surplus supply of milk in Marathwada and it causes price drop and the farmers have to incur losses, as no milk powder making facility is available there. So, Aurangabad District Milk Society should be allowed to set up a 20 ton milk powder making facility with 100% financial assistance.

Sir, milk production and processing cost include the costs of electricity and transportation. So, the milk collection centre should be equipped with processing facilities so that the production cost should be minimized and they can provide some kind of help to farmers.

MSP should be fixed for milk too. The cow milk should be purchased at the rate of Rs. 50 per litre. To increase the production of pure milk and also to provide employment through conservation of lactating dairy cattle, Dairy Research Institute should be opened at Sambhaji Nagar.

Sir, Gokul Mission Scheme was launched only for rich farmers who owns at least 250 cattle. I would like to request Union Government to change the criterion for this Gokul Mission Scheme and the benefits should be extended to the farmers owning even 25 cattle. It would be in interest of small and marginalized farmers.

Milk adulteration is also a big issue in Marathwada. An anti-adulteration drive for milk should be launched.

I am thankful for giving me this opportunity to speak.

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): India with only 2.29 percent of land area of the world is maintaining nearly 10.70 percent livestock with only 5 percent of its cultivable land under fodder production. Inadequate Funding at about 12% of the total public expenditure on agriculture and allied sectors, which is disproportionately lesser than its contribution to agricultural GDP. The Indian livestock and livestock product market are mostly underdeveloped, irregular and uncertain. Nearly 60 percent of milk is sold by the unorganized sector. The Indian livestock and livestock product market are mostly underdeveloped, irregular and uncertain. Nearly 60 percent of milk is sold by the unorganized sector.

Transfer of funds to States/UTs under Centrally Sponsored Schemes namely, the demand for grants in Dairy Development was Rs. 219 crores 2023-24 to zero in 2024-25. Similarly, the allocation of Rashtriya Gokul Mission which is the mission works towards the development and conservation of indigenous bovine breeds in order to enhance the milk production and productivity of bovines has been reduced from Rs. 599.84 crores in 2023-24 to nil in 2024-25. The total-Centrally Sponsored Schemes allocation cut down from Rs. 1014.16 crores to Rs. 369 crores.

The budget allocation for the National Livestock Mission which aims for the sustainable development of the livestock sector, focusing on improving the availability of feed and fodder. extension services, flow of credit, and organization of livestock farmers and rearers is slashed from Rs. 410 crores in 2023-224 to Rs. 324 crores in 2024-25.

The contribution of livestock sector of Bihar is about 5 percent to total state GDP or GSDP. Inadequate fodder supply is one of the main constraints of livestock production in Bihar. 42.6% of people below the poverty line in Bihar depend on livestock, especially goats, for theira livelihood. According to the 2021 Multidimensional Poverty Index (MPI), Kishanganj is the poorest district in Bihar, with 64.75% of its population living in poverty. With the rising animal diseases, there's a need for a Veterinary Institute in Bahadurganj, Kishanganj district, Bihar.

The inadequate coverage of vaccination results in economic losses due to various animal diseases. Average annual economic losses due to Haemorrhagic Septicaemia (HS), Foot and Mouth Disease (FMD), Brucellosis, Peste des Petits Ruminants (PPR), and Classical Swine Fever were around Rs. 429 crores in 2016.

The budgetary allocation to Animal Health Research has reduced drastically even in the presence of the Animal Health Institute, Small Livestock Institute, Breed Improvement Institute and Centre of Excellence for Animal Husbandry.

Regulatory Bodies namely, the Animal Welfare Board have also been sidelined.

There is no MSP support for animal husbandry products and they lack marketing like crop based commodities.

Currently, only 6% of the animal heads (excluding poultry) are provided insurance cover. No mention of reducing greenhouse gasses through mitigation and adaptation strategies found in the budget. Cattle in India account for approximately 33% of the country's total greenhouse gas emissions.

Institute for fisheries at Baisi in Purnea, may be considered.

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Problems of milk subsidy to farmers

Milk production is the main occupation of many farmers in rural areas. The government has implemented various subsidy schemes to promote milk production and sale. However, farmers are facing some difficulties in benefiting from these schemes. Following are those problems and their solutions.

- **DIFFICULTIES IN REGISTRATION:**

Difficulty of documents: Farmers find it difficult complete necessary documents like an Aadhaar card, bank account details, and milk union certificate.

Incorrect Information: Providing incomplete or incorrect information during registration will lead to difficulties in getting benefits.

- **Bank Account Related Issues:**

Bank Account Link: Due to the incomplete process of linking Aadhaar card and bank accounts, many farmers do not get subsidy amounts credited to their accounts.

Updating Bank Account: If the farmers do not update the bank account information properly, the payment process is blocked.

- **Problems of milk union:**

Registration of Union: Sometimes due to the wrong registration of milk unions farmers face difficulties in getting subsidies.

Honesty: Some unions do not record the information of the farmers honestly, so there is no benefit. The milk subsidy given by the government is not deposited in the bank account of the farmers, they deposit it in the milk union account. The milk union does not give the subsidy amount to the farmers.

- **Lack of awareness about the scheme:**

Many farmers are not fully aware of this scheme. As a result, they cannot be registered properly and do not get benefits.

- **Technical Issues:**

Problems in Online Registration: Sometimes the website or portal faces technical issues which prevent the registration process from completing.

Server Downtime: Downtime of websites or portals during registration.

- **Indifference of Officers:**

Sometimes the local authorities do not cooperate in the registration process of the farmers, thus causing difficulties in the registration process.

#Solutions to solve the problem (Milk Subsidy to Farmers):

Providing complete information: Farmers should provide correct and complete information while registering.

Preparation of documents: Necessary documents like Aadhaar card, bank account details, and milk union certificate should prepared.

Raising awareness: The government and concerned authorities should create awareness among the farmers about this scheme and its benefits.

Technical support: For technical issues contact helpline numbers or local authorities.

Updating Bank Account: Bank account information should be kept up to date and necessary linking should be done.

Honesty of Milk Union: Milk unions should record the information of farmers honestly and the government should check it.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): As per the Economic Survey 2022-23, the Animal Husbandry and Dairying sectors are increasingly being seen as emerging sectors due to performance relative to the Crop sector. But the Budget for Demands for Grants for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has fallen short on multiple grounds.

One of the prime budgetary issues in the Animal Husbandry sector has been the consistent shortfall in the BE allocation as compared to the allocations proposed by the department. And the systematic reduction in RE allocations compared to BE allocations. This has a cascading effect on the physical targets set for the schemes.

In her Budget speech, the Honourable Finance Minister famously announced that this year's budget would focus on the four "castes", one of which is farmers. Fishermen fall under the definition of a farmer. However, the Government has displayed sheer indifference when it comes to securing the lives of fishermen in our country, specifically those from my state, Tamil Nadu. Every other week, there is a new report on fishermen either being arrested or dying at the hands of Sri Lankan authorities. On 1st August, 59-year-old K Malaisamy died after a collision with a Sri Lankan Navy vessel. Another fisherman is missing, and two have been detained in Sri Lanka. Over 250 such cases have already been recorded this year. Many fishermen have died mysteriously while under custody. The MEA, in the Lok Sabha in 2022, said that a total of 626 fishermen from Tamil Nadu were arrested in Sri Lanka, and 99 boats were seized, between 2019 and 2022. Often, even when fishermen are released, their boats have not been returned. This has led to a significant impact on fishermen's livelihoods. The fishermen from Rameshwaram have now announced an indefinite strike calling for the release of all arrested fishermen in Sri Lanka. The marginal increase in the Budget allocations is merely tokenistic if the Union Government does not pay heed to our fishermen's cries. The Ministry also needs to look into the under-regulation of aquaculture. Disease outbreaks as a result have not been given enough attention. India's first tilapia parvovirus (TiPV) case was reported in the Ranipet district of Tamil Nadu last year. In an effort to

tackle these outbreaks, antimicrobials are used excessively. As a result, there is a serious risk of antimicrobial resistance (AMR) in fish-consumers. The Government must enact the Aquatic Animal Disease and Health Management Bill, which has been pending for five years. This will act as a benchmark for how State Governments should regulate fisheries in their respective jurisdictions.

Retailers are hiking milk prices, which will lead to an increase in inflation. This is due to the effect of heat on dairy production. The Union Government must look into the impact of heat stress on dairy-producing animals. Milk production had decreased by almost 15% in 2022 due to extreme heat. Summer month also see a surge in demand for milk products. So, it is essential to ensure that heat-stress induced inflation does not burn a hole in consumers' pockets.

The mortality rate amongst poultry birds has also surged. Farmers have had to use extra measures like installing coolers to curb poultry deaths. The Union Government must account for such additional expenses and accommodate for them through adequate infrastructure and allocations. Between July 2022 and July 2023, there were over 2 lakh cattle deaths due to Lumpy Skin Disease. But the Department provided a compensation scheme for farmers affected by these losses.

We must center the interests of our farmers, fishermen, and consumers in our Budgets. A Budget that is responsive to evolving threats like climate change is the need of the hour. Thank You

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): India is ranked first in milk production contributing 24.64% of global milk production. This sector is the backbone of our rural economy, providing livelihoods to millions of farmers and contributing significantly to our nation's GDP. Dairy is the single largest agricultural commodity contributing 5% of the national economy and employing more than eight crore farmers directly. As we review the Union Budget for 2024-25, it is imperative to address these issues comprehensively and allocate resources effectively to ensure sustainable growth and prosperity for our farmers. A notable aspect of the Indian dairy industry is the extensive involvement of women, with 35% of them participating in dairy cooperatives. There are 48,000 women dairy cooperative societies operating at the village level across the country, promoting inclusive growth and empowering women.

Animal husbandry and dairy farming in India face several persistent challenges. Low productivity of indigenous breeds: One of the foremost issues is the low productivity of indigenous breeds. While these breeds are well-suited to local conditions, their milk yield is significantly lower compared to crossbreeds. The Rashtriya Gokul Mission has made strides in improving this through genomic selection and advanced breeding techniques, but we need to scale these efforts substantially.

Economic Impact on Poultry Farmers: The outbreak of avian influenza (H5N1) has led to substantial economic losses for poultry farmers in Maharashtra. The death of infected birds and the culling of poultry within affected zones have severely impacted livelihoods. This includes financial strain due to the cost of culling operations and the loss of income from poultry products. The subsidy provided for the same are not sufficient to incur the loss beared.

Biosecurity and Surveillance: There have been gaps in biosecurity measures and surveillance, which are crucial for early detection and containment of the disease. Enhanced training for veterinary workers and strengthening of diagnostic laboratories are necessary steps to improve the response to such outbreaks, for which the government does conduct training but the capacity for the same shall be increased.

Failure in Timely Intervention: The delayed response in some regions has exacerbated the situation. There have been instances where initial symptoms were not promptly addressed, leading to a wider spread of the disease before containment measures could be effectively implemented.

Availability of Feed and Fodder: Feed and fodder availability remains a significant bottleneck. The shortage of quality feed and grazing land directly impacts livestock health and productivity. It is imperative that we develop a robust strategy to enhance the production and availability of nutritious feed across the country.

It has been observed that time again white onion farmers are given priority over red onion farmers, which on ground means preference to farmers in certain other states over Maharashtra. Recently in Maharashtra, we saw senior ministers of the government issuing false and misleading statements regarding an old relaxation being portrayed as a new policy move for the farmers, days before the elections. These events show the influence of the political agenda of the ruling government on the onion export policy, which is worrisome and problematic. The intent should be to protect our onion farmers throughout and not only during elections.

Farmers always suffer due to the policy of banning onion exports, but this time, even the ruling party has been affected by the situation. Maharashtra is the largest onion-producing state in the country, accounting for 42.3% of India's total onion production. In comparison, Madhya Pradesh produces 15%, Karnataka 8%, and Gujarat 8% of the total onion production. The combined production of these three states is equivalent to Maharashtra's output alone. Despite Gujarat producing only eight percent of the country's total onion production, it has a significantly more developed onion processing industry compared to Maharashtra. The Directorate of Onion and Garlic Research website lists various processing industries that can be established using onions, including onion paste, onion pickles, and onion oil, among other products including renewable energy. The government should conduct an in- depth study on this matter and ensure development and expansion of such processing units in Maharashtra.

Thalinomics Analysis indicates a significant rise in the prices of thalis (plates of food) in Maharashtra for the year 2023-24. The Economic Survey highlighted that food prices, including essential items like vegetables and pulses, have seen a notable increase, impacting the affordability of a standard thali for the common person. This trend reflects broader inflationary pressures within the state's food sector, influencing overall consumer expenses.

Livestock diseases such as Foot and Mouth Disease (FMD) and Brucellosis continue to plague our dairy sector. Despite extensive vaccination programs, including the vaccination of millions of animals, these diseases persist, causing economic losses and reducing productivity. We need to strengthen our veterinary infrastructure and ensure timely and effective disease control measures. Disease management is another pressing concern.

Infrastructure inadequacies, particularly in milk collection, storage, and transportation, further exacerbate the sector's challenges. While there have been Improvements with the installation of Bulk Milk Coolers and modern testing equipment, many regions still lack adequate infrastructure. This leads to post- harvest losses and affects the quality of milk products, ultimately impacting farmers' incomes.

Milk adulteration is a critical issue that undermines consumer trust and the dairy industry's reputation. Efforts to install sophisticated testing equipment are ongoing, but ensuring widespread and effective implementation remains a challenge. We must prioritize food safety and quality control to protect consumers and support our dairy farmers. Along with mother's milk, cow's milk is also considered nectar for health. In the Rigveda it is said 'गोषु प्रियम् अमृतं रक्षमाणा'so I urge the government to have stringent measures for quality control to save this nectar.

Market access and fair pricing are essential for the sector's growth. Farmers often rely on middlemen, which affects their earnings. Strengthening dairy cooperatives and Farmer Producer Organizations (FPOs) can provide better market access and ensure that farmers receive fair compensation for their produce. The government's support for these organizations must be intensified to make a real difference.

Technological adoption in the sector is still in its early stages. Initiatives like the e-GOPALA app for livestock management and genomic selection are promising, but broader dissemination and effective use of these technologies are necessary to boost productivity and farmer incomes.

The impacts of climate change pose a growing threat to livestock health and productivity. Increased heat stress and changing disease patterns necessitate adaptive strategies and resilience-building measures within the sector.

Strengthening dairy cooperatives and farmer producer organizations (FPOs) is crucial for improving procurement and processing infrastructure. While there have been initiatives to support these organizations, more needs to be done to ensure their sustainability and effectiveness.

The Kisan Credit Card (KCC) facility has been extended to livestock and dairy farmers since 2019, providing them with easier and increased access to institutional credit. Many farmers face difficulties in accessing banking services. Banks often lack dedicated counters for handling KCC applications, resulting in delays and inefficiencies. Moreover, the process of activating inactive KCC accounts or increasing credit limits can be slow and cumbersome.

I also urge the Government to look into several important requests regarding the following issues and allocate sufficient resources to address these issues effectively.

- Enhancing feed and fodder availability through dedicated programs and subsidies.
- Strengthening disease control and veterinary services with increased funding and infrastructure development.
- Improving milk collection, storage, and transportation infrastructure to reduce post- harvest losses and ensure quality.
- Promoting technological adoption and innovation to increase productivity and efficiency.
- Ensuring better market access and fair pricing mechanisms for farmers through support for dairy cooperatives and FPOs.
- Developing adaptive strategies to mitigate the impacts of climate change on livestock.

SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA): In the 2024-25 budget, the demand for the Department of Animal Husbandry and dairying has gone up only by 4 percent from 2023-24 budget estimates. Farmers, including those who do animal husbandry and cattle rearing require specific support from the central government. The major problems that such farmers face across the state of Uttar Pradesh and in the constituency are: low productivity of the milk producing animals, high cost of fodder, and diseases that affect the animals.

Diseases are a very common problem, in 2022 a severe outbreak of the Lumpy Skin Disease affected hundreds of farmers in Sahranpur and Shamli districts and led to the death of hundreds of cows. The Livestock Health and Disease control scheme that deals with controlling and monitoring outbreak of diseases, improving veterinary infrastructure and introducing mobile veterinary units. The scheme has seen a marginal increase of 100 crores in 2024-25 from 2023 24. In Uttar Pradesh, as of August 2023, only 520 mobile veterinary units have been commissioned. Such units are of utmost importance for farmers who require immediate veterinary services for their livestock.

The National Livestock Mission has seen a fall in allocation from 410 crores to 324 crores this year. This is a crucial scheme as it plays a role in employment generation through entrepreneurship in poultry, sheep, goat and piggery and includes feed and fodder development, and livestock insurance as well. In 2022-23, 96686 animals were insured in Uttar Pradesh and this fell to 20917 in 2023-24. Therefore, there is a need to increase the cover of livestock insurance. High feed and fodder rates are a longtime concern of farmers and

the fall in allocation will hurt their support. For dairy development, the National Programme for Dairy Development has been allocated 370 crores and has been converted as a central sector scheme. Component B of the Scheme is "dairying through cooperatives" to help increase farmers' sale of milk and dairy products on the organised market, upgrade dairy processing facilities, marketing etc. As on February 2024, of the total outlay of 81.84 crores in Uttar Pradesh, only 45.08 crore has been released in the past three years and only 0.49 crore in 2023-24. These funds need to be released and utilised to ensure maximum benefit for farmers.

Component A of scheme focuses on creating or improving pre-existing infrastructure for quality milk testing equipment, primary chilling facilities ete for State Cooperative Dairy Federations District Cooperative Milk Producers' Union/SHGs/Milk Producer Companies/Farmer Producer Organizations. Under this scheme so far, only 26,400 farmers in Uttar Pradesh have been approved for training. This number should be increased.

The Rashtriya Gokul Mission has been allocated 700 crores in 2024-25. The scheme aims to make milk production more profitable for farmers, especially in rural areas. It also aims to conserve indigenous breeds of bovines and genetic upgradation of them. In 2023-24, 869.54 crore was allocated but only 452.00 crore was spent. There must also be a proper evaluation whether the Nationwide Artificial Insemination programme under this scheme in the districts of Shamli and Kairana. They have been identified as districts with less than 50% of Artificial Insemination Coverage. Shamli has a coverage of only 34% and Saharanpur is at 38%.

Under the Department of Fisheries, the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) has been allocated 2352.00 crores. Under the scheme, entral assistance by entities of the Central Government is up to 60% for Women and SC/ST categories. It should be ensured that these categories are made aware of the benefits available under the scheme and funds are released timely.

Main demands:

- Implement schemes such as the Livestock Health and Disease Control Scheme across the state and in Shamli and Saharanpur Districts to increase vaccination coverage of animals and reduce disease burden. This will be crucial to ensure increase in livestock productivity.
- Under the Livestock Health and Disease Control Scheme improve the infrastructure of veterinary hospitals in Shamli and Saharanpur districts and increase the number of Mobile Veterinary Units.
- Funds for Uttar Pradesh under National Programme for Dairy Development must be released at the earliest and the number of farmers who receive training under the scheme should also be increased.
- Implement National Livestock Mission and increase coverage of livestock insurance to protect them from the losses that occur due to unanticipated death of livestock.
- Increase coverage of Artificial Insemination in districts of Shamli and Saharanpur free of cost at the farmers doorstep.
- Improve access of PMMSY scheme benefits across the constituency and ensure that vulnerable populations of women, SC/ST categories receive adequate allocation of funds. There must also be promotion of inland fishing such as construction of new ponds. Fisherfolk must also be provided assistance in marketing to ensure that their produce can be sold profitably.

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The fisheries, animal husbandry and dairying are the oldest profession of mankind. Starting from the Neolithic period 9000

BC, human beings have cohabitated with the domestic animals like, cows, goats, buffaloes, fowls, ducks. The subsistence of human race depended more on fisheries, animal husbandry and dairying. Even today, the majority of the world population depends on the outcome of three revolutions, Green Revolution, Blue Revolution and White Revolution. To cater to the food and economic needs of 140 crore Indians, the development of fisheries, animal husbandry and dairying is very important. I feel the Government of India has taken these sectors as granted and not focused on the core issues and problems faced by the people in these sectors, especially the problems and hazards created by the modern human on animal population are sickening. The Government of India once again behaves like an ungrateful and thankless Government. The fishermen, cattle-rearing communities which served and thrived and shaped the human civilization for several centuries have been treated as the third-class citizens in this Budget.

The entire 1,076-km coastline of Tamil Nadu affected severely because of either natural calamity like cyclones, or, by the atrocities committed by the Lankan Navy. The State Governments perceive coastal security as a subset of national security. The creation of a Central Marine Police Force (CMPF) would relieve the police forces of an additional responsibility for coastal security to compensate the poor policeman-to-population ratio. I would like the Government to create the Central Marine Police Force by recruiting the former Navy personnel and members of the fishing community of each State as marine police to overcome the language barriers and to enhance familiarity with coastal waters.

The coastal corridor in Tamil Nadu consists of 13 districts with 15 major ports and harbours, sandy beaches, lakes and river estuaries. Tamil Nadu has a fishermen population of two million, and the coast consists of three major fishing harbours, three medium fishing harbours and 363 fish landing centres. Unfortunately, there have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel firing on Indian fishermen fishing in the Palk Strait, where India and Sri Lanka are only separated by 12 nautical miles. The Government of Tamil Nadu protests against Sri Lankan Navy for its alleged involvement in the attacks on Indian fishermen. But the incidents continue to happen, and over 600 fishermen have been killed and thousands of their fishing vessels seized and damaged in the last 30 years.

Katchatheevu was ceded to Sri Lanka in violation under the 1974 and 1976 agreements without the approval of the two Houses of Parliament and hence, the ceding is unlawful and not valid. Puratchi Thalaivi Amma wanted the retrieval of Katchatheevu as it will be the only solution to solve the long-standing issues of Indian fishermen.

The remote-controlled boats fitted with high-definition thermal cameras, operated through satellite-based technology, are most effective for coastal security especially during pitch dark nights over the seas. The Central Marine Fisheries Research Institute (CMFRI) has developed a database of all the fish-landing centres to ensure the security of fishermen during cyclones. I urge the Government to provide adequate funds for the purchase of the state-of-the-art equipment to strengthen the coastal security.

Fishing has to be recognized on par with agriculture. The fisher communities suffer very much due to natural calamities like, cyclone, rough sea, heavy rains, heavy floods, hurricanes and tsunami and they need waiver off of their loans by the Government. Fishermen should be provided with loans to buy boats, nets, and other gears and equipment. An exclusive bank in the name of the National Bank for Fisheries and Fisher Development shall be established. Fishermen shall be provided with fuel at cost price, without any Central

and State taxes and cess. Letter of Permit (LOP) shall be provided to the traditional fishermen and 60 per cent subsidy facility from the banks.

Fishermen community should be accorded with the Schedule Tribe status, and there is a need to provide two per cent exclusive reservation for fishermen community in education and job opportunities. A Comprehensive special package for diversification of fisheries is the need of the hour. Diversification of bottom trawlers into deep sea tuna long liners would reduce the pressure of bottom-trawling boats in the Palk Bay and will cost Rs.1,975 crores. The Mid Sea Fish Processing Park project, require Rs.180 crores.

The present level of assistance of Rs. 3 crores per year for motorization of nearly 1,000 traditional crafts is very meagre since there are over 40,000 non- motorized traditional crafts in Tamil Nadu. I urge the Government to sanction Rs.12 crores per year to ensure all traditional craft be motorized within five years. The Government has sanctioned the construction of fishing harbour at Poompuhar in Nagapattinam District. There is a need to provide funds for the construction of fishing bays at Nagore, Senthur, Vellapallam, Vizhunthavadi, Siruthalaikkadu, Vedaranyam, Muthupettai, Akkarappettai, kodiyakkarai, Thondiyankadu, Pushpavanam and Nambiyar Nagar under the Centrally-sponsored Schemes, in my Nagappatinam Parliamentary Constituency. The Tamil Nadu Fisheries University at Nagapattinam needs generous financial and logistic support from the Government of India.

Dairying is a major contributing factor to the livelihood of farmers in a number of ways including income from milk and milk products insurance against draught, emergency cash requirements, household nutrition etc. Dairying plays a central role in the natural resource-based livelihood for the vast majority of the population, which is mostly confined to rural areas. Dairy sector is a thriving enterprise in the Indian agriculture showing colossal growth responsible for placing the country at the top two position worldwide in milk production, with a total milk production of 230.58 million tonnes in 2022-23. In India, the per capita availability of milk is 459 grams per day. Milk production in Tamil Nadu is 10.32 million tonnes during 2022-23, contributing a share of 4.47 per cent of total milk production in the country. The per capita availability of milk in Tamil Nadu is 370 grams per day.

Muthamilarignar Dr. Kalaignar has established the Tamil Nadu Dairy Development Corporation, which was formed in the year 1972 under the Companies Act, to manage all the commercial activities of the department. The Tamil Nadu Government implemented a three-tier dairy co-operative system in the year 1981 known as "Anand Pattern". In Tier-1, the Primary Milk Producers' Co-operative Societies (MPCS) are formed at the village level, which is the base of the three-tier system. In Tier-2, the District Co-operative Milk Producers' Unions (DCMPU) are the middle-level co-operative societies, wherein the Primary Milk Producers' Co-operatives in their jurisdiction are their members. In the Tier-3, the Tamil Nadu Co-operative Milk Producers' Federation (TCMPF) is the apex level society in which all the DCMPUs in the State are members. At present, there are 9,189 Primary Milk Producers Societies functioning at the village level in Tamil Nadu.

The 9,189 Primary Milk Producers' Co-operative Societies are procuring milk from 3.91 lakh milk producers, and the average milk procurement by the unions in the financial year 2023-2024 is 28.30 LLPD, apart from the local sale by the MPCS catering village public needs. The growth in milk procurement will be sustained and efforts will continue to achieve 40 LLPD.

Milk producers are being trained and enlightened in the areas of clean milk production, ration balancing techniques, fodder cultivation, dairy animal management and breeding, decreasing the cost of production, and effective utilization of unconventional feeds etc. The MPCS staffs are trained on MPCS administration, clean milk procurement, quality testing, artificial insemination activities etc. The regional training centres at Salem, Madurai and Tirunelveli, DCMPUs are accredited by the Government of India's Central Monitoring Unit. The training centres at Villupuram, Vellore and Madhavaram were also strengthened by obtaining a sum of Rs. 200 lakh as 100 per cent grant assistance under the Rastriya Gokul Mission from the Union Government. By utilizing the training centre facilities 75,677 milk producers and 6,521 staffs were given training on dairy animal management, clean milk production, calf rearing and infertility management. There are 34 chilling plants in Tamil Nadu with a total chilling capacity of 43,34,000 Litres.

The Aavin State Central Laboratory, Madhavaram was established under the NPDD Scheme and inaugurated by the Honourable Chief Minister of Tamil Nadu on 16.08.2022. The laboratory is equipped with the hi-tech equipment for detecting the pesticide residues, drug residues, heavy metals and aflatoxin content. The establishment of the State Central Laboratory at Madhavaram reduced the cost incurred for testing of milk and milk products in the external laboratory and also increases the quality of milk and milk products by increasing the number of samples. The laboratory also caters to the cattle feed and mineral mixture plants of the TCMPF Ltd., to check the quality of raw materials and finished products to ensure the supply of quality products to the Farmers. The Aavin Skill Development Centre, Madhavaram is functioning from 14.11.2022 with the main objective of enhancing the skills of employees working in village level Primary Milk Co-operative Societies, District Unions and Federation. As on date, 36 nos. of multidisciplinary trainings were conducted at Skill Development Centre, Madhavaram, which includes basic and refresher training to the dairying and quality assurance staffs, technical staffs, administrative and accounting staffs of Federation and DCMPUs Artificial Insemination Training was conducted to the MPCS Staffs of various District Unions.

Due to the continuous efforts, the sales volume, of Aavin milk has been on an increasing trend. In the last two years, the sale volume has increased by 3.45 per cent from 29.20 LLPD to 30.25 LLPD. High quality Aavin Milk Products are produced at Chennai, and District Co-operative Milk Producers Unions to cater to the needs of the consumers throughout the State. The sales of Aavin's dairy products are around Rs. 523.48 crore during the financial year 2023-24.

The diversified product portfolio of Aavin is enhanced with the introduction of new products on a continuous basis to meet out the changing preferences of the consumers and to sustain market share in a competitive dairy sector. During festive seasons, Aavin prepares and sells special sweet varieties for the benefit of the consumers at an affordable price.

Now, I come to online milk cards. In order to enable purchase of milk cards from the comfort of one's home, it has been facilitated to purchase and renew milk card through online mode. Approximately, 58,650 online milk cards have been issued from Jan'24 to Mar24. This initiative has garnered positive reception from the public and has brought new customers under the ambit of Aavin. Aavin, that is striving to enhance its market presence, is leveraging digital and online platforms to increase its market share.

Aavin further sells SMP/ghee/butter through the National Cooperative Dairy Federation of India-NCDFI's e-portal, which is a national platform for marketing of dairy commodities and was adjudged as the

second highest grossing business partner during the 2023-24

The Quality Assurance Laboratories of Tamil Nadu Co-operative Milk Producers' Federation Limited is well equipped with the state-of-the-art laboratory equipment to analyse the quality of Milk State-wide. Milk is tested at MPCS /BMC/ CC/ District union Dairy/ Metro Dairy laboratory for chemical and microbiological contents. The TCMPF Ltd. has been certified by ISO 22000, Food Safety Management system (FSMS) for the Federation Dairies and DCMPUs, to ensure the Food Safety of the Milk & Milk Products.

Now, I come to National Programme for Dairy Development (NPDD). The aim of the National Programme for Dairy Development is to enhance the milk chilling infrastructure, procure quality milk and sell quality milk products and also increase the share of co-operative sectors in the clean milk procurement, processing, value addition and marketing. Under this scheme for the year 2022-24, Rs. 9,080.11 lakh (GoI Share of Rs.6,026.88 lakh) has been sanctioned and below mentioned works are in progress. Under the NPDD 2022-24, the State Central Laboratory has been established on 16.08.2022 at Madhavaram. The lab is equipped with high-end precision equipment for analyzing the milk and milk product samples to detect adulterants, heavy metals, pesticides and antibiotic residues by LCMS, GCMS, ICPMS in order to ensure the quality and safety of milk and milk products to consumers as per FSSAI standards. Under the NABARD-RIDF 2024-25 tranche XXX, installation of Automatic Milk pouch stacking and conveyor system work is being started at Metro Dairies viz., Madhavaram, Sholinganallur, Ambattur and Unions viz., Coimbatore, Salem, Madurai and Trichy at an estimated cost of Rs.30 crores. In order to fulfil the increasing demand of milk in Chennai, a new dairy with 10 Lakh litres per day capacity is being established at Madhavaram by availing loan under DIDF at an outlay of Rs. 14,218.68 lakh. The project will be completed by February 2026.

Now, I come to the Tamil Nadu Innovation Initiatives scheme (TANII) - buffalo calf rearing scheme under TANII. To increase the revenue of the Milk Producers Buffalo Calf rearing scheme (CRS) with Ovi synch & sexed semen insemination at Village level, is introduced for increasing buffalo milk production with estimated cost of Rs. 820.62 lakh, covering 2000 nos. of buffalo heifer calves in 12 district unions viz. Erode, Tirupur, Trichy, Karur, Salem, Namakkal, Kallakurichi, Dharmapuri, Kanchipuram, Dindigul, Krishnagiri and Cuddalore.

The Rashtriya Gokulmission - Progeny Testing Programme (RGM- PTP) - RGM - PTP is being implemented with a financial outlay of Rs. 2,087.51 lakh in three District Co-operative Milk Producers' Unions namely Vellore, Erode and Salem under the technical guidance of NDDB, with the objective of producing High Genetic Merit bull calves and to evaluate and rank bulls.

Dairying is one of the major sustenance factors of rural economy. The Dairy Development Department strives to improve the livelihood of milk producers by providing remunerative price to the milk producers and also by providing input services. Various initiatives like providing spot acknowledgement to the milk producers, milk testing equipment, incentives to the milk producers are being carried out in order to improve the income of the milk producers. The Dairy Development Department ensures supply of milk at a reasonable rate to the consumers. Continuous efforts are being taken to make all Dairy Cooperatives to be economically viable societies

Livestock is an integral part of agriculture, and it plays a significant role in the nutritional security of the people. The sector provides livelihood to more than two-thirds of the rural population. India has the largest

animal husbandry sector and contributes 18.6 percent to the total milk production of the world.

There are many challenges the sector will come across, during the process of achieving any set target in the future, like disease outbreaks, antimicrobial resistance, greenhouse gas emission, inadequate human resources and infrastructure for veterinary services, low productivity of animals, non-remunerative milk prices, unorganized markets for livestock products, poor livestock extension, and scarcity of feed and fodder. The shortage of fodder resources and ineffective control of animal diseases are very embarrassing to the country which is known for its acumen in cattle rearing. There is also an absence of field-oriented conservation strategy for indigenous breeds. The adoption of sex-sorted semen technology, by-product utilization use of feed supplements, replacement of low producing animals with the high producers, judicious use of antibiotics, promotion to organized market, livestock-based integrated farming system, and public-private partnership in the livestock sector are some of the suggested interventions to mitigate these challenges.

The livestock sector has more equitable distribution than agriculture so each scheme or policy of the Government directly affects the individual household. Each sub-sector of the livestock has an annual growth rate of more than five percent, validating the enormous potential for a rainbow revolution in the sector. Hence, it can be truly said that livestock is the new growth dynamo of the economy.

Before I conclude, I would like to urge the Union Government to take a serious note on the various issues and problems of fishermen communities, and people who live only on cattle rearing and dairy development, and allocate adequate funds for their welfare and sustenance so that they live with dignity and self-respect.

Thank You.

SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM): I am grateful for the opportunity to express my views on Demands for Grants under the control of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

Traditional industries such as animal husbandry and fishing have been associated with the livelihood of mankind since time immemorial. To meet the food and economic needs of 140 crore Indians, the development of fisheries, including animal husbandry and dairying, is becoming increasingly important. But I would like to record here that the funds allocated to such sectors by the Union Government and the interest shown in focusing on the critical issues faced by such sectors are not conducive to the importance of such sectors. Fishermen, the traditional workers of centuries-old human civilization, have been treated as third-class citizens without any significant emphasis on the pastoralist communities in this financial statement. This Government does not care about the fishermen in particular.

Tamil Nadu covers a coastline of 1076 km. Especially my Ramanathapuram parliamentary constituency which consists of mostly coastal areas. Our fishermen are suffering from natural calamities on the one hand and are being hunted by the Sri Lankan Navy on the other. I have brought these to the notice of this House several times. This Government is wasting time without finding a permanent solution to the problem of Tamil Nadu fishermen. The cry of our fishermen who are dying every day has not reached the ears of this Government??

On the morning of August 1, a Sri Lankan Navy patrol boat collided with the boat of four fishermen belonging to Rameswaram in Ramanathapuram district who were fishing near Nedunthidu. Also, the Sri Lankan Navy has taken away two fishermen who were on that barge and later released them. Another

fisherman is still being sought. I am just asking if this Union Government is not aware that our fishermen are constantly losing their lives in the sea.

Similarly, two days ago on August 3, the Sri Lankan Navy arrested four fishermen and a barge belonging to Jagathapatnam in my Ramanathapuram parliamentary constituency. Similarly, the Sri Lankan Navy arrested 25 fishermen and four national boats who had gone fishing from Pampan area of Ramanathapuram district on July 01, of which only 17 fishermen have been released. Only 14 of them have returned to the country so far. One of the 25 fishermen arrested has been sentenced to 18 months in prison. 9 fishermen and 2 boats were detained by the Sri Lankan Navy on July 22 and 3 barges and 22 fishermen on June 26. For the last five years, I have been talking about this in this House many times. Why the cries of our fishermen refuse to be heard by the Union Government.

But before the election, when the finance minister visited our Ramanathapuram parliamentary constituency, he took steps to release the arrested fishermen overnight. I just ask why you care about our fishermen only during elections, when our fishermen are killed and lives are lost. I am just asking why this Government is refusing to show the concern it has shown to our fishermen for election vote politics. Why is this Government refusing to protect our fishermen from Sri Lanka, a country that is smaller than us and dependent on us in every way?

Our Tamil Nadu Chief Minister has been writing letters to the Union Government in this regard. But the BJP Government is deceiving us without taking any action so far. The Sri Lankan Navy has arrested the country boats to an unprecedented extent. Immediate action should be taken to release the arrested fishermen and their boats. I request the Government to take immediate action to find a permanent solution to the issue of Tamil Nadu fishermen who are being arrested like this.

Similarly, our Hon'ble Tamil Nadu Chief Minister has announced a compensation of Rs 10 lakh to the family of the deceased fisherman. Similarly, he announced that the families of fishermen arrested and imprisoned by the Sri Lankan Navy will be given a relief of Rs 350 per day and Rs 6 lakh for films captured by the Sri Lanka Navy and unable to be rescued and Rs 2 lakh for country boats. But the Union Government refuses to provide relief. Therefore, I request the Union Government to ensure that appropriate relief is provided to the affected fishermen.

I request that recognition should be given to fishermen along with agriculture. I request the Government to waive off the loans of the fishermen community who are vulnerable to natural calamities such as storm surges, heavy rains, floods, cyclones and tsunamis. I request that a special loan assistance scheme be established for fishermen to purchase boats and fishing equipment. A National Bank for Fisheries and Fisheries Development should be set up. I request that steps be taken to provide fuel to the fishermen without taxes and cess from the Union and State Governments and to provide loans with 60 percent subsidy to the traditional fishermen.

We have been continuously demanding that the fishermen community should be given Schedule and Tribal status and exclusive reservation in education and economic employment. I request that steps be taken to provide such reservation keeping in mind their social development.

Also, we have been demanding for a long time that a modern fish processing factory and modern plants for fish export should be set up in Ramanathapuram parliamentary constituency where there are more

fishermen. I request the Government to take necessary steps to set up a fish processing factory. I also request the Union Government to pay serious attention to the various problems and challenges faced by the people who depend only on industries like animal husbandry and dairy development and fisheries and allocate adequate funds for their welfare and livelihood.

Thank You.

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) : मैं 2024-25 की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

सार में, यदि मैं कहूं तो, इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार की प्राथमिकता सूची में समाज के अंतिम घटक का उत्थान करना नहीं है ।

?सतह पर तैरते सागर, धरती की गोद में पशुधन,

यह बजट दिखा रहा है, सरकार की अदूरदर्शिता का दर्पण ।

मछुआरे और किसान रो रहे, उनकी चिंताओं को भुला दिया,

सरकार ने बजट में, इन सभी को रुला दिया ।

कहां है महिलाओं का सम्मान कहां है उनका सशक्तिकरण,

हमारी मांग है कि यह सरकार, अपने वादों को निभाए,

पंच महाभूतों का सम्मान करें, और सबके हितों का ध्यान लगाए ।?

मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय वह क्षेत्र है, जिसके माध्यम से हमारा देश आर्थिक विकास में लंबी छलांग लगा सकता है । बढ़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मत्स्यपालकों की अनदेखी की गई है और उनकी जरूरतों को पूरा करने में सरकार असफल रही है ।

हम सभी ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं । भारतीय संस्कृति में धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच तत्वों को पंचमहाभूत कहा जाता है । ये न केवल हमारे अस्तित्व का आधार हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी हैं । हमें इन पंचमहाभूतों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । लेकिन बजट में किए गए प्रावधान हमारे सागरों और जलाशयों का अत्यधिक दोहन बढ़ाएंगे, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है । मत्स्य उद्योग में नई तकनीकों और तरीकों के आने से प्रभावित होने वाले श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रावधान करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है । इससे उन श्रमिकों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा । सरकार महिला सम्मान और सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन फिशरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है । महिलाओं का समावेश और उनके कौशल विकास के लिए विशेष योजनाएँ बनानी चाहिए थीं ।

भारत विश्व का प्रमुख दूध उत्पादक देश है । कान्हा के देश में, नंदलाला, कन्हैया, बंसीबजैया माखन चोर के इस देश में, जहां दूध और मक्खन प्रचुर मात्रा में होते थे, आज दूध और डेयरी उत्पादों की बढ़ती कीमतें एक बड़ी समस्या बन गई हैं । पिछले वर्ष में दूध की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जिससे आम घरों का बजट प्रभावित हो रहा है ।

बजट में मत्स्य क्षेत्र को केवल जलीय कृषि (aquaculture) तक सीमित कर दिया गया है, जिससे समुद्री और पारंपरिक मछुआरों (marine and traditional fishers) पर बुरा असर पड़ा है ।

पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों के लिए बजट में 64.55% की कमी की गई है । 2022-23 के वित्तीय वर्ष के वास्तविक व्यय की तुलना में और पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 80.07% की कमी की गई है । डेयरी विकास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सहकारी माध्यम से डेयरी योजनाओं के

लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई है। (The budget for the program (Rs. 369 crore) has been decreased by 64.55% when compared to the actual expenditure in FY 2022-23, and 80.07% when compared to the revised estimates for the previous fiscal year.)

जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच लंपी त्वचा रोग के कारण 2,00,001 मवेशियों की मृत्यु हुई है, प्रति पशु लगभग 30,000 रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार ने इस नुकसान के लिए कोई मुआवजा योजना नहीं दी है और न ही कोई ऐसा कार्यक्रम घोषित किया है जो यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में मवेशियों को बचाने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत नीली क्रांति (Blue Revolution) कार्यक्रम के लिए धन में 56.8% की वृद्धि की गई है, लेकिन मछलीपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund) के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है।

(The budget for the program (Rs. 369 crore) has been decreased by 64.55% when compared to the actual expenditure in FY 2022-23, and 80.07% when compared to the revised estimates for the previous fiscal year.)

हमारी अन्य चिंताएं भी हैं: बंदरगाह परियोजनाओं, जलवायु परिवर्तन और संरक्षण प्रयास ने आदिवासी मछुआरा समुदायों के घरों और आजीविका को खतरे में डाल दिया है। मछली पकड़ने वाले और बिक्री करने वालों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे वे संस्थागत ऋण तक पहुंच से वंचित रह जाते हैं। मछली और संबंधित उत्पादों का विपणन अत्यधिक असंगठित और अप्रशिक्षित है। 2024 के बजट में इस समस्या को हल करने के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है। "असंगठित श्रमिकों की बड़ी संख्या के बावजूद, उनके कौशल विकास और उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं।

मैं देख रहा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र के मछुआरों, पशुपालकों और डेयरी उत्पादकों की वास्तविक समस्याओं का समाधान इस बजट में है या नहीं। सरकार को चाहिए कि वह इन क्षेत्रों के विकास और सुधार के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि देश के आम नागरिकों और किसानों का जीवन बेहतर हो सके। हम सभी को गायों की चिंता है। गौ हत्या निंदनीय है, लेकिन गौशालाएँ गायों को बचाने का समाधान नहीं हो सकतीं। फेवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि गायों की रक्षा कैसे होगी। मेरे पिता किसान थे। पशुपालक थे। स्वर्गीय यादवरावजी पडोळे ने पूर्व विदर्भ में दूध क्रांति शुरू की थी। उन्होंने सहकारी दूध डेयरी को गांव तक पहुंचाया और धान उत्पादक किसानों को डेयरी क्षेत्र से जोड़ा। आज मेरा संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। लेकिन सरकार क्षेत्र संकट में आ गया है। उसे सहायता की जरूरत है। मैं फिर से मुद्दे पर आता हूँ - गायों की रक्षा कैसे होगी? मेरे पिता का मानना था कि केवल चिंता करने से गायें नहीं बचेंगी। हमें ध्यान देना होगा कि गायों को अच्छा आहार मिले, ताकि वे स्वस्थ रहें और अधिक दूध दें।

हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्यों पशुपालक अपने पशुओं को खुले में छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। गायें भटक भटक कर जूठन खाकर अपना पेट भरती हैं। नंदलाला के देश में, गाय जूठन खाकर और हम स्वयं को सच्चा गौ भक्त कहलाएँ - इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जिस तरह हम गर्भवती माताओं और बच्चों के लिए पोषण आहार उपलब्ध करवाते हैं, उसी तर्ज पर प हमें दुधारू पशुओं के लिए भी योजना शुरू करनी चाहिए ताकि कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को खुले में छोड़ने के लिए मजबूर न हो।

मेरा संसदीय क्षेत्र हजारों तालाबों और प्रवाही नदियों से संपन्न है। यहाँ लाखों मछुआरे हैं। इन मछुआरों का जीवन उन्नत करने के लिए मेरे क्षेत्र में मत्स्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि अगली पीढ़ी तकनीकी और ज्ञान से संपन्न हो सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके।

मैं मानता हूँ कि मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र का विकास 5 बिंदुओं से होगाः तकनीकी उन्नयन उन्नत तकनीकों का उपयोग। कोशल विकास प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। पर्यावरणीय स्थिरता संसाधनों का स्थायी उपयोग और सुरक्षा मानकों का पालन। सरकारी समर्थन अनुदान, ऋण और बीमा योजनाएँ। महिला सशक्तिकरण योजनाएँ। महिलाओं को शामिल करना और उनके कौशल विकास के लिए विशेष

विश्व में ऐसे देश हैं जिन्होंने मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी पर आधारित अर्थव्यवस्था से अपना विकास किया है। उनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के उच्च मानकों को अपना सकते हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए नियमित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। हमें अपने देश के मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी उद्योगों को एक नई ऊँचाई पर ले जाना होगा। इन क्षेत्रों में विकास और उन्नति से हमारे किसानों, मछुआरों और उद्योग कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

धन्यवाद ।

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : गौ, गायत्री व गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। हमारे देश मे कई राज्यो मे भेड बकरी व घोडो के लिए अनुसंधान केंद्र व शिक्षण केंद्र खोले गए है परंतु गाय के लिए कोई केंद्र नहीं खोला गया है। निवेदन है कि गोगुन्दा क्षेत्र में गौ विज्ञान विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव करता हूँ जहां गौ विषय पर शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशलता की भी रचना बने। इस हेतु सीएसआर में धनराशि लगाने के लिए वण्डर सीमेन्ट की अनौपचरिक स्वीकृति भी मिल चुकी है । सादर ।

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां डेयरी और मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये सेक्टर न केवल देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान करते हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। 2024- 2025 के बजट में, भारत सरकार ने डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

झींगा पालन उद्योग को समर्थन देने के लिए, सरकार ने झींगा ब्रूडस्टॉक के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स (NBCs) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा, नाबार्ड के माध्यम से झींगा और निर्यात के लिए वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। झींगा ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वर्क्स और झींगा फीड पर आयात शुल्क में कटौती का भी प्रस्ताव है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और लाभप्रदता बढ़ेगी। पिछले 10 वर्षों में, भारत में दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। 2013- 14 में, दूध उत्पादन 137.69 मिलियन टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 209.96 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि न केवल उत्पादन क्षमता में सुधार को दर्शाती है बल्कि डेयरी किसानों की आय में भी वृद्धि को दर्शाती है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2013-14 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 307 ग्राम प्रति दिन थी, जो 2023-24 में बढ़कर 427 ग्राम प्रति दिन हो गई। यह वृद्धि भारतीयों के पोषण स्तर में सुधार का संकेत है। भारत ने पिछले दशक में दुग्ध उत्पादों के निर्यात में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023-24 में, भारत ने 1.34 लाख टन दूध पाउडर, घी, मक्खन, चीज़ और अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया। यह निर्यात 3,000 करोड़ रुपये का था, जो 2013-14 में 1,500 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए कुल 4,521 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशनः ₹700 करोड़; इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड-370 करोड़; Livestock Health and Disease Control Programme-2400 करोड़; वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन विभाग के लिए कुल 2,616.44 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित अनुमान में यह राशि 1,701.00 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2024-25 के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) योजना के लिए 2,352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं; यह आवंटन वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 56% अधिक है।

मैं मंत्री जी को इस क्षेत्र में कुछ सुझाव देना चाहूंगा- डेयरी सहकारी समितियों का सशक्तिकरण डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त बनाना आवश्यक है। इससे वे किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगी और उनके उत्पादों को बाजार में सही मूल्य मिल सकेगा। चारे की कमी दूर करने पर काम करे सरकार। आज देश में चारे की कमी है। हरा ही नहीं सूखे चारे की कमी भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इसका डेयरी सेक्टर की डिमांड के साथ ही लागत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। इसके लिए silos पर बड़ा काम किए जाने की जरूरत है। सरकार किसान और पशुपालकों को साइलेज और हे बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही साइलेज बनाने की मशीनों को लेकर कोई योजना बना सकती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग साइलेज बनाने के काम में शामिल हों। इससे किसानों की इनकम तो बढ़ेगी ही साथ में चारे की कमी भी दूर होगी।

डेयरी एग्रीकलचर में शामिल होते ही होंगे ये दो काम डेयरी को एग्रीकल्चर की कैटेगिरी में शामिल करने से दो बड़े फायदे होंगे। ऐसा करते ही किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पशुपालक भी हैं। क्योंकि अगर डेयरी सेक्टर को एग्रीकल्चर में शामिल कर लिया जाता है तो मौजूदा बिजली के रेट कम हो जाएंगे और फिर टैक्स भी उसी हिसाब से लिया जाएगा। अगर केन्द्र सरकार अपने बजट में डेयरी को एग्रीकल्चर की कैटेगिरी में शामिल करती है, डेयरी में इंवेस्ट बढ़ाती है और साथ ही डेयरी से जुड़े स्टार्टअप को प्रोत्साहन देती है तो इस सेक्टर में नौकरियों की भरमार होगी और गांव के युवाओं को शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा।

डेयरी उद्योग वर्तमान में अधिशेष की समस्या का सामना कर रहा है, जिसमें 300,000 MT से अधिक स्किम्ड दूध पाउडर (SMP) और 100,000 MT मक्खन स्टॉक हैं। इसे संबोधित करने के लिए, सरकार को भारत के खाद्य निगम के अनाज भंडार की तरह दूध पाउडर और मक्खन के लिए एक राष्ट्रीय बफर स्टॉक स्थापित करना चाहिए। यह बफर कीमतों को स्थिर कर सकता है, संकट बिक्री को रोक सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अधिशेष के दौरान, बफर स्टॉक अतिरिक्त उत्पादन को अवशोषित कर सकता है, और कमी के दौरान, यह बाजार स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टॉक जारी कर सकता है।

भारत का डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय विकास और उपलब्धियों का साक्षी रहा है। दूध उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में सुधार, दुग्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और डेयरी प्रसंस्करण में नवाचार ने इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है।

सरकार के बजट आवंटन और नीतियों ने इस क्षेत्र को और भी सशक्त बनाया है। उत्पादकता में सुधार, पशु निपटान और वध कानूनों में सुधार, अवसंरचना विकास के लिए अनुदान और सॉफ्ट लोन और राष्ट्रीय बफर स्टॉक की स्थापना जैसे सकारात्मक सुझावों को अपनाकर, भारत का डेयरी उद्योग और भी मजबूत और उत्पादक बन

सकता है।

इन सुधारों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार होगा।

श्री पुष्पेंद्र सरोज (कौशाम्बी) : मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशांबी की जनता की ओर से और विपक्ष की ओर से अपनी बात रखना चाहता हूँ।

आज हम केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखते हैं, विशेष रूप से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट पर। यह मंत्रालय हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस बार के बजट में इस मंत्रालय को जो आवंटन मिला है, वह हमारे किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले, मत्स्य पालन के क्षेत्र में आवंटित धनराशि पर ध्यान दें। यह क्षेत्र न केवल लाखों मछुआरों की जीविका का स्रोत है, बल्कि हमारे खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछले वर्ष के बजट में मत्स्य पालन के लिए 2,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर केवल 2,500 करोड़ रुपये किया गया है। यह मात्र 8.7% की वृद्धि है, जो कि मछुआरों की जरूरतों और क्षेत्र के विकास के लिए नाकाफी है। इसके अलावा, सरकार ने कई स्थानों पर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगा दी है और मछुआरों के लिए नौकाओं की उपलब्धता भी सीमित कर दी है। इससे मछुआरों की आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ा है और वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

पशुपालन क्षेत्र की बात करें तो, यह क्षेत्र हमारे किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पिछले वर्ष के बजट में पशुपालन के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष इसे घटाकर 3,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह समझ से परे है कि जब हमें किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करना है, तब इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश घटाया जा रहा है। हमें पशुओं की देखभाल, टीकाकरण और चारे की उपलब्धता के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

डेयरी उद्योग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। हमारे देश में दूध उत्पादन में हम विश्व में अग्रणी हैं, लेकिन इस उद्योग की चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हमारे राज्य में दो प्रमुख पराग डेयरी खोली गई थीं, जो अब बंद होने की कगार पर हैं। इन डेयरियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष डेयरी क्षेत्र के लिए 4,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि इस वर्ष इसे बढ़ाकर 4,400 करोड़ रुपये किया गया है। यह मात्र 4.8% की वृद्धि है, जो डेयरी किसानों के समक्ष आर्थिक संकट को हल करने के लिए अपर्याप्त है।

इसके अलावा, राज्य में आवारा पशुओं की समस्या भी विकराल रूप ले चुकी है। आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई स्थानों पर इन पशुओं के कारण बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। किसान न केवल अपनी फसलें खो रहे हैं, बल्कि कई बार अपने जीवन और संपत्ति को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सरकार को इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो सके और किसानों को राहत मिल सके।

अंत में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशांबी के लिए कुछ महत्वपूर्ण माँगें रखना चाहता हूँ:

- मछुआरों के लिए सुरक्षा सहायता बहाल करना : सरकार को तत्काल प्रभाव से मछुआरों के लिए सुरक्षा सहायता की गतिविधियाँ फिर से शुरू करनी चाहिए, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें और सुरक्षित रूप से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।
- आवारा पशुओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई: आवारा पशुओं के मुद्दे को हल करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। इन पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन और आश्रय की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को होने वाली क्षति को रोका जा सके।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) का सुधार: हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को सुधारने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति और कमजोर वर्गों को इस योजना के तहत पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस बजट पर पुनर्विचार किया जाए और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए, ताकि हमारे किसान और ग्रामीण क्षेत्र मजबूत और समृद्ध हो सकें।

धन्यवाद।

दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा डेयरी विभाग के लिए दी गई बजट राशि पर अपने विचार रखता हूँ। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा डेयरी विभाग को मजबूत बनाने के लिये 2024-25 के

वितीय वर्ष में 4521.24 करोड़ की धनराशि प्रदान कर अनेकों परियोजनाओं के कार्यों की गतिशक्ति बढ़ानें का कार्य किया है।

मैं इसका सर्मथन करता हूँ। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में 20050 करोड़ रूपये सर्वोच्च निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी०एम०एम०एस०वाई०) नामक प्रमुख योजना को लागू किया गया है, जो किसानों की आय वृद्धि करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं जो केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा चालू की गई है उससे प्रत्येक किसानों को आर्थिक लाभ में काफी वृद्धी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि बिहार के किसानों के हित में भी अनेक प्रमुख योजनाएँ चालू की है। बिहार जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के मछुआरों एवं किसानों को मत्स्य पालन करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। मत्स्य पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी को मशीनरी के साथ-साथ हैचरी में मछली पालन करने के लिए 70 तक का अनुदान दिया जाएगा। बाकी की शेष राशि को लाभार्थी द्वारा बैंक लोन या खुद वहन करना होगा। अनुदान राशि प्राप्त कर राज्य के मछुआरे एवं किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना को बिहार राज्य में शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अलंकारी थोक, खुदरा, ब्रीडर, शौकिया पालनकर्ता को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। ताकि राज्य में सजावटी (अलंकारी) मछलियों के व्यापार को टिकाऊ बनाकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाए जा सके। समग्र अलंकारी मत्स्यिकी योजना बिहार के माध्यम से अलंकारी मछलियों के व्यापार से जुड़े अन्य वर्ग के आवेदकों को मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करवाने पर 50% अनुदान दिया जाएगा और SC/ST वर्ग के आवेदकों को 50 से 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। जिससे इच्छुक व्यक्ति आसानी से इस व्यापार को कर सके और उन्हें ज्यादा आर्थिक दबाव न झेलना पड़े। Bihar Samagra Alankari Matsyaki Yojana 2024 का मुख्य उद्देश्य विशेष तौर पर अलंकारी थोक, खुदरा ब्रीडर, शौकिया पालनकर्ता, वयवसायी को अलंकारी आधारभूत, संरचना एवं संवर्धन इकाइयों का सुदृढीकरण और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहायता पहुंचाकर इस कारोबार को सतत एवं टिकाऊ बनाना है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल एवं कोशी क्षेत्र के किसानों के लिए मत्स्य पालन एवं पशुपालन तथा डेयरी विभाग की सुविधा हेतु मुख्य मांगो की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत-

- डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना स्थापित की जाए ।
- मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना स्थापित की जाए।
- पशु चारा संयत्र स्थापित किया जाए।
- नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित किया जाए।
- पशु अपशिष्ट से संपत्ति धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) और
- पशु चिकित्सा टीके और औषधि निर्माण के साथ पशुओं के लिए अस्पताल, इन सभी सुविधाओं की स्थापना की जाए।
- मेरे क्षेत्र सुपौल में वेटनरी कॉलेज की स्थापना की जाये जिससे उत्तरी बिहार के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): In order to improve the livelihood of fishermen living in Kancheepuram parliamentary constituency, Union Government should distribute petrol and diesel to them at subsidised prices. Sea erosion should be prevented in order to protect the houses of fishermen of Tamil Nadu. Boats, motor and nets should be provided to our fishermen on subsidised prices. In my Kancheepuram constituency, fishermen are living in the villages like Kanathur, Kovalam, Devaneri Kuppam, Kokilamedu and Idaikkazhinaadu in dangerous situations due to sea erosion in these areas. Seawalls should be constructed along these coastal areas in order to prevent sea erosion. I urge that a warehouse with fish processing facility should be set-up in Mamallapuram area for the welfare of our fishermen. Thank you

DR. BACHHAV SHOBHA DINESH (DHULE): I would like to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

We start our day by consuming dairy products and that is why, it is important to discuss this issue. The Union Government has disbursed Rs. 2,585 crore to Fisheries and Rs. 4,521 crore to Dairying Department. But it is a lesser allocation in comparison to the year

2023-24 as the farmers and fisherman are totally dependent on their professions to earn their livelihood. We consider farmers as food providers and Smt. Nirmala Sitharaman has cleared that farmer?s welfare has given utmost priority in the budget. So, the budget provisions for fisheries and dairying should be doubled. Our country has got a coastline of 7517 km. and Maharashtra has also got 720 km. long coast line.

During last five years, due to the cyclonic storms like Phyan, Vaayu, Nisarga, Tauktae, the poor fishermen had to suffer a lot and incurred heavy losses and they have to face these calamities every year.

So, I would like to request the Union Government to make a significant provision for these poor fishermen in the budget. In this year?s budget, Rs. 2,352 crores have been allocated for fisheries under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. An additional allocation of Rs. 1000 crore should be made to it so that the fishermen could further develop their business as well as recover from natural calamities.

Water pollution is also a big menace which pollutes the water of rivers as well as seacoast in Maharashtra which badly affects fish farming. So, to control this water pollution, Central Government should set up water purification plants. There is a lack of training and technical assistance for fisheries which causes problems in product upgradation. So, Central Government should open at least one fishery, poultry or animal husbandry training institute.

My State Maharashtra is leading in the cases of farmers? suicides. For the last few years, Yavatmal district was identified as farmers? suicide capital of Maharashtra, but now Amravati District is at top position. As per records, till May 2024, 143 farmers in Yavatmal district and 132 farmers in Amravati district have committed suicide. Due to barrenness of land, indebtedness and natural calamities, the number of suicide cases have been increased. Fluctuation in milk prices is also a big trouble which affects milk producing farmers and also causes deterioration in milk quality. These milk producing farmers lack proper training and that is why they are unable to increase milk production too. There is no market available for milk products in Maharashtra. Hence, it is necessary to control and regulate the prices of milk products. Union Government should set up milk testing centres at city and Tehsil levels and also open Dairy Training Institute to enhance the production of dairy products. The Central Government should allocate sufficient funds for it. Thank you.

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL): Today, I would like to address the pressing concerns and shortcomings in the budget allocation for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying for the fiscal year 2024-25. As we delve into the details, it becomes evident that this budget falls short of addressing the needs and aspirations of our fisherfolk, dairy farmers, and those dependent on animal husbandry.

Firstly, let's talk about our fisherfolk. This budget is a significant letdown for them. The Government's approach has led to the exploitation of our oceans and water bodies without adequately addressing the needs of the people who rely on these resources for their livelihoods. The budget fails to provide provisions for upskilling the workforce in the fisheries industry. With the introduction of new technologies and methods, our workers are left in the lurch, unable to compete or thrive in this changing environment.

Moreover, the issue of gender inclusion in the fisheries sector is glaringly ignored. Skilled and trained women workers are almost absent in this sector, and there are no provisions for their inclusion or skill enhancement. This is a severe oversight in a country that prides itself on 'Nari Samman aur Sashaktikaran' (respect and empowerment of women).

Moving on to the dairy sector, despite India being a leading milk producer globally, the rising prices of dairy products have been a significant challenge for consumers. Over the last year, the cost of milk increased by Rs. 10 per liter, affecting the daily household expenditure of millions. The Government has failed to control these prices, which has severely impacted the common man.

The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying, created in 2019, operates through two departments. The Department of Fisheries is responsible for the formulation of policies and schemes related to the development of inland, marine, and coastal fisheries and fishery institutes across the country. The Department of Animal Husbandry and Dairying handles livestock production, disease prevention, and dairy development.

Despite a significant increase in the overall budget for the Ministry compared to the previous fiscal year, the Government's focus has been skewed. The fisheries sector has been reduced to aquaculture, severely affecting marine and traditional fishers due to the capital and profit-driven approach. The budget focuses on boosting fish culture and farming, leaving out other crucial aspects within the fisheries sector.

The Finance Minister announced a reduction in customs duty on essential inputs to 5% and proposed import duty reductions on key inputs for shrimp farming to strengthen India's shrimp farming industry globally. However, these measures benefit large-scale commercial operations more than our traditional and small-scale fishers.

The Department of Animal Husbandry and Dairying's development programs have seen a significant reduction in funding. The budget for these programs has decreased by 64.55% compared to the actual expenditure in FY 2022-23. Shockingly, no funds have been allocated for Dairy Development, the Rashtriya Gokul Mission, or Dairying through Cooperatives for the current fiscal year. This reduction in funding undermines the growth and sustainability of the dairy sector.

Between July 2022 and July 2023, we witnessed 200,001 cattle deaths due to Lumpy Skin Disease, with an estimated loss of Rs. 30,000 per animal. The Department has neither provided a compensation scheme for farmers affected by these losses nor introduced a scheme to control the spread of the disease. This neglect is unacceptable and detrimental to our farmers' livelihoods.

Under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY), funds for the Blue Revolution program have increased by 56.8% compared to the previous fiscal year. However, no funds have been allocated for the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund. Additionally, there has been a significant shortfall in the development of brackish water aquaculture, with only 52 hectares under cultivation against a target of 1,300 hectares in FY 2022-23. The Government's promises remain unfulfilled, and our fishers continue to suffer.

Other areas of concern include the impact of port projects, climate change, and conservation efforts on the homes and livelihoods of indigenous fishing communities. The budget fails to support these communities adequately. Fish vendors, curers, and marketers are not considered for Kisan Credit Card issuance, limiting their access to institutional credit. The marketing of fish and related products remains highly unorganized and unregulated, with no specific plan introduced to address this issue in the 2024 budget.

Despite a large unskilled workforce, no measures have been implemented to develop their skills and boost the industry's growth. The government has not included a specific insurance scheme for dam fishers, leaving them vulnerable to heavy losses during rainfall. Once again, there is no focus on 'Nari Samman aur Sashaktikaran,' as skilled and trained women workers remain absent in the fishery sector, with no provisions made for their inclusion.

In conclusion, while the Government claims to support the fisheries, animal husbandry, and dairy sectors, the budget for 2024-25 reveals a different story. Our fisherfolk, dairy farmers, and those dependent on animal husbandry deserve better. They need a budget that addresses their needs, supports their growth, and empowers them to thrive. Let us work together to ensure that the voices of our hardworking citizens are heard and that their concerns are addressed with the urgency and importance they deserve.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): Fisherfolk have been let down by this budget as it does not address their needs. The budget will lead to exploitation of India's oceans and water bodies. Budget has no provisions for upskilling the workforce in the fisheries industry, who are affected by the introduction of new technologies and methods. No focus on 'Nari Samman aur Sashaktikaran': skilled and trained women workers are almost absent in the fishery sector, no provisions for their inclusion or skill enhancement. Despite India being a leading milk producer in the world, the rising prices of dairy products has been a challenge for consumers, with the government failing to control prices of milk and related products, Over the last year the cost of milk increased by Rs. 10/ liter, affecting daily household expenditure. The disproportionate allocation of centrally sponsored schemes and subsidies favors aquaculture at the expense of marine fisheries and post-harvest operations. As it stands, the current allocation provides approximately 70% of the financial support to aquaculture, leaving a mere 30% for marine fisheries and post-harvest operations. This imbalance is not only unfair but also detrimental to the sustainability and growth of the marine fisheries sector, which plays a crucial role in our national economy and food sccurity and is likely to displace Approximately 2 crore fishermen who solely depend upon fishing for their livelihood. The capital and profit driven approach of the governmenthas reduced the fisheries sector to aquaculture, thereby severely affecting the marine and traditional fishers.

The overall funding for Development Programs under the department of Animal Husbandry and Dairying, has reduced significantly. The budget for the program (Rs. 369 crore) has been decreased by 64.55% when compared to the actual expenditure in FY 2022-23, and 80.07% when compared to the revised estimates for the previous fiscal year. Under the scheme, no funds have been allocated for Dairy Development, the Rashtriya Gokul Mission and Dairying through Cooperatives for the current fiscal year. Between July 2022 and July 2023, there have been 2,00,001 cattle deaths due to Lumpy Skin Disease, with an estimated loss of Rs. 30,000 per animal. Neither does the Department provide a compensation scheme for farmers affected by these losses nor has the Government introduced a scheme to control the spread of the disease.

Port projects, climate change, and conservation efforts threaten homes and livelihoods of indigenous fishing communities. Budget fails to support fishermen. A standing committee report noted that fish vendors, curers, and marketers were not considered for Kisan Credit Card (KCC) issuance, limiting their access to institutional credit. The marketing of fish and related products is highly unorganised and unregulated. No specific plan has been introduced to address this problem in the recent budget of 2024.6. Despite a large unskilled workforce, no measures have been implemented to develop their skills and boost the industry's growth. Despite Standing Committee recommendations, the government has not included a specific insurance scheme for dam fishers in the budget leaving dam fishers vulnerable to heavy losses during rainfall. No focus on 'Nari Samman aur Sashaktikaran' as widely claimed by the Government. The skilled and trained women workers are almost absent in the fishery sector, no provisions have been made for their inclusion. Despite being a leading milk producer, India faces rising dairy product prices. The government has failed to control these prices, with a Rs. 10 per litre increase last year, significantly impacting household expenses.

Beach nourishment for beach erosion: Of the 8118 k.m. coastline in the country, 42% of the coast has already been washed away and the main cause highlighted is the sudden construction of unplanned ports/harbors which are documented by reports of the National Institute of Port Management (NIPM). In Goa, almost 20% of our coastline is on the verge of vanishing, according to the report by the National Centre for Coastal Research (NCCR), an institute under the Ministry of Earth Sciences.

In Goa, the unregulated dredging carried out by the Mormugao Port Authority (MPA) is affecting our sandy beaches of Goa. The maintenance dredging carried at MPA of more than 6 lakh cubic-millimeter (M3) of sediment is dredged every year. This continuous dredging of such a large quantum is destroying the ecology of the region and this has aggravated the sand erosion and has caused drastic

morphological changes as is very evident at Khariwado, Siridao, Baina, Destero beaches as the major part of the beach is already eroded and now this is adversely effecting other beaches too including Velsao, Cansaulim, Arossim, Majorda, Colva, Benaulim, etc.

SHRIMATI PRATIBHA SURESH DHANORKAR (CHANDRAPUR): There is an urgent need to focus on fisheries if you really want to develop the fishermen community by making this profession more progressive. More women should be engaged in this profession and the women related to Bachat Gat (self-help group) should be given priority. If you provide fishery Cages for fishing in smaller rivers and lakes to these women Bachat Gat, it would help in further strengthening of this group. It should be implemented through the State as well as Union Government.

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) : पशुपालन हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी है। As per PLFS 2022-23 data, agriculture allied sectors engaged 46% of the Indian workforce. 2020-21 में, प ने देश की कुल income का लगभग 5% हिस्सा बनाया था। पशुपालन किसानों की आय बढ़ाता है बल्कि देश के पोषण level को भी ऊंचा उत Without a doubt, animal husbandry is an important pillar for an economy's foundation. In my parliamentary constituency of Sang dear grandfather respected Late Padmabhushan awardee Vasant Patil ji had laid the foundation of a cooperative. बीते बोहोत व cooperative movement पशुपालन के sector में भी प्रवेश किया है। How it is concerning to note that the Department of Animal Husbandry Dairying has consistently failed to effectively utilize allocated funds to underutilization between FY 2019 to 2021 to a tune of Rs 154 Crore. There has been continuous cuts in allocation as per DFG 202 the department coupled with revision of targets of various scher noted in the Standing Committee reports. This mismanagement of pu funds is detrimental to the development of the animal husbandry dairying sector, slowing the pace of its economic contribution. इसका परिणाम मेरे क्षेत्र तक भी पहुंचा है।

To begin with the Rashtriya Gokul Mission, संगली में 2022 के एक Lok Sabha reply se पता चलता है कि MAITRI program में केवल 9 युवाओं को training दिया गया था और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसी reply में 2022-23 के लिए targeted and achieved MAITRI centres, उसका कोई उल्लेख तक नहीं है। संगली में कुल मिलाकर केवल 6 Veterinary Hospitals हैं। अब ESVHD Scheme की बात करे तोह 2018-19 to 2021-22 में महाराष्ट्र को कोई funds नहीं मिले।

Moreover, studies from Indian Veterinary Research Institute in Sangli shows that around 42% farmers prefer private services where the doctor comes to visit. Thus, I urge the Government to ensure funds are disbursed and coordination with the State Government is made to set up para-vets.

वित्त मंत्री ने अपने interim budget भाषण में यह बताया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा milk producer देश है लेकिन यहां milch animals की productivity कम है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बात संगली को कैसे प्रभावित करती है। NDDB का आंकड़ा दिखाता है कि सांगली में सिर्फ 1 semen station है और E- pashuhaat में 3 अगस्त की बात है, मात्र 37 frozen semen records थे जिनमें से ज्यादातर Holstein exotic breeds थे। साफ है कि Indian breeds में cross breeding अच्छे से नहीं हो रही है। Cross breeding is essential. As per Tamil Nadu Agricultural University, cross breeds were found to have higher birth weight, faster growth rate. At first calving there is higher lactation yield, longer lactation period. Shorter service period, dry period and milk production, high breeding efficiency.

It is unfortunate to note कि सांगली में 0 IVF Embryo centres हैं। सांगली में 0 sexed sorted semen centres है। सांगली में 0 Breed Improvement Institues हैं। बड़ा साफ़ है क्यों सांगली अभी भी less than 50% coverage of artificial insemination के दायरे में आता है।

वित्त मंत्री ने आपने interim budget में जिक्र किया था कि Foot and Mouth Disease (FMD) हमारे पशुपालन में harm पोहोचति है। Eradication target है 2030, लेकिन आप implementation देखिये। 12% brucellosis vaccination हुआ है महाराष्ट्र में, और ICAR का आंकड़ा है कि 0 buffaloes vaccinate हुए है सांगली के जाट, वालेखिंदी और गुगवाद क्षेत्रों में। ये दिखाते है 94% FMD vaccinated है महाराष्ट्र में, लेकिन ICAR का data दिखता है की low percentageof

animals sampled हैं। मैं अपेक्षा रखता हु की Government सांगली में Livestock Health & Disease Control Scheme में इन vaccination gaps को address करे। This holds great importance in the face of rising impact of climate change on animal health. As per World Organization for Animal Health, the proponent of the "One Health" concept states that 60% of existing human infectious diseases are 89 zoonotic and at least 75% of emerging infectious diseases of humans have an animal origin. Controlling zoonotic pathogens at their animal source is the most effective and economic way of protecting people, which also falls in line with the National One Health Mission of the Government of India.

I would like to talk of other schemes of the Ministry. NABARD का रिपोर्ट दिखाता है कि मेरे सांगली के पास 25 करोड़ का credit potential है लेकिन अभी भी कई सारे dairy plants जैसे मिराज में बंद पड़ा है, आशा करता हूँ सरकार National Programme for Dairy Development के under इन मुद्दों को हल करे | National Livestock Mission की बात करूं तो 25 लाख subsidy दी जाती है poultry के लिए, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक सांगलिकार को Gopal Ratna Award दिया गया लेकिन ground reality तो यह है कि बहुत सारे poultry businesses बंद हो रहे हैं। NABARD बताता है कि सांगली में fisheries जिसमें करीब 13 Crore का credit potential है, उसमें processing और value addition ना के बराबर है। मैं आशा करता हूँ कि PM Matsya Sampada योजना के under सांगली को शामिल किया जाए। The Government in its Interim budget said that it will provide a 3% interest subvention for eight years to modernize Dairy cooperatives and strengthening of dairy plants.

However, with procurement prices of milk dipping from time to time since COVID, on behalf of many dairy farmers in Sangli and Maharashtra, I propose the Government to coordinate with States regarding adoption of the C Rangarajan Committee's revenue sharing formula (RSF) for the dairy sector. This will help shield the dairy sector from price volatility, helping the dairy business to grow and overcome the brunt of post- COVID crisis. अंत में यही बोलूंगा कि Standing Committee की report दिखाती है कि विभाग बिना खर्चा करके भी demand बढ़ा रहा है, आशा करता हूँ कि यह actual expenditure में तब्दील हो, न केवल सांगली के लिए पर महाराष्ट्र और पूरे भारत के लिए।

SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I would like to place my views on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for 2024-25.

Allied jobs pertaining to agriculture for farmers are getting reduced. The Government should give more attention to allied sector for the welfare of farmers. In the rural sector, fisheries, animal husbandry and dairy industry provide income to farmers and backward classes. But the BJP Government has given very less amount in the 2024-25 Budget for this sector. There is an urgent need to provide more funds and attention towards the milch cattle. The milk of cows and buffaloes is being used by all families in India for drinking, making tea, making cheese etc. In Punjab, Verka is a cooperative agency being run by the State Government. This agency directly purchases milk from farmers. Adulterated milk is wreaking havoc on the health of common man. Such spurious products are spreading diseases like cancer.

I urge upon the Government that those who sell adulterated milk and milk products must be brought to book. Cases of causing death and disease should be lodged against such shady elements. No political interference should be tolerated. There are no checks done regarding adulteration by the concerned Department. Farmers are being exploited. Let me say that even in all units of Punjab?s cooperative Verka, rampant corruption is there. Milch farmers are not getting remunerative prices for the milk etc. sold by them to Verka.

I urge upon the Centre to send a high-level delegation to probe the rampant corruption present in cooperatives like Verka. Officers found guilty must be given stringent and exemplary punishment. Fisheries

can become a remunerative allied sector for farmers. But the State Government must provide relevant information and help to farmers and labourers. This should not be done only as a ritual. Tangible steps should be taken. Otherwise, what happens is that those who don?t know anything about fisheries will fail miserably if they take up this occupation. During earlier times, the milk of native species of cows and buffaloes like Sahiwal and Gir was considered very beneficial for the health of people. I urge upon the Government to take necessary steps to improve and encourage the breeding of native species of cows and buffaloes. Allied occupations like pig rearing, rabbit rearing, honey production through keeping honey-bees etc. should be encouraged and such farmers should be helped financially. It will help the rural people increase their income by adopting these allied occupations.

I urge upon the Government to implement all schemes related to fisheries, animal husbandry and dairying for the farmers etc. of the border area of my constituency Amritsar. These people should be given more subsidy to pursue these occupations. Goat milk is very beneficial for patients suffering from Dengue fever. The Government should popularise this remedy. The Government should also try to control the cattle roaming freely on roads and streets. In the end, I thank for allowing me to lay my speech on the Table of the House.

Thank you.

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): India has made remarkable strides over the decades in the agricultural sector, particularly, in fisheries, animal husbandry, and dairying. We are the producers of nearly 25 per cent of the world's milk and dairy sector. With a coastline stretching over 7500 kilometres, India ranks second in global fish production, contributing significantly to the livelihoods of millions. The fisheries sector alone employs over 14 million people and has an export value surpassing $7 billion annually.

Although India accounts for one-fourth of the world's milk production, this figure has been decreasing due to inadequate attention to livestock well-being, particularly, in States that fail to vaccinate their livestock, adversely affecting output quality. The emergence of new diseases affecting cattle, fish, and other animal's demands Innovative approaches to help the sector grow and contribute significantly to the country's potential.

Building the capacity of animal health professionals, evolving the subject academically to cover the emerging scenario is imperative for the empowerment of rural and urban poor. Improved animal health translates to better productivity and income for small farmers and dairy producers. Ensuring healthy livestock leads to increased milk production and better-quality dairy products. Outbreak of diseases needs increased invigilation, contemporary and advanced approaches for effective management and prevention.

We request the Union Government to provide substantial grants beyond the allocated Rs. 520 crore to our State for fisheries, animal husbandry, and dairying. There are specific areas of concern that need immediate attention. In Karnataka, there is an urgent need for more veterinary hospitals and doctors. Enhanced education and training programs are needed to make animal husbandry an attractive career option for students. Additionally, gaps in the implementation of existing schemes must be addressed to ensure better outcomes.

In regions like Davanagere, prevalent cattle diseases require immediate attention and intervention. Proactive measures and timely vaccination programs are critical to prevent disease outbreaks and maintain livestock health

We specifically request grants for infrastructure development, including funds for the construction and upgrading of veterinary hospital and clinics across Karnataka and other States facing similar challenges. Programs to train and recruit more veterinary doctors and animal health professionals are essential to meet the growing needs of the sector. Supporting educational institutions to offer specialized courses in animal husbandry and veterinary sciences will attract more students into these fields.

Implementation of existing Government schemes by addressing the gaps and providing necessary resources and support to State Governments is crucial. Investing in research and development tackle new and emerging diseases in cattle, fish, and other livestock will promote innovative solutions and treatments. Establishing standards and regular assessments to ensure the production of high-quality, nutritious dairy products that meet both domestic and international standards is also important. Providing immediate assistance to address the disease outbreak in Davangere, including vaccination drives and veterinary support, is essential.

To achieve self-reliance in fisheries, animal husbandry, and dairying, it is imperative that the Union Government provides the necessary grants and support. This will empower the rural and urban poor, enhance milk production, and improve the overall quality of dairy products. Addressing the specific needs of States like Karnataka and regions like Davanagere will ensure a healthier and uses productive livestock sector, contributing significantly to India's agricultural and economic growth. We urge the Government to consider these requests and take immediate action to support this vital sector.

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I express my wholehearted support for the Demands for Grants presented by our respected Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Minister, Shri Rajiv Ranjan Singh.

First and foremost, I must commend the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji and the diligent efforts of our Minister in steering this crucial sector towards unprecedented growth and development. Under their guidance, we have witnessed remarkable progress in the fields of animal husbandry, dairying, and fisheries. The allocation of Rs. 7,138 crore for 2024-25, marking a significant 27 per cent increase over the previous year, demonstrates the Government's unwavering commitment to these vital sectors of our economy.

Our nation's dairy sector continues to shine on the global stage. India proudly maintains its position as the world's largest milk producer, accounting for an impressive 25 per cent of global production. This achievement is a testament to the hard work of our farmers and the effectiveness of our policies. Our domestic milk production reached a remarkable 231 million tonnes in 2022-23, growing at a robust annual rate of 5.7 per cent since 2016-17. This growth not only ensures food security but also provides a stable source of income for millions of rural households.

Turning to our fisheries sector, we have made equally impressive strides. India has emerged as the third-largest fish producer globally, contributing 8 per cent to the world?s production. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been instrumental in this success, enhancing fish production and improving post-harvest management. This scheme's holistic approach addresses critical gaps in the value chain, from production to consumption, benefiting fishermen and consumers alike. Our efforts in these sectors have borne fruit in the international market as well.

Our marine product exports exceeded Rs. 60,000 crore in 2022-23, growing at an annual rate of 8 per cent since 2018-19. This remarkable achievement showcases the increasing global demand for Indian seafood and our improved production capabilities. It is a clear indicator that our products are competitive and sought after in the global marketplace.

The health and welfare of our livestock remain a top priority for this Government. The allocation of Rs. 2,465 crore for the Livestock Health and Disease Control Programme in 2024-25 represents a substantial 64 per cent increase. This significant boost in funding underscores our commitment to preventing and controlling animal diseases, thereby protecting our farmers' livelihoods and ensuring the quality of our animal products.

We also recognize the importance of preserving our indigenous bovine breeds. The Rashtriya Gokul Mission continues to play a crucial role in this endeavor, while simultaneously enhancing milk production. This initiative benefits around nine crore farmers engaged in dairying, contributing significantly to rural prosperity and the preservation of our agricultural heritage.

While we celebrate these achievements, we must also address some challenges to ensure continued growth. We need to work closely with States to improve vaccination rates against diseases like foot and mouth disease and brucellosis. To combat outbreaks like the recent Lumpy Skin Disease, we should consider establishing a dedicated fund for compensating affected livestock owners and intensifying research for more effective vaccines.

In the fisheries sector, to meet our ambitious production targets, we must accelerate the development of fishing harbours and landing centres. To achieve our goal of Rs. 1 lakh crore in marine exports by 2024-25, we should invest in improving production of commercially important freshwater fish and addressing international trade barriers. Additionally, given that almost half of our livestock product imports are animal fodder and feed, intensifying research and development in domestic feed production could help reduce import dependency.

In conclusion, I wholeheartedly support the Demands for Grants for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. These allocations are a reflection of Prime Minister Narendra Modi Ji's unwavering commitment to the welfare of our farmers, fishermen, and his vision of a prosperous, self-reliant India. Under his dynamic leadership, I am confident that we will not only meet but exceed our goals, ushering in a new era of growth and sustainability in animal husbandry, dairying, and fisheries. Thank you.

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The fisheries, animal husbandry and dairying sector of the country needs great investments, considering the backward nature of people who are most dependent on them. Also, the climate change and related issues have made it more and more difficult for the people to sustain their livelihood through these vocations. In this scenario, I would like to bring to the attention of the Government a few issues that concern us.

My constituency Idukki is known for its plenty of water bodies including colossal reservoirs like that of the Idukki Dam. There is an immense potential for the development of inland fisheries in these water bodies. It is also necessary that we invest in developing infrastructure as well as technical knowhow in raising globally-demanded fish stocks in these water bodies. Considering all these, the Government must declare a package for developing inland fisheries in Idukki.

The plight of people who depend upon dairying as a livelihood is grossly ignored by the Government. Their life is precarious, depending upon the existence of milk collection networks in their area. Many of them even do not receive assured buying guarantee or prices for milk. Considering this, they also deserve a package. My humble submission is that they are included in the ambit of MGNREGA or a similar scheme so that their work is covered under that scheme. This will also ensure that they receive an amount to sustain their livelihoods.

The Government has imposed GST on the dairy cooperative societies. It is causing a great distress to the farmers who are dependent on them. On the one hand, the margins are very less, and on the other hand, they are exposed to various risks. Taking this into considering, it is unacceptable that they have to pay additional GST. I request the Government to remove the GST imposed on diary societies.

Areas that lie close to the forest are prone to wild animal attacks. In these attacks, livestock suffer a huge loss. Even last week, tigers have attacked livestock animals in parts of Wayanad. People of Idukki, especially farmers, suffer this on a daily basis. There should be some support for them, especially those related to dairying. Otherwise, animal husbandry will cease to be a viable livelihood option for the majority of farmers. I request the Government to create a scheme for helping farmers who have lost their cattle and other livestock to wild animal attacks.

In 2024, the Standing Committee on Agriculture had noted that the full potential of the Indian fisheries sector is yet to be realised due to gaps in: (i) production inputs, (ii) investment, (iii) infrastructure, and (iv) skilled manpower. The sector is also at risk from factors such as overfishing, pollution, disease outbreak, and climate change. The Economic Survey recommended that to increase the income of small farmers they must shift to producing high-value agricultural commodities such as fisheries, poultry, dairy, and buffalo meat. We need to assess whether the Government has formed credible policies to ensure that such a shift is taking place. There is a palpable lack of vision in the budgetary exercise. I request that the House should disapprove this Demand of Grants.

Thank you.

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): There is nothing for fisheries in this Budget, regarding Maharashtra. It is disappointing because many rivers pass through Maharashtra. There are Narmada and Tapi rivers flowing through Maharashtra, and no big projects exist.

Budget has no provisions for manual labour in fisheries and the use of technology is a hindrance. Labour force should be encouraged.

The milk prices have not been in control. The milk production has not increased in the country.

There should be a veterinary hospital in every village of the country.

Dairy plants, including in Maharashtra, have been shut down in many parts of India, which need to be revived.

More budget for animal husbandry and dairy farming is needed as this will increase employment.

Stray animals should not be ignored and should be protected, especially cows. Due to stray animals, many accidents happen on the highways etc. At least, one *gaushala* should be sanctioned in every village. Mobile ambulance services should be there for such stray animals.

In Maharashtra, vaccination of animals has become a priority. Lumpy skin disease was a major problem for many farmers. There should be encouragement of organic fertilisers instead of chemical fertilisers which ultimately harm animals.

Many insurance claims for death of animals are denied or refused. The insurance claims should be sped up and process made smooth.

There should be public water drinking body for animals so that they do not suffer from heatstroke and dehydration.

DR. ANGOMCHA BIMOL AKOIJAM (INNER MANIPUR): This is to request the Union Government to establish a centrally run Institute of Veterinary and Animal Sciences under the Government of India in the State of Manipur.

It must be noted that despite home to numerous rare species such as the endangered animal like sangai and rare breed like pony, there is not a single veterinary institute in the State.

श्री रोडमल नागर (**राजगढ़**) : सभापति महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी और पशुधन क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण आय में वृद्धि करने तथा कृषि विविधीकरण का समर्थन करने में पशुपालन के महत्व पर जोर दिया गया है । पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रति पशु उत्पादकता में सुधार के लिये पिछले दस वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं । पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है । यह वर्ष 2014-15 से 2023-24 के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से आगे बढ़ा है । कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्द्धन (स्थिर कीमतों पर) 24 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 31 प्रतिशत हो गया है ।

महोदय, डेयरी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिल रहा है । भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है । पिछले आठ वर्षों में दूध उत्पादन में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023-24 में लगभग 225 मिलियन टन तक पहुँच गया है ।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रेरणा से हमने भी एक नवाचार किया था । वर्ष 2017 में 12 समूह की बहनों के साथ एफ.पी.ओ. के अन्तर्गत मालव डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी बनाई । 12 महिलाओं से शुरू होकर आज उसमें 37,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं । उस समय मात्र 21-22 लीटर दूध से शुरू हुआ था, पर आज 45,000 लीटर दूध है और उनका टर्न ओवर 85 करोड़ रुपये का है ।

महोदय, देश में पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन में 1.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है । राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 5 करोड़ 71 लाख से अधिक पशुओं को शामिल किया गया, जिससे 3 करोड़ 74 लाख किसानों को लाभ हुआ है ।

लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन में बछिया पैदा करने के लिये 90 प्रतिशत सटीकता के साथ लिंग वर्गीकृत वीर्य का समावेश किया गया है । केवल बछिया पैदा होने से 90 प्रतिशत की सटीकता के साथ देश में दूध उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुना करने में मदद मिलेगी । डीएनए आधारित जीनोमिक चयन विशिष्ट देशी नस्लों के चयन के लिये पशुओं की जीनोटाइपिंग व्यवस्था की गयी है । पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता, विशिष्ट पहचान लेबल टैग का उपयोग करके 53 करोड़ 50 लाख जानवरों की पहचान करके पंजीकरण किया है । राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के माध्यम से पशुधन उत्पादकता बढ़ाकर बीमारियों को नियंत्रित करने और घरेलू तथा निर्यात बाज़ारों के लिये गुणवत्ता सुनिश्चित कर अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है । बात चाहे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पोल्ट्री फार्म, भेड़ एवं बकरी नस्ल गुणन फार्म, एवं चारा इकाइयों की स्थापना के लिये व्यक्तियों, एफ.पी.ओ. और अन्य को प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करने की हो या डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता देकर प्रतिकूल बाज़ार स्थितियों या

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान डेयरी सहकारी समितियों की सहायता के लिये सॉफ्ट कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने एवं नस्ल गुणन फार्म की स्थापना के तहत निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए किया है ।

15.00 hrs

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष का उपयोग दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढाँचे का निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु किया जा रहा है ।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि से डेयरी एवं पशु चारा संयंत्र एवं नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया है ।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ पशुओं के कान में टैग लगाए गए हैं ।

खुरपका और मुँहपका रोग टीकाकरण ? दूसरे दौर में 24 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया है । तीसरे दौर में लगभग 5 करोड़ पशुओं का टीकारण किया गया है । ब्रुसेला टीकाकरण ? लगभग ढाई करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया है । टीकाकरण कर के सरकार ने पशु स्वास्थ्य के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाया है ।

सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ भी स्थापित की हैं । डेयरी किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों में पशुपालक किसानों के लिये लगभग 27 लाख से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को स्वीकृति देकर आर्थिक रूप से पशुपालकों को समृद्धि देने का प्रयास किया है ।

महोदय, इस क्षेत्र में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं । पशु चिकित्सा सेवाओं और बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने, टीकाकरण कार्यक्रमों एवं नियमित स्वास्थ्य जाँच को बढ़ावा दिए जाने तथा पशुधन के रोग का शीघ्रता से पता लगाने के लिये प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता है । करना चाहिए । साथ ही, जो आवारा पशु होते हैं, उनके लिए कोई बड़े केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए । हमने मध्य प्रदेश में, अपने क्षेत्र में दो हज़ार एकड़ में एक गौ-अभ्यारण्य विकसित किया है । जिसमें पंचगव्य को आधार बना कर विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है ।

उच्च गुणवत्ता वाली चारा फसलों की खेती को बढ़ावा देकर हाइड्रोपोनिक्स तथा साइलेज उत्पादन जैसी आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहित करने के साथ गुणवत्ता युक्त चारे की निरंतर आपूर्ति के लिये चारा प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने एवं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से पोषक तत्त्वों से भरपूर जल का उपयोग करके मृदा रहित कृषि विधि से साइलेज उत्पादन में पशुधन के चारे के लिये उच्च नमी वाला चारा फसलों को किण्वित और संरक्षित करने की आवश्यकता है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि पशुधन फार्मों, डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों के साथ पशु चिकित्सालयों का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण; उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर तथा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके सहायक नीतियाँ के साथ उन्हें लागू करें, जिससे पशुपालन एवं डेयरी उद्योग में रोजगार एवं निवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।

धन्यवाद ।

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I stand before this esteemed House to address the pressing issues and concerns regarding the Demands for Grants under the control of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for 2024-25.

Today, I bring to your attention the urgent needs of the fishermen of my Constituency, Kanyakumari, a region blessed with a diverse and rich maritime heritage. The fishing community here, spanning 48 villages along a 72-kilometre coastline, is integral not only to our local economy but also to our national food security.

Sir, Kanyakumari?s coastline is increasingly vulnerable to sea erosion, which threatens the safety and livelihoods of the people of our fishing villages. To safeguard these communities, I urge the allocation of

additional funds for the construction of permanent breakwater, groyne walls and retaining walls along the coastline. This infrastructure is essential to protect against environmental damage. Furthermore, establishing watch towers, a modern coast guard station, and enhancing coastal security measures will improve both safety and communication. There is also a need to set up a heliport in Kanyakumari and introduce sea ambulances for emergency assistance to fishermen in distress.

Sir, currently, the compensation for deceased or missing fishermen is accessible only after a distressing delay of at least seven years. This prolonged process adds to the suffering of the grieving families. I propose the formation of a fact-finding committee to expedite this process, ensuring death certificates to be issued within three months. Furthermore, I propose to provide a compensation amount of Rs. 10 lakh to the families of the deceased fishermen.

Sir, many fishermen lack essential social security benefits, health insurance and pension schemes. This financial instability exacerbates their vulnerability, especially in cases of injury or illness. So, I urge the Government to implement a monthly pension scheme for fishermen aged 60 and above ensuring their financial security.

Sir, the fluctuating fish prices, overfishing and competition, pose significant economic challenges. We need to provide a fixed daily compensation to be enhanced during periods when fishermen are unable to go to the sea due to the rough weather or fishing bans. Additionally, increase in subsidized quantity of kerosene and diesel will help them eliminate their operation costs.

Sir, in order to improve connectivity, Kanyakumari needs infrastructure development like a bridge between Thengai Pattinam and Iraimanthurai. Thengai Pattinam Fishing Harbour construction work should be speeded up. There is an urgent need for upgradation of the road from Neerodi to Arockiapuram. The cold storage systems should be established in all fishing villages. The fisheries office cum skill development training centre should be established in Kanyakumari district. Construction of fish landing centres in all fishing villages should be done.

Sir, Kanyakumari is known for its tourism. There is a huge scope for coastal tourism in Bay of Bengal, Indian Ocean, and Arabian Sea. I would humbly request the Government to develop a coastal stretch from Arockiapuram to Neerodi coastal village in Kanyakumari. The fishing harbour at Colachel and Muttom should be extended, and construction of new fishing harbour at Vaniyakudi should be started immediately.

Sir, I urge the Government to establish a dedicated Ministry for Fisheries. This will ensure that the distinct needs of the fishing community are addressed with focussed attention. I also recommend the formation of a Coordination Committee which would consist of Members of Parliament from coastal regions. This Coordination Committee would help in addressing the complex issues of arrest of fishermen and boat seizures by neighbouring countries. This Committee would also help in resolving disputes diplomatically and expedite court cases resolution. Establishment of fishing colleges, specialised cancer hospitals, sports villages within the fishing community is the need of the hour.

Sir, now I would like to say a few words about Budget allocation. The fisherfolk?s needs have been neglected. Oceans and water bodies are being exploited. There is a lack of upskilling provisions, and there is inadequate support for women. There are no provisions for the inclusion or skill enhancement of women workers in the fisheries sector, where their presence is minimal, but critical.

Sir, there is a significant delay in processing of claims of fishermen. Only 86 of 305 claims have been settled. The development of backwater aquaculture is below target. Only 52 hectares are cultivated against 1300 acres.

Sir, I urge the Government to take immediate action to secure the release of 70 Tamil Nadu fishermen and 176 fishing boats detained in Sri Lankan custody. Seven Tamil Nadu fishermen are also held in Pakistan.

Sir, I acknowledge the Government?s effort to boost the fisheries sector through increased funding and strategic initiatives. However, we urge the Government to ensure that these measures are implemented effectively and transparently. The focus must be on translating budgetary allocation into real benefits for the sector and the people who depend on it. I call for a detailed action plan, a regular progress report to hold the Government accountable for the promises made.

Thank you, Sir.

श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) : सभापति महोदय, मैं आज पशुपालन, मत्स्यपालन और डेयरी विभाग के लिए वर्ष 2024-2025 के बजट में अनुदानो की मांगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ । यह विभाग हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है । पशुपालन और डेयरी उद्योग न केवल किसानों की आय में वृद्धि कर रहा है, बल्कि राष्ट्र की पोषण सुरक्षा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है ।

सभापति महोदय, मैं खगड़िया लोक सभा क्षेत्र से आता हूं । मेरे लोक सभा क्षेत्र की एक बड़ी आबादी कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन करती है । बिहार और देश के विकास में इन क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है । इस क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए सरकार ने Department of Fisheries को 2,616 करोड़ रुपये और Department of Animal Husbandry and Dairying को 4,521 करोड़ रूपये दिए हैं । यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ही बिहार के अभिभावक आदरणीय राजीव रंजन सिंह जी को दी गई है । इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ ।

महोदय, इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं । लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 2,465 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य सरकारों को टिकाऊ पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 370 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो दूध की प्रोसेसिंग और चिलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और गांव स्तर पर मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग उपकरणों के लिए है । राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को वैज्ञानिक और समग्र तरीके से करना है । डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए 371 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न दुग्ध संघों और राज्य दुग्ध संघों को मंजूर परियोजनाओं के लिए वितरित किया जाएगा । इन योजनाओं और परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है ।

महोदय, मैं मंत्रालय से संबंधित कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव है - उन्नत नस्लों का प्रचार और प्रसार । भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन हम अभी भी दुग्ध उत्पादन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं । वर्ष 2023-24 में भारत ने लगभग 220 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया । मेरा सुझाव है कि उन्नत नस्लों जैसे फ्रीजियन, जर्सी और साहीवाल को बढ़ावा देने के लिए विशेष नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं । इन नस्लों के लिए विशेष प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार अभियानों का आयोजन किया जाए ।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है - आधुनिक तकनीकों का उपयोग । हाल ही में, भारत में दुग्ध उत्पादन में स्वचालित उपकरणों की कमी का सामना देखा गया है । केवल 20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक ही दूध निकालने की मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अन्य 80 प्रतिशत पारम्परिक विधियों पर अब भी निर्भर हैं । सरकार को स्वचालित दूध निकालने की मशीनों, दूध परीक्षण उपकरणों और अन्य आधुनिक तकनीकों को सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए । इसके लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की जाए, जिससे छोटे किसानों को भी इन उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित हो सके ।

महोदय, मेरा तीसरा सुझाव है ? पशु स्वास्थ्य और आहार प्रबंधन । भारत में दुग्ध उत्पादन में पशु स्वास्थ्य और आहार प्रबंधन की स्थिति चिंताजनक है । वर्ष 2023 में पशुओं में होने वाली बीमारियों की वजह से लगभग 15 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन प्रभावित हुआ है । नियमित पशु चिकित्सा जांच, टीकाकरण कार्यक्रम और बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार को एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए । पशुपालकों को आहार प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने की कार्यशालाएं चलानी चाहिए ।

मेरा अगला सुझाव है ? नवीन तकनीकों को अपनाना । भारत में मछली पालन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का उपयोग देखा गया है । वर्ष 2024 में मछली पालन के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग केवल 25 प्रतिशत मछली पालकों के द्वारा किया गया है । मछली पालन के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

मेरा अंतिम सुझाव है ? मछली पालन में प्रशिक्षण और शिक्षा । मछली पालन के क्षेत्र में किसानों को आवश्यक प्रशक्षिण की कमी है । केवल 30 प्रतिशत मछली पालक ही सही प्रबंधन विधियों और आहार प्रबंधन से परिचित हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए प्रस्तावित बजट न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी आवश्यक है । हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए इस बजट का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है ।

इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं इन अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं ।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Hon. Chairperson, Sir, for the financial year 2024-25, the Animal Husbandry and Dairy Development Department received an increased allocation of Rs. 4,931 crore. Maintaining this funding is essential for improving disease control and competitiveness, diary exports and milk productivity. The Department of Fisheries? Budget has increased to Rs. 2,616 crore despite the Standing Committee Report highlighting the gaps in production, investment, infrastructure and expertise that limit the sector?s potential. The blue economy is particularly vulnerable. It depends on climate change and geopolitical uncertainties.

It is important to develop some measures to store products and ensure cold chain facilities. Hence, I request the hon. Minister to sanction more funds to Andhra Pradesh, which is a major contributor to marine exports and shrimp production.

The second point is this. As per the Standing Committee Report, only three fish landing centres were being developed in the year 2022-23. We made several representations to the Government of India to develop a fish landing centre in the Tirupati Parliamentary Constituency, but the Government sanctioned a fish landing centre at Pudirayadoruvu. The land survey and site allotment were completed but the grounding of work has not yet started. I request the Minister to release the sanctioned funds for early grounding and completion of the fish landing centre at Tirupati Parliamentary Constituency.

My third point is this. Pulicat Lake is the second largest brackish water lake next to the Chilika Lake with an extent of 461 sq. kms., out of which 400 sq. kms. falls in Andhra Pradesh and 61 sq. kms. falls in the State of Tamil Nadu. This is a livelihood for 20,000 fishermen families which have been subsisting exclusively on fishing on this lake for generations. The southern portion of the Pulicat in Tamil Nadu is quite deeper and water remains throughout the year, whereas the northern portion of the Andhra Pradesh area is shallow with a depth below 0.5 metres due to sandbar formation across the mouth getting dried up for a major period of the year. These 20,000 fishermen families? livelihoods are under threat due to the depletion of fishery resources in the lake and the siltation of navigable channels. We represented several times to the Union

Government for opening the sea mouth of the Pulicat Lake. Finally, the Union Government approved Rs. 97 crore under the Sagarmala Project for opening the sea mouth of the Pulicat Lake.

I urge the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and the Ministry of Ports, Shipping and Waterways to consider the immediate need and release grants to open the sea mouth of Pulicat Lake at Kondurupalem and Pudirayadoruvu areas.

The fourth point is this. The Pulicat Lake is spread across seven *mandals* in my parliamentary constituency. Fishermen residing in this region face considerable challenges due to lack of efficient road connectivity. This is hampering the residents? access to educational institutions, Government services, and other critical amenities, thereby affecting their overall quality of life. In this regard, I request the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the Ministry of Road Transport and Highways, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to accord permission for the development of road connectivity in the Pulicat Lake region for hassle-free movement and overall development of the fishermen community.

Sir, my fifth point is this. The PMMSY aimed at sustainable and responsible development of the fisheries sector received a budgetary allocation of Rs. 2,352 crore, up from financial year 2024 Budget Estimate of Rs. 2,000 crore, a 17.6 per cent increase. However, as PMMSY enters its final year of implementation, the Department of Fisheries needs to expedite and overcome several challenges in the effective implementation of the scheme.

Tirupati Parliamentary Constituency has an 80-kilometre coastline, with local fishermen from very poor backgrounds relying on traditional fishing methods and motor boats with 5HP engines. Currently, under the PMMSY Scheme, only 40 per cent subsidy is provided for purchasing boats and nets. This level of subsidy places a significant financial burden on the fishermen community. To alleviate this burden and support their livelihoods more effectively, it is essential to increase the subsidy to 75 per cent.

The fisheries sector also faces gaps in infrastructure, technology, skilled manpower and extension services. There is also limited financial inclusion and social protection for fishermen with inadequate access to credit and insurance. Additionally, there is insufficient awareness and compliance with regulatory frameworks impacting the sector?s sustainability and competitiveness.

Finally, I would like to request the hon. Minister to implement the suggestions shared for fisheries, livestock and dairy sectors. Thank you, Sir.

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

When we talk about fishermen, we feel sympathetic towards them and we must be sympathetic towards them also. It is because of the hard work that they do, and they have 24X7 type of work. The risk factor involved in their work is also there and they have a seasonal kind of a situation. As a result of all these factors they are suffering a lot. Since there is not much time for me, I would like to mention a few things in brief.

The first threat is regarding the international maritime boundary line and its violations. Everybody knows that innocent fishermen are unnecessarily brought into various difficulties. I hope that the hon. Minister is fully aware of all these things and will take appropriate action at the higher levels in this regard also.

There is another threat now hanging as the sword of Damocles, that is subsidy challenges. Internationally, there is pressure on the part of WTO to reduce or eliminate subsidies provided to the Indian fishermen. We can very well imagine if subsidy is also reduced or eradicated, then what will be their situation. So, I would humbly request the Government not to yield to that kind of pressure. We have to be sympathetic to fishermen and should not agree to these kinds of things whatever maybe the pressure.

Now, I would like to mention about the economic empowerment of the fishermen. There are different schemes for them, but their implementation is very poor. As regards the Sagar Parikrama Scheme, *prima facie*, it seems a very good scheme, but as far as its implementation is concerned, it is very poor. I would humbly request the hon. Minister to examine it and revive the scheme or kindly give special attention to whatever may be the shortcomings in the scheme and to get it resolved as well.

There is another threat with regard to shrimp export and we are in the forefront of it. We export to America and for the last five years America has banned receiving our exported shrimps. The reason given for it is that the turtles are not given proper consideration by the Government. I am not against making any law, but there is no reasonable argument on the side of the US in banning this export. I would humbly request the hon. Minister to intervene in the matter because we all know that export to America is very good for our fishermen. Our shrimp export was banned in 2019 and it is five years since this ban came into force. In 2023-2024, Rs. 60.52 crore worth of marine products were exported out of which 60 per cent was shrimp. So, it was a very good thing for us. We are having very good diplomatic relations with everybody including America. So, kindly examine where the hurdle lies in resolving it. I would like to say that we must take a firm stand with America and convince them about the fact that we are not disturbing the turtles.

Sir, imparting education to fishermen is very important. I would request the Government to start more educational institutions and arrange for a special type of concession concerning the backwardness of the fishermen in the coastal area.

Infrastructure development exclusively for the coastal area like road, connectivity, fishermen port etc. is very important. The subject of sea erosion used to be dealt with by the Central Government but the Government has transferred the responsibility to the State Government. In my constituency, sea erosion takes place in a big way. The Government must discuss it with the State Government and ensure that the funds are utilised properly with regard to soil erosion.

Lastly, appropriate action should be taken to use funds. You are allocating budget but I would like to ask the Government to make a threadbare analysis of the expenditure as mentioned in the Budget. These are all certain things that need to be taken into consideration.

I hope that the hon. Minister and the Government will be sympathetic to the neglected section of the society.

***m63 श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) :** धन्यवाद माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम मैं विश्व नेता, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ता से प्रयासरत भारत के यशस्वी प्रधान सेवक आदरणीय प्रधान मंत्री जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं । मैं देश के 140 करोड़ लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि एक नकारात्मक, असत्य और भ्रमित करने वाले दुष्प्रचार के बावजूद भी उन्होंने अपने परिश्रमी प्रधान सेवक को तीसरी बार सेवा का अवसर दिया और विकसित भारत बनाने हेतु सही निर्णय लिया ।

महोदय, यह हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है । मेरा संसदीय क्षेत्र आणंद है, सरदार साहब की कर्मभूमि है और अमूल डेयरी की स्थापना भी वहीं हुई थी । सरदार साहब ने ही अमूल डेयरी की स्थापना की थी । मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मुझे लोक सभा में चुनकर भेजा है ।

महोदय, पिछले 10 साल में इस देश ने कई गौरवपूर्ण क्षण देखे हैं । चाहे राम मंदिर निर्माण हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जी 20 का सफल आयोजन एवं अध्यक्षता हो । पिछले दस सालों से देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं जिससे गरीबों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ा है । पूर्व में आपातकाल जैसी विभीषिका झेलने के उपरांत गरीबों को मोदी जी ने विश्वास दिलाया है कि अब लोकतंत्र को कोई भी परिवारवादी पंजा कमजोर नहीं कर पाएगा ।

महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पशुपालन और दुग्ध विभाग भी अपने अब तक के सबसे बेहतरीन समय को देख रहा है एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार का एक महत्वपूर्ण फैक्टर बना हुआ है ।

पशुधन क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक 13.36 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है । कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य संवर्धन कुल योगदान वर्ष 2014-15 में 24.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 30.19 प्रतिशत हो गया है । पशुधन क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 में कुल सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में 5.73 प्रतिशत का योगदान दिया । भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया है । जारी किए गए क्रेडिट कार्ड वाले किसान इसे बैंक में डेबिट कार्ड की तरह उपयोग कर सकते हैं । पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में नामांकित पशुपालकों के लिए प्रति भैंस 60 हजार रुपये और प्रति गाय 40 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध है । क्रेडिट कार्ड धारक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना 1.60 लाख रुपये तक पहुंच सकते हैं ।

महोदय, दूध उत्पादन सबसे बड़ी कृषि वस्तु है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत योगदान देती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है । भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64 प्रतिशत का योगदान देता है । दूध उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 5.85 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है । यह वर्ष 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 230.58 मिलियन टन हो गया है । वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के दौरान विश्व दूध उत्पादन में 0.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन थी, जबकि 2022 में विश्व औसत 322 ग्राम प्रति दिन थी ।

महोदय, देश में आईवीएफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर आज तक कार्यक्रम के तहत स्थानांतरित किए गए 10,331 भ्रूणों और 1621 बछड़ों में से 19,124 जीवनक्षम भ्रूण पैदा किए गए हैं । पशुपालन और डेयरी विभाग ने एनडीडीबी के साथ एक डिजिटल मिशन "राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम)" शुरू किया है । इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, घरेलू और निर्यात बाजारों दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पशुधन और पशुधन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी ।

महोदय, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)" लागू कर रहा है । जुलाई 2021 में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना का पुनर्गठन किया गया । इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाना है, ताकि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक इसका कार्यान्वयन किया जा सके । किसानों को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और उसे मजबूत करना है ।

महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा की मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ, वहां दुग्ध क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी अमूल स्थापित है, इस नाते मेरा अनुभव और विचार है कि पशुपालन क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं और उनसे संबंधित कार्य के बारे में कुछ बिंदुओं पर कार्य हो और अनुदान दिया जाए । आनंद में एनडीडीबी, अमूल और वेटरिनरी कॉलेज होने के कारण आधुनिक तकनीक जैसे सीमेन सेक्सिंग और टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके जिले में प्रति पशु उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । यह कार्य वर्तमान में प्रगति पर है ।

महोदय, एनडीडीबी, अमूल और वेटरिनरी कॉलेज द्वारा राज्य में आधुनिक पशु रोग निदान और पशु पोषण विश्लेषण के लिए एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला की स्थापना आवश्यक है । आनंद और मध्य गुजरात पॉल्ट्री उद्योग के लिए पूरे देश में जाना जाता है । गुजरात में अंडों की कीमत निर्धारण में आनंद जिले का बड़ा योगदान है । दूध की गुणवता और मूल्य निर्धारण के लिए मानक पद्धति विकसित करना भी जरूरी है । इसी तरह से दूध की गुणवत्ता की जांच भी जरूरी है ।

महोदय, पशु अस्पतालों में एक अति आवश्यक जरूरत के बारे में मैं संबंधित विभाग के मंत्री जी से आग्रह करूंगा की अनुदान की व्यवस्था की जाए । पशु अस्पतालों में यदि पशु गंभीर रोग से ग्रसित हो और किसान रुक कर या पशु को भर्ती करके इलाज कराना चाहे तो उस तरह की सुविधा पशु अस्पतालों में नहीं है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा की उसके लिए व्यवस्था की जाए ।

महोदय, अंत में अपने क्षेत्र की एक मांग शिक्षा मंत्रालय से करना चाहूंगा कि मेरा लोक सभा क्षेत्र आनंद, जो लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल जी की कर्मस्थली रही है और महान शिक्षाविद आदरणीय भाइ काका जी और आदरणीय भीखाभाई पटेल जी की जन्म भूमि है, वहां एक कल्चरल सेंटर चालू है, मैं चाहूंगा कि सरकार विद्यानगर में आईआईटी और आईआईएम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोले । धन्यवाद ।

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले (जालना) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे इस बजट में कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले एनिमल हसबेंडरी और फिशरीज विभाग पर अपनी बात रखने का मौका दिया । माननीया वित्त मंत्री जी ने कृषि मंत्रालय के अंदर जो बजट पेश किया है, उसमें कुछ जगहों पर बजट में बहुत बड़ी कटौती हुई है । जैसे हमारे 369 करोड़ रुपये डिक्रीज किए गए हैं, जो 64.55 परसेंट के बराबर है । यह एक्चुअल एक्सपेंडिचर वर्ष 2022-23 में हुआ था ।

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा । हमारे एक सहयोगी सदस्य ने ?राष्ट्रीय गोकुल मिशन? की बात कही है । इस वर्ष के बजट में ?राष्ट्रीय गोकुल मिशन? के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है । यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप इस वर्ष ?राष्ट्रीय गोकुल मिशन? में कुछ धनराशि देने वाले या नहीं देने वाले हैं? यदि कुछ देना है, तो मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार, वित्त मंत्री जी एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी से कुछ कहना चाहूंगा । वर्ष 2019-20 और 2022-23 में हमारे देश में राजस्थान से लंपी नामक स्किन बीमारी फैलनी शुरू हुई थी । फिर वह बीमारी पूरे हिन्दुस्तान में फैली । उसमें करीब-करीब 2,00,000 गाय-भैंसों की मृत्यु हुई थी । किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कोई भी धनराशि नहीं दी । एक गाय या भैंस की कीमत करीब-करीब 50,000 रुपये होती है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहूंगा । महाराष्ट्र में खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की कमी के कारण वहां के किसानों को हमेशा अकाल का सामना करना पड़ता है । उसकी वजह से यदि किसान आत्महत्या न करे, यदि वह ख़ुदकुशी न करे, हमें उनके लिए दूध (डेयरी) व्यवसाय के माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहिए । यदि उनको कुछ देना है, तो सरकार को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए । सरकार को क्लस्टर जोन का डेवलेपमेंट करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है । हमारे बहुत से सहयोगी सदस्यों ने भी बताया है कि हमारी गायों की जो देशी नस्लें हैं, उसमें उनका विकास हो । हमें क्लस्टर के अंदर सारी चीजें एक ही जगह पर मिलें ।

महोदय, जैसे कि 10 गायें हैं । हमने ?राष्ट्रीय गोकुल मिशन? में 200 गायों के लिए काम किया है । क्या किया है, पता नहीं किसे दिया है? यदि हमारे छोटे किसानों को 10 गायों की एक यूनिट दी जाती, यदि उस क्लस्टर को 10 से 25 गांवों तक बढ़ाया जाए, तो वहां कुछ न कुछ जरूर विकास होगा । उससे हमें किसानों को सारी सुविधाएं देने में आसानी होती है । जैसे आज की तारीख में मैंने आपसे बात की है । मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश कम होने के कारण अकाल पड़ता है । सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की होती है कि फॉडर मैनेजमेंट कैसे हो । उनके खाद के लिए क्या करें? यदि क्लस्टर में किया जाए, तो मैं फॉडर मैनेजमेंट के बारे में एक और बात कहूंगा ।

साइलोज बनाने की जो छोटी-छोटी मशीनें हैं, साइलेज बनाने के लिए जो मशीन होती हैं, यदि हम किसानों को वह मशीनें सब्सिडी पर दें, ताकि वे साइलोज में कुछ प्रिजर्व करके रख सकें । हम मराठी में उसको ?मुरघास? बोलते हैं । उसके लिए बंकर बनाएं, उसके लिए वेल की मशीन दें, ताकि हमेशा के लिए हमारे किसानों की फॉडर की समस्या खत्म हो जाए । जो लोग अकाल की वजह से चिंतित हैं, वे चिंतित नहीं रहेंगे एवं जो लोग आत्महत्या करते हैं, वे आत्महत्या भी नहीं करेंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह बात कहना चाहूंगा ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं दूध एवं किसानों पर पहली बार बोल रहा हूं । मुझे थोड़ा और समय दीजिए । मैं दूध के बारे में यही कहूंगा कि दूध में बहुत बड़ी तादाद में मिलावट होती है, जिसकी वजह से किसानों को दूध के दाम कम मिलते हैं । यदि यह मिलावट रुक जाए, तो किसानों को दूध के अच्छे दाम मिलेंगे । दूसरी बात यह भी है कि दूध में मिलावट के साथ-साथ, हमारी सरकार एक तरफ तो दूध का पाउडर दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है । उसकी वजह से पाउडर प्लांट वाले दूध के दाम कम कर देते हैं ।

सभापति महोदय, अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा में एनडीडीबी और वीएमडीडीबी ने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल लिमिटेड नामक कंपनी से कहा है । मदर डेयरी के साथ एक एग्रीमेंट किया है ।?.(व्यवधान) विदर्भ और मराठवाड़ा में जो जिले हैं, उनमें सभी जिले शामिल नहीं किए हैं । अगर उसके अंदर सारे जिले समाहित हो जाएं, तो हमारा काम हो जाएगा और वह काम और भी अच्छा होगा ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, जो दूध (डेयरी) का बिजनेस है, उसको एक इंट्राप्रेन्योर और इंडस्ट्रियल बेस पर देखा जाए, ताकि आगे चलकर अच्छे से अच्छा काम हो सके ।?(व्यवधान) मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि हमारे पूरे हिन्दुस्तान में कहते हैं कि गाय हमारी माता है । आपने देशी गाय के लिए कोई भी योजना लागू नहीं की है । मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए विनती करना चाहूंगा ।

महोदय, अंत में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गायों के लिए इंश्योरेंस का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।?(व्यवधान) गायों के लिए कोई इंश्योरेंस की योजना लाई जाए ।?(व्यवधान)

श्री अमरा राम (सीकर) : सभापति महोदय, मुझे मछलीपालन, पशुपालन और डेयरी पर चर्चा में भाग लेने का आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, राजस्थान पशुपालन में अग्रणी राज्यों में है । राजस्थान में गाय और बछड़ों के लिए मेले लगते थे, जिनमें हजारों करोड़ रुपये राजस्थान के किसानो को मिलते थे । बछड़ों पर पाबंदी लगाकर, गाय, बछड़ा और उनको पालने वाले किसान को मारने का काम मैं समझता हूं कि इस राजनीति ने किया है ।

महोदय, जहां तक दूध का सवाल है, सबसे अधिक दूध पैदा करने वालों में मैं समझता हूं कि राजस्थान आता है । लेकिन किसान को उसके दूध की लागत की कीमत नहीं मिलती है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि सरकार दूध का लाभकारी मूल्य तय करने का काम करे । फोडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन दूध की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए किसान हतोत्साहित है । किसान को 35 परसेंट इनकम खेती के अलावा दूध और पशुपालन से होती है । दूध और दूध प्रोडक्ट, जैसे- पनीर और मावा, केमिकल से बन रहे हैं । इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा कोशिश करने की आवश्यकता है । फूड एडलट्रेशन की जांच के लिए लैब संभाग मुख्यालय में भी नहीं है । इसलिए लैब की व्यवस्था करायी जानी चाहिए । किसान को पशुपालक को बचाने के लिए दूध और दूध उत्पाद पर आयात टैक्स को बढ़ाने से राजस्थान और देश के किसान को प्रोत्साहन मिलेगा ।

राजस्थान भेड़ और बकरी पालन में देश में अग्रणी है । माईनोरिटी के मुस्लिम इसके व्यापारी हैं और पशु क्रूरता के नाम पर जिस तरह का उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है, वह सही नहीं है । राजस्थान की भेड़ और बकरियां पूरे देश में जाती हैं । भेड़ की ऊन को बेचने पर जो कीमत मिलती थी, वह आज की तारीख में न के बराबर हो गयी है । बाहर से ऊन आयात की जाती है, लेकिन अगर हमारी स्वदेशी ऊन को प्रोत्साहन देने का काम किया जाना चाहिए । अगर किसान खुशहाल होगा तो खेती के अलावा दूध और पशुपालन से होगा । अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा । धन्यवाद ।

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आपने मुझे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी पर चर्चा में भाग लेने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

महोदय, वर्ष 2023-24 के संशोधित बजट में विभाग के लिए 59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे । वर्ष 2024-25 के बजट में इसे घटाकर 51.03 करोड़ कर दिया गया है । यह महत्वूर्ण कमी इस मंत्रालय की कार्यक्षमता को निश्चित तौर पर बाधित करेगा । डेयरी विकास के बजट को 506.99 करोड़ रुपये से घटाकर 377 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह कटौती डेयरी उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाएगी, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका का आधार है । नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का बजट वर्ष 2023-24 में 410 करोड़ रुपये का था । उस बजट को घटाकर 324 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यह मिशन पशुधन की उत्पादकता और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है । यह घटाव निश्चित तौर पर इसे प्रभावित करेगा ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि ऐसे छोटे-छोटे पशुपालक जो ऋण लेकर और अपने स्तर पर गाय, भैंस या बकरी की खरीद करते हैं, चूँकि इसके साथ बहुत बड़ा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है या पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है । चूँकि पशुपालन में जितने भी छोटे किसान हैं, वे उससे जुड़े हुए हैं ।

सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग होगी कि वह ऐसे छोटे पशुपालकों को, जो ऋण लेकर या अपने स्तर पर पशु को रखकर दूध की उत्पादकता से अपना स्वरोजगार करते हैं, अगर उनके पशुओं के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उन्होंने जो ऋण ले रखा है, उनका वह ऋण माफ हो तथा जिस किसान ने ऋण लेकर पशु नहीं खरीदे हैं, अगर उनके पशुओं के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करे ।

सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय जी से एक आग्रह है । चूँकि दूध उत्पादन एक बहुत बड़ा उद्योग है । निश्चित तौर पर इससे बहुत छोटे-छोटे परिवार जुड़े हुए हैं । कोई भी छोटा परिवार यह चाहता है कि हम गाय या भैंस ले लें और दूध बेचकर अपना जीवन यापन करें और अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करे । अगर ऐसी स्थिति में कोई विपदा आ जाती है तो उनका पैसा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है और उनको सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल पाती है ।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि बिहार में औरंगाबाद जिला है, वहां जिला पशु चिकित्सालय की स्थिति बहुत ही दयनीय है । जब चिकित्सालय ही बढ़िया नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे पशुओं को क्षति पहुंचेगी । इसकी प्रखण्ड स्तर पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इसके साथ ही हमें कृषि के क्षेत्र में सुचारू रूप से सिंचाई करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

सभापति महोदय, मैं छोटे पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, ठोस योजना बनाए और पशुपालन को प्रोत्साहित करे तथा इसे प्रोत्साहित करके इसका प्रचार-प्रसार करे, ताकि हमारे छोटे किसान इस चीज से जुड़ सके तथा इससे जुड़कर दुध उत्पादन की स्थिति और बेहतर हो ।

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं सबसे पहले तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात को भलीभांति समझा कि अगर किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, किसानों की समृद्धि को बढ़ाना है तो अनाज उत्पादन के अलावा पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा । इसलिए वर्ष 2019 में उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का गठन किया । उसके बाद से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए ।

सभापति महोदय, आज जो लोग किसानों की बात करते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा । इस देश में 40-45 साल पहले दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं । पहली घटना यह थी कि हमने भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए शीत क्षेत्र की जर्सी गायों का आयात किया और उसी कालखंड में ब्राजील हमारे यहां से गिर नस्ल लेकर गया, इजरायल साहीवाल लेकर गया । नस्ल संवर्धन के बाद आज ब्राजील में गिर गाय से 40-50 लीटर दूध का उत्पादन

होता है । इजरायल में शाहीवाल गाय से लगभग 40 लीटर दूध का उत्पादन होता है । हमने अपने देसी नस्लों का संवर्धन नहीं किया । पता नहीं किन कारणों से, किन गिरोहों के दबाव में आकर हमने जर्सी गायों का आयात किया ।

महोदय, मैं बड़े-बड़े फार्मों को नहीं जानता हूं । मैं गांव-किसानी से जुड़ा हुआ आदमी हूं । हमारे यहां 20 वर्ष पहले हर घर में एक जर्सी गाय दिखती थी । आज किसानों के खूंटों में जर्सी गाय का नाश हो गया, सर्वनाश हो गया, उनके पास एक भी जर्सी गाय नहीं है । जीरो डिग्री सेल्सियस में पलने वाली गाय, हमारे गांव के 45 डिग्री और 48 डिग्री सेल्सियस की धूप में हांफती हैं, उनके फेफड़े फट गए, वे मर गईं, वंश का नाश हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस के लोग, जिनकी सरकारों ने जर्सी गायों का आयात किया, उन लोगों का यह दोष है । उन लोगों ने हिन्दुस्तान में जर्सी नस्ल ला कर, गौवंश का नाश किया । हमारे यहां के गौवंश को निराश्रित छोड़ दिया गया ।

महोदय, यह मोदी जी की सरकार की दूरदृष्टि है कि उन्होंने देसी नस्लों के उत्पादन के लिए, उनके संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है । आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे गोकुल मिशन हो, कामधेनु मिशन हो, डेयरी संस्करण-प्रसंस्करण के मामले हों, डीएनए आधारित जैविक चयन का मामला हो, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान हो, आईबीपीएम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का मामला हो, लिंग चयनित वीर्य उत्पादन का मामला हो, पशु की पहचान, पता लगाने का मामला हो, वंश परिक्षण और नस्ल चयन का मामला हो, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के माध्यम से पशुओं की गुणवत्ता सुधारने का मामला हो या गाय के नस्ल के गुणन फार्म का मामला हो, इन सारी नीतियों का संचालन करके देसी नस्लों को, दुधारू पशुओं के संवर्धन को बढ़ावा दिया गया है । यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि जिन पशुओं से दूध की उत्पादकता छः महीने में 300 लीटर, 400 लीटर या 500 लीटर होती है, उसे बढ़ा कर 4000 लीटर प्रति दूध स्रवण वर्ष के रूप में लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस तरह से हम यह देखें कि आज मोदी जी की सरकार दूध उत्पादन के क्षेत्र में किसानों की मदद करने के लिए किस तरह की मदद कर रही है । पशुधन के मामले में चाहे वह बकरी पालन का मामला हो, सुअर पालन का मामला हो, ऊंट पालन का मामला हो, भेड़ पालन का मामला हो या ऊन उत्पादन का मामला हो, इन सारे मामलों में जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में बताने के लिए समय नहीं है । अभी आप घंटी बजाएंगे । मैं संक्षेप में इन सारी योजनाओं के बारे में बता रहा हूं ।? (व्यवधान) बृजमोहन जी ठीक कह रहे हैं कि नस्ल परिवर्तन हो गया है, लेकिन अक्ल परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह दिक्कत है । नस्ल परिवर्तित हो गई है, लेकिन अभी अक्ल का परिवर्तन होना बाकी है ।?(व्यवधान)

महोदय, मैं भैंसों के बारे में भी कहना चाहता था, लेकिन आपका चेहरा देख कर लग रहा है कि हमारी भैंस गई पानी में । आवारा पशु, निराश्रित पशु एक बहुत बड़ी समस्या है । मैं इस संबंध में बात करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकारें गौशालाओं का निर्माण कर रही हैं । गौशालाओं में उन गौवंशों को रखा जा रहा है, लेकिन यह पूरी मदद सरकारी है और सरकारी तंत्र के माध्यम से इसका समाधान नहीं निकलेगा । ये गायें लाखों वर्षों से हमारे पुरखों के साथ रहती आई हैं । इनके लिए जनमानस को श्रम, पैसा, उनकी देख-रेख और सरकारी सुविधाओं सबको मिला कर, एक समन्वित प्रयास के माध्यम से इन देसी नस्लों का वहीं पर गर्भाधान कराया जाए । जिस तरह से गिर, साहीवाल वगैरह व दूसरी देशी नस्लों की वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसी तरह से ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री जनार्दन मिश्रा : उसी तरह से इन गौशालाओं में रहने वाली बेसहारा गायों की नस्लों में सुधार और इनके परिपोषण का काम होना चाहिए । किसान परेशान है और खेती बर्बाद हो रही है । किसान खेती के लिए दिन-रात इनको डंडा मारता है और ये इनको मारते हैं । अभी एक सदस्य कह रहे थे कि बैल भी मारते हैं तो वह मारेंगे ही । हम उनको मारेंगे तो वह हमको थोड़े ही छोड़ेंगे । इसलिए समन्वित प्रयास के माध्यम से इस समस्या के हल का प्रयास होना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से इस विभाग को संभालने का जिम्मा लिया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय ललन सिंह जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी का चतुर्मुखी विकास होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय भारत ।

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के एक जीवंत कथन से करना चाहती हूँ, जो आज भी सार्थक है: ?किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के पशुओं के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं ।?

भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 70 से 80% आबादी पशुपालन एवं कृषि पर निर्भर करती है । केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में पशुपालन एवं मत्स्यपालन में लगभग सात हजार एक सौ अड़तीस करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसमें पशुधन, स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2024-25 में 2,465 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा व स्वास्थ्य लाभ के लिए है । वर्ष 2023 में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ टीकाकरण के पहले दौर में कोई टीकाकरण नहीं हुआ था । इसी तरह बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में ब्रुसेला के खिलाफ कोई टीकाकरण नहीं हुआ था, जिसका मूल कारण मानव संसाधन की कमी है ।

इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में भारत में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग का प्रकोप हुआ । इसके कारण हमारे बहुत सारे मवेशी मारे गए । विभाग को शारीरिक टीकाकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जनशक्ति की भर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए । विभाग ने वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 700 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा है, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 19% कम है, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफी नहीं है ।

भारतीय गोवंश के विकास के लिए Assisted Reproductive Technology (ART) का विकास एवं उपयोग देश के हर राज्य में किया जाना चाहिए । वर्तमान में यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उतराखंड में ही है । यहीं Embryo Transfer Technology (ETT) और Multiple Ovulation Transfer Technology (MOET) का विकास एवं प्रसार हो, जिससे भारतीय गोवंश की नस्ल सुधार में गति मिलेगी । जिस प्रकार से ब्राजील में भारतीय गिर गाय की मिल्किंग क्षमता 40 से 50 लीटर कर ली गयी है और भारत में अब तक नहीं हुई है । In-Vitro Fertilization (IVF) का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए एवं Sex sorted Semen लैब में विकसित होना चाहिए । ड्वार्फ गोवंश पुंगनर (आंध्र प्रदेश), वेचूर (केरल), कोसाली (छत्तीसगढ़), जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनका संरक्षण आवश्यक हैं । इस संदर्भ में बजट में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है ।

देश में पशु चिकित्सालयों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है । ऐसे समस्त पशु चिकित्सालयों का उन्नयन एवं पशु चिकित्सकों की नियुक्ति के साथ-साथ पर्याप्त दवाईयां और संसाधन को लेकर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में 25% हिस्सा है । वर्ष 2016-17 और वर्ष 2022-23 के बीच भारत का दूध उत्पादन 5.7% की वार्षिक दर से बढ़ा । हालांकि दूध उत्पादन में साल-दर-साल वृद्धि वर्ष 2018-19 में 6.46% तक हुई और वर्ष 2022-23 में वह घटकर 3.8% हो गई । इससे प्रतीत होता है कि पशु आहार की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में कमी आई है ।

16.00 hrs

इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में भारत ने 13,261 करोड़ रुपए के पशुधन उत्पादों का आयात किया, जिसमें लगभग आधा एनिमल फॉडर और फीड था । यानी पशु आहार के लिए सरकार दूसरे देशों पर निर्भर है, जिसकी गुणवत्ता भी कम है । आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत दूसरे देशों से पशु आहार ले रहा है, यह आश्चर्यजनक बात है । सरकार को चाहिए कि पशु पालकों को सही दर पर उचित गुणवत्ता का पशु आहार- चारा और दाना उपलब्ध कराए, जिसकी पूर्ति में अभी वह असमर्थ है ।

पशुपालन और मत्स्य पालन में जहां करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन कहीं पर भी यह बताने की कोशिश नहीं है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों, पशुओं, किसानों के

खेत-खलिहान को नुकसान पहुंचा रहे पशुओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है । सडकों पर घूम रहे पशुओं, जिनकी वजह से सडक़ दुर्घटनाओं में मानव और पशु अपनी जान गँवा रहे इसलिए सभी राज्यों में निराश्रित पशुओं के लिए शेल्टर्स बनाए जाने का प्रावधान होना चाहिए ।

मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार थी, तो पशुपालन में उनको संरक्षण देने के लिए गौठान बनवाए गए थे, लेकिन सरकार बदलते ही वे बंद हो गए ।

16.02 hrs

(Shri Jagdambika Pal *in the Chair*)

इसके अलावा, आये दिन गौ वंशों की तस्करी, उन्हें बेचने, कंपनियों से चंदा लेना, हमारे मन को विचलित करती है । गौवंश की रक्षा के लिए सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन मामलों से बयाँ होती है । मेरा आग्रह है कि कानून का कठोरता से पालन किया जाए ।

वर्ष 2022-23 में, भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मछली उत्पादक था और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 8% थी । समिति ने 2022 में कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 2022-23 में केवल 52 हेक्टेयर भूमि खारे पानी की जलीय कृषि के अंतर्गत थी, जबकि इसमें लक्ष्य 1,300 हेक्टेयर था । पशु पालन के साथ-साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हितग्राहियों और छोटे-छोटे तालाबों में मत्स्य पालन कर जीविकोपार्जन कर रहे मछुआरों के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है ।

देश के अर्थव्यवस्था की प्राथमिक इकाई गांव के लोगों के रोजगार से जुड़े पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से, जिस तरह का लाभ और आर्थिक उत्थान होना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों को इन योजनाओं से जोडकर स्वावलंबी बनाना चाहिए, इस दिशा में, अधिकांश क्षेत्रों में यह नगण्य के बराबर है ।

अंत में, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ । छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जीवनदायिनी मिनीमाता हसदेव बांगो बांध व उसके पानी से विद्युत संयंत्रों की सांस तो चल रही है और छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि अन्य प्रदेशों को भी कोरबा रोशन कर रही है । लेकिन मिनीमाता बांगो बांध व छत्तीसगढ़ सहित देशभर के जलाशयों से प्रभावित व आसपास के किसानों व ग्रामीणों को मत्स्य पालन, झींगा पालन व उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कार्ययोजना तैयार करने की जरूरत है, जो इसमें नहीं दिख रही है, जिससे बांध के प्रभावितों को लाभ मिल सके ।

धन्यवाद ।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, there is a point of information.

माननीय सभापति : आप पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं?

क्या पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, our neighbouring country, Bangladesh is under military rule. It is being taken over. ? (*Interruptions*) Their Prime Minister has ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप दूसरे देश का संज्ञान न लें ।

श्री राम प्रसाद चौधरी ।

? (व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): The External Affairs Minister is there. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपकी बात आ गई है ।

श्री राम प्रसाद चौधरी ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Owaisi *Saheb,* please do not disturb.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Premachandran ji, you are quite aware of the rules.

? (*Interruptions*)

SHRI S. SUPONGMEREN JAMIR (NAGALAND): I would request the hon. Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to establish a fish seed production centre, and provide one Animal Husbandry College for the State of Nagaland.

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying has been allocated Rs. 4,521.24 crore in the general Budget 2024-25 which is not sufficient for comprehensive development of Animal Husbandry sector. An allocation to the tune of Rs. 2,616.44 crore in 2024-25 is also not sufficient keeping in view the vast scope of fishing in the country which is considered as the sunrise sector of Indian economy. India has nine coastal States and one of them is the State of Tamil Nadu which requires higher allocation of funds for inclusive and holistic development of the sector. PM Matsya Sampada Yojana needs additional requirement of funds to enhance production and productivity of fish.

Similarly, I appeal for setting up of Animal Health Institute, Small Livestock Institute, Breed Improvement Institute and Centre of Excellence for Animal Husbandry in the State of Tamil Nadu, particularly, in my Parliamentary constituency, Tiruvannamalai, Tamil Nadu.

I further request for higher allocation and effective implementation of Rashtriya Gokul Mission, Dairy Development, Livestock Health and Disease Control Programmes in Tamil Nadu and allocation of infrastructure development fund in the State of Tamil Nadu to focus on processing and chilling infrastructure, milk adulteration testing equipment at village level and also for supporting working capital requirements of State Co-operative Dairy Federation.

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय की अनुदान मांगो पर मैं अपने विचार रखता हूँ ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में मत्स्यपालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के लिए 7 हजार 137 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए 2 हजार 352 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

पशुपालन और डेयरी विभाग को 2023-24 के बजट की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4 हजार 521 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि मत्स्य पालन विभाग के लिए 54 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि के साथ 2 हजार 916 करोड़ का आवंटन किया गया है ।

भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में, जब सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी विभाग और मत्स्यपालन विभाग कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग थे, तब इस मंत्रालय का कुल बजट आवंटन मात्र 27 हजार 662 करोड़ रुपये था ।

पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के लघु उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में ऐतिहासिक योजनाओं का क्रियान्वन करते हुए करोड़ों लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध करवाया है ।

वित्त वर्ष 2014-2023 के मध्य भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र 8.9 प्रतिशत वृद्धि की दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी अलग पहचान बना रहा है और बहुत तेज गति से बढ़ रहा है । भारत वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और वर्ष 2023-24 में लगभग 175 लाख टन की रिकॉर्ड मछली उत्पादन दर के साथ भारत की वैधिक मछली

उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी है । पशुपालन एवं मत्स्यपालन आज सकल घरेलू उत्पादन में 35 प्रतिशत का योगदान कर रहा है और हम 63 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निर्यात करने लगे हैं ।

भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है और दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री भोजन निर्यात करने वाले देशों में से एक है । यह क्षेत्र 3 करोड़ से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है, जिनमें से ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के हैं ।

मोदी सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण भारत के झींगा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 के भारत का झींगा निर्यात 8 हजार 175 करोड़ रुपये का था, जोकि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है ।

भारत दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 प्रतिशत का योगदान देता है । डेयरी क्षेत्र में मोदी सरकार के सार्थक प्रयासों के बल पर पिछले पिछले 10 वर्षों में देश का दूध उत्पादन 51.05% बढ़ा है ।

वर्ष 2014-15 के दौरान देश का दूध उत्पादन 14.63 करोड़ टन था, जो 2022-23 के दौरान बढ़कर 23 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है । पिछले 9 वर्षों में दुग्ध उत्पादन 5.85 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक दुग्ध उत्पादन केवल 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है ।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है । यह योजना देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी को अधिक लाभदायक बनाने के लिए गोजातीय दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण है । इस योजना को 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अंब्रेला योजना विकास कार्यक्रमों के तहत जारी रखा गया है ।

आजादी के बाद से पहली बार मोदी सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी का लाभ दिया । आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में लगभग । करोड़ 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसानों को केसीसी के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के डेयरी किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसानों को 1900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उपलब्ध करवाया गया है, जिनमें 16 हजार 870 किसान उत्तर-पूर्वी राज्यों से है ।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड 6 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में पायलट आधार पर मछली हैचरी/मछली फार्म ब्रूड बैंक/फीड मिल का प्रमाणीकरण की योजना लागू की है । इसमें लगभग 3040 लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य 4.52 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ प्रमाणन योजना के तहत विभिन्न हैचरी, फीड मिलों और मछली फार्मों की 1711 इकाइयों को स्थापित करना है ।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में मछली उत्पादन के क्षेत्र में 2014-15 से 2022-23 तक पिछले 09 वर्षों के दौरान 5.38 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है । उत्तर-पूर्वी राज्यों में वर्ष 2014-15 में कुल मछली उत्पादन 4.03 लाख टन था, जो वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बढ़कर 6.04 लाख टन तक पहुंच गया है ।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए 2015-16 से 2019-20 तक केंद्र प्रायोजित नीली क्रांति योजना लागू की थी, जिसके तहत उत्तर- पूर्वी राज्यों के लिए 392 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई थी ।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 1391.62 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है ।

बजट 2024-25 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए रणनीतिक समर्थन से मछली, मछली बीज और मठली मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करके इस क्षेत्र का समावेशी और समग्र विकास होगा ।

'सुधार-प्रदर्शन-परिवर्तन' के आदर्श वाक्य के साथ, 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत सरकार एक प्रमुख कारक के रूप में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास को गति देने और इन क्षेत्रों से जुड़े किसानों और अन्य कामगारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में इन विभागों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से अलग करके एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया और निरंतर उसके बजट में वृद्धि भी की ।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र नोदी जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी क्षेत्र मे तेज गति से विकास को बढ़ावा मिला है । आज ये क्षेत्र और इनसे जुड़े सूक्ष्म व लघु उद्योगों में करोड़ों लोग अपनी आजीविका कमा रहे है, साथ ही देश के विकास में भी ये क्षेत्र निरंतर अपनी भागीदारी को बढ़ा रहे है । देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु मोदी सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों और योजनाओं के लिए मैं, एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का आभार व्यक्त करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूँ ।

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I support the Demand for Grants for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the year 2024-2025.

Under the leadership of our PM Shri Narendra Modi, our Government has brought transformational reforms in the fisheries sector that is a lifeline for a large section of our population, given our vast coastline.

India is the third largest fish producing country in the world. We give the world 8 per cent of its fish produce with our fish production standing at a record 175.45 lakh tons in FY 2022-23.

The last decade has seen a massive improvement in this sector which is recognized as the 'Sunrise Sector' sustaining over 30 million lives especially those belonging to the marginalized and vulnerable sectors of our society. While what was spent on the fisheries sector, over six decades, since the first five year plan of 2013-2014 was only Rs3,680 crore our Government led by Prime Minister Narendra Modi has in the last 10 years released Rs 6,378 crore for various developmental activities in this sector.

The highest ever targeted investment in this sector too has happened in the last 9 years, it stands at a total of Rs 38,572 crore. Also, of the one lakh startups in the country, 400 start-ups belong to the fishing sector. Our Government has consistently been making efforts for the holistic development of the fisheries sector while also focussing on the socio-economic well-being of our fishermen, fish farmers and other stakeholders in this industry.

In FY 2015-16 itself, the Blue Revolution scheme for Integrated development and management of fisheries was launched with an outlay of Rs 3,000 crore. In 2017-18 the National Marine Fisheries Policy was launched.

In 2018-19 Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund was launched with a corpus of Rs 7,522 crore. In order to ensure our fish farmers are accorded the same facilities as our Annadaatas, the Kisan Credit Card (KCC) facility has been extended to include both our fishing as well as animal husbandry farmers since 2018 more than 3.2 lakh applications have been received so far of which over 1.7 lakh have already been issued.

To ensure it gets its exclusive attention, given its potential and the vast scope for development, an exclusive department of fisheries was created in 2018-19.

In 2019-20, our Government also created a separate Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, thanks to which I have this opportunity too to speak about this key sector and its growth as a special story of growth and transformation.

The creation of this Ministry made way for focused attention through policy and financial support for sustainable, responsible, inclusive and equitable growth. A flagship scheme of our Government which is transforming lives of our fish farmers and making them Atmanirbhar is the PM Matsya Sampada Yojana. This initiative launched in 2020-21 takes what we achieved through the Blue revolution scheme to the next level - from development of cluster based approach to policy support to technology infusion and enhanced investment in value chain that will enhance fisheries production and productivity; modernize fisheries infrastructure; improve fisheries exports.

This pathbreaking effort will transform the sector and the millions of lives connected to it like never before. For just between 2020-2025 the investment that is to flow into the fisheries sector was Rs 20,050 crore - this highest ever in this sector.

The Sagar Parikrama programme (whose fourth edition encompassing our coastal districts of Karnataka, was held in 2023) was a unique effort to reach out to, understand and empower the fishermen community in the country. This journey that started from Gujarat's Mandvi in March 2022 completed a coastal length of 7,898 kms in touching about 3,071 fishing villages culminating in January this year and I am sure, as intended, the feedback, suggestions and on- ground experience will help our Government in policy and scheme formulation for betterment of our fishing community.

From 1st June, our Government converged two schemes and brought out a new insurance scheme for fisherfolk that provides a comprehensive coverage of Rs 5 lakh which is fully subsidized with our fisher folk not required to pay any premium. Over 3.2 million fisher folk are covered under this scheme.

The PMMSY has also been a true enabler of *sabka saath sabka vikas* as there are various subsidies - especially for women fish farmers and the SC/ST community.

In the Interim Budget 2024-25, several schemes were announced to boost the sector ? Rs. 22,000 crore for the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund ? Rs. 21,500 crore for the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund ? Rs. 2750 crore for the Dairy Infrastructure Development Fund.

The budgetary announcement for department of fisheries for FY 2024-25 is the highest ever allocation to the Department. The interim Budget also announced the launch of Blue Economy 2.0. In the Full Budget 2024-25, we have built upon these initiatives - Launching the National Fisheries and Aquaculture Development Scheme with an outlay of Rs. 5,000 crore.

While we have been making great strides, especially under the Matsya Sampada Yojana that include fishermen welfare through replacement boats and livelihood and nutritional support, Aquatic Health Management through disease diagnostic centres, quality testing labs, as well as Sagar Mitras and Matsya Seva Kendras approved.

I seek that in the days to come and under this scheme, my constituency which has a coastline of 62 kilometres, be able to avail the best of the schemes and efforts being made by our Government for the well-being of this sector and its related communities of people.

In addition to these national initiatives, I would like to highlight the significance of this sector to my constituency, Mangalore. The coastal city of Mangalore is renowned for its vibrant fisheries industry, with a rich tradition of fishing and aquaculture. As per local sources, 20 fishermen communities reside in Karnataka - with a total of 70 lakh people of which around 1.2 lakh live in my constituency majority of whom have been very happy with the schemes of our Central Government, the PMMSY. However, our fishermen face numerous challenges, and I would seek that our Government also devote attention in the coming days to - Addressing fish decline issues caused by pollution from major oil based industries around the coast; Address issues of vulnerability to climate change and natural disasters - low rainfall and pollution from industries affecting catch; Lack of alternate livelihood during fishing ban and lean season - while a financial assistance of Rs 3000 per annum is provided to each enrolled beneficiary, it would be truly empowering if alternate means of employment or livelihood could be provided to the fisher folk during the fishing ban seasons - under related central government schemes or projects enabling the socio-economically backward families to be employed with sustainable sources of income; Addressing issues faced by traditional and small-scale fish farmers, including provision of adequate infrastructure for fish landing and support and facilities for promoting salting and fish drying by constructing fish drying yards for small scale fisher folk; Greater encouragement for coastal women fisher folk to pursue seaweed cultivation in our region; Upgradation of the Fisheries College to University status to enable greater advancements in the fisheries sector; Setting up of Marine Fisheries museums in key coastal towns, documenting, preserving and promoting the rich marine wealth of our country as well the traditional knowledge systems of the communities associated with the occupation.

The Narendra Modi Government's efforts to achieve reforms and resilience jal focus on the Fisheries sector will surely be a boon to the many promoting the rich marine wealth of our country as well the traditional knowledge systems of the communities associated with the occupation.

The Narendra Modi Government's efforts to achieve reforms and resilience in this sector, with special focus on the Fisheries sector will surely be a boon to the many families dependent on this sector for their livelihood.

I once again wholeheartedly support the demand for grants for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and urge this august House to do the same.

Jai Hind!

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) : मैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूँ । मैं अपनी ओर से माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मंत्रालय के वर्ष 2024-25 के बजट में देश के व्यापक हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है । केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में इस बात पर जोर दिया है कि मछुआरों की सहायता के महत्व को समझने के लिए एक अलग मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन दोनों में दोगुना वृद्धि हुई है । वर्ष 2013-14 से समुद्री खाद्य निर्यात में भी दोगुना वृद्धि हुई है । प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मौजूदा 3 टन/हेक्टेयर से 5 टन/हेक्टेयर तक जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात को दोगुना

करके 1 लाख करोड़ रुपये करने और 55 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ 5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित करने के बड़े बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है । इसके अलावा, जलवायु अनुकूल गतिविधियों, बहाली और अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देने और एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 शुरू की जाएगी । मत्स्य पालन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह राष्ट्रीय आय, निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी योगदान देता है । मत्स्य पालन क्षेत्र को 'सूर्योदय क्षेत्र' के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह भारत में लगभग 30 मिलियन लोगों की आजीविका को बनाए रखने में सहायक है, जो हाशिए पर पड़े कमजोर समुदायों के लोग हैं ।

आज हमारा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, इसका वैश्विक उत्पादन में 8 प्रतिशत हिस्सा है और देश के सकल मूल्य वर्धित में लगभग 1.09 प्रतिशत और कृषि में 6.724 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है । हमारी सरकार ने डेयरी किसानों को सहायता देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत "खुरपका और मुंहपका रोग" को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा विकास निधि सहित मौजूदा योजनाओं की सफलता पर आधारित है ।

आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ रहा है । लेकिन, विपक्षी दलों, जिनमें माननीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी भी शामिल हैं, उनको यह अच्छा नहीं लग रहा है । माननीय प्रतिपक्ष नेता राजनीति कर रहे हैं, जो शोभा नहीं देता है ।

अंत में, मैं पुनः मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूँ ।

श्री नारायणदास अहिरवार (जालौन): मैं अपने संसदीय क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर की जनता जनार्दन एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका दिया ।

मेरा संसदीय क्षेत्र बुन्देलखण्ड में आता है, जो कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि पर ही निर्भर हैं, लेकिन इस क्षेत्र में छुट्टा आवारा पशुओं की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है । ये आवारा पशु किसानों की फसल को तैयार होने से पहले ही खा लेते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं । किसान अपने खेत में बास-बल्ली, तार की घेराबन्दी करने के बावजूद भी अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं । मेहनत से तैयार फसलों को आवारा पशुओं के नुकसान से किसान तबाही के कगार पर आ गये हैं । इन छुट्टा आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण सही तरीके से आज तक नहीं हो पाया है ।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में आवारा घूम रहे पशुओं को रहने के लिए बड़ी-बड़ी गौशाला बनाकर उनके खाने-पीने की व्यवस्था कर दी जाये तथा उनके देख-रेख के लिए वेतन पर लोगों की नियुक्ति की जाये, जिससे वे सही तरीके से उन पशुओं की देखभाल कर सकें । इससे आवारा पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ दूध-घी का उत्पादन भी होगा और साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी । धन्यवाद ।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मैं पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर अपने विचार रखता हूँ ।

पूरे विश्व में पशुपालन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है यहाँ 535 मिलियन से भी अधिक पशुधन है, और देश भर में स्वदेसी नस्लों की संख्या आज 220 तक पहुँच गई है । आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम प्रति पशु दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में बहुत पीछे है । आज भी हमारे यहाँ देसी गायों का औसतन दूध उत्पादन 5 लिटर तक भी नहीं पहुंच पाया है, क्यों की हमने कभी भी देसी नस्ल के पशुओं पर नस्ल सुधार की दिशा में कोई खास कार्य नहीं किया है ।

भारत आज विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा गोकुल मिशन व डेयरी डेवलपमेंट के तहत कोई भी बजट जारी नहीं किया गया हैं । यह अत्यंत ही विचारणीय विषय हैं । इस मंत्रालय के तहत जारी बजट में डेयरी विकास के लिए बजट में 69% तक कि कटौती इस बार भारत सरकार द्वारा कि गई हैं । पिछले

वर्ष देश में पशुओं विशेषकर दुधारू पशुओं में लम्पी बिमारी का भारी प्रकोप रहा, राजस्थान में हजारों कि संख्या में पशु काल का ग्रास बने । भारत सरकार द्वारा न तो लम्पी से ग्रसित पशुधन को बचाने के लिए ही कोई त्वरित कार्यवाही कि और न ही अब आगे इस प्रकार कि कोई समस्या हो तो उसके रोकथाम के लिए ही कोई योजना बने गई हैं । भारत सरकार को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए व आगे से इस प्रकार कि बिमारी से पशुधन कि रक्षा कि जा सके इसके लिए त्वरित प्रयास किये जाने चाहिए ।

वर्तमान में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गौकुल मिशन योजना के अंतर्गत Breed Multiplication Farms योजना चलाई जा रही है । इस योजना के तहत सरकार कम से कम 200 गाय या भैंसों पर सब्सिडी देती है । जबकि आज देश में 70 प्रतिशत से भी अधिक किसान छोटे और सीमांत किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो किसान 200 गाय या भैंसों को कैसे पाल सकता है । इस योजना का फायदा आज तक किसी सामान्य किसान या पशुपालक को नहीं मिला है । इसी लिए इस योजना को छोटे लेवल पर शुरू किया जाए ताकि सामान्य किसान भी इसका लाभ उठा सके और इस योजना को सरकार केवल दो से तीन महीने तक चला कर वापिस बंद कर देती है । जब तक एक साधारण व्यक्ति अपने कागज योजना के लिए तैयार करता है तो पता चलता है की योजना बजट के आभाव में बंद हो गई इसी लिए इसे साल भर चलाया जाए और इस का बजट भी बढाया जाए ।

आज भारत सरकार द्वारा पशु पालकों के लिए भी पशुधन पर लोन की सुविधा दिया जाना बताया जा रहा हैं । लेकिन कोई भी किसान जब बैंक के पास पशुपालन पर लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक मेनेजर किसान को लोन देने को तेयार नहीं होता है, ऐसे योजनाओं का भट्ठा ऐसे बैंकों के द्वारा बैठाया जा रहा हैं । बैंक मेनेजेर अपनी मर्जी से लोन देते हैं ।

भारत सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना NLM यानी (राष्ट्रीय पशुधन मिशन) योजना के तहत भेड़ बकरी पालन के लिए आज पुरे देश भर में लगभग 50 हजार किसानों ने आवेदन किया है जबकि आज तक सब्सिडी मुश्किल से केवल 1000 किसानों को ही मिल पाई है और इसमें राजस्थान जैसा प्रदेश जो भेड़ बकरी पालन में देश में सबसे अग्रणी राज्य है वहां आप की सरकार होते हुए भी केवल 20 से 25 किसानों को ही इस योजना का लाभ मिला है । जिसका भी अभी तक पूरा डाटा सामने नहीं आया हैं । इसके तहत भी किसान को बैंकों के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन बैंक मैनेजर की हठधर्मिता के कारण अधिकतर किसान इस योजना का लाभ लेने से पीछे हट जाते हैं । सरकार को एक उचित और स्थाई मोनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ पात्र व्यक्ति को दिया जा सके ।

भारत द्वारा पिछले वर्ष 60 हजार करोड़ रूपये का मस्त्य एक्सपोर्ट किया हैं जिसमे 45 हजार करोड़ का सिर्फ झींगा एक्सपोर्ट किया गया हैं । इसके निर्यात के द्वारा देश को काफी लाभ मिला हैं और आम किसान को भी संबल मिला हैं । लेकिन आश्चर्य की बात हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारें इस और कार्य करने में बिलकुल भी जाग्रत प्रतीत नहीं हो रही हैं । प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत पिछले वर्ष 20 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें से अधिकतर बजट अभी तक भी प्रयोग में नहीं लाया जा सका है । इसका मूल कारण हैं, सब्सिडी में राज्य सरकार का अंश होना । मैं इस मामले में राजस्थान के बारे में बोलना चाहता हूँ कि राज्य सरकार द्वारा इस और कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरु में इस समय झींगा पालन का कार्य अनेक किसानों के द्वारा किया जा रहा हैं । जिससे क्षेत्र के किसानों को काफी संबल मिल रहा हैं । एक रिपोर्ट के अनुसार चुरु लोकसभा क्षेत्र में लगभग 20 हजार हेक्टेयर जमीन पर झींगा उत्पादन कि क्षमता हैं । अगर यह होता हैं तो चुरु लोकसभा क्षेत्र अकेला ही पुरे क्षेत्र में झींगा उत्पादन में अग्रिणी हो जायेगा । लेकिन सरकार कि उदासीनता के कारण क्षेत्र के किसानों का इस और ज्यादा झुकाव नहीं बन पा रहा है । अभी तक चुरु लोकसभा क्षेत्र के 1 भी किसान को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत लाभ नहीं मिला हैं । यह काफी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस मामले में कितनी उदासीनता दर्शा रही हैं ।

अगर क्षेत्र के किसानों को इस योजना के तहत स्पेशल कोटा दे कर सब्सिडी का लाभ दिया जाए तो पुरे उत्तर भारत में चुरू लोकसभा क्षेत्र इस मामले में अग्रिन भूमिका निभा सकता हैं । और पूरी तरह से निर्यात आधारित उद्योग होने के

कारण यह क्षेत्र को संबल भी प्रदान कर सकता हैं । अतः सरकार को चुरु लोक सभा क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत विशेष लाभ दिया जाए व उन्हें लोन भी उपलब्ध करवाया जाए ।

इसी प्रकार राजस्थान में हो रहे झींगा उत्पादन हेतु किसी भी बीमा कंपनी द्वारा क्षेत्र के किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं । जिनके द्वरा उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनके द्वारा इतनी अधिक शर्ते लगाई जाती हैं कि कोई भी किसान इन शर्तों के तहत बीमा का लाभ नहीं ले सकता । अतः सरकार को इस और विशेष ध्यान देते हुए इनलैंड फिश फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए विशेष बीमा योजना का प्रावधान करवाया जाना चाहिए ताकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ-साथ पूरे राजस्थान के किसान इस योजना का लाभ ले सकें । सरकार द्वारा उक्त योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के साथ जोड़कर शामिल किया जाना चाहिए ।

पशु बीमा योजना की भी आज बहुत ख़राब हालात है कोई भी बीमा कम्पनी पशुओं का बीमा करने के लिए तैयार नहीं है तो बीमा कंपनियों को इस लिए पाबंद किया जाए । गौशालाओं में भी नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान और सेक्स सॉर्टेड यानी बछड़ी पैदा होने वाले सीमेन को ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाए । किसानों को सेक्स सॉर्टेड यानी बछड़ी पैदा होने वाले सीमेन पर अधिक से अधिक सब्सिडी देकर सस्ती दरों में सीमन दिया जाए । सीमेन सेंटरों की जाँच की जाए क्यों की आज देश भर में बहुत अधिक फर्जी सीमेन सेंटर चल रहे है उनके पास किसी भी सांड (नर पशु) का अधिकारिक उत्पादन का कोई रिकॉर्ड नहीं है और किसान को वो लुटने का काम करते है इसी लिए सीमेन सेंटरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएँ और दूध उत्पादन के लिए पशुओं की अच्छी नस्लों को बढ़ावा दिया जाए ।

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल (बाड़मेर) : रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट किसी जमाने मे जीवनोपार्जन का क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है । किसी जमाने में आवागमन एवं वाणिज्यक कार्यों में साधन के रूप इसका सर्वाधिक उपयोग होता था । इसी कारण इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है । परन्तु वर्तमान में ऊंटों की जो स्थिति है यह चिन्ता जनक है, दिन-प्रतिदिन कटों की संख्या में भारी मात्रा में कमी आ रही है । इसका मुख्य कारण उनका सही रूप से संरक्षण एवं संवर्धन नहीं होना है । यदि विभागीय आंकड़ों का अवलोकन करे तो हेरानी होगी कि जिस तरह ऊंटो की संख्या घट रही है यदि यही हाल रहे तो एक दिन यह प्रजाति विलोपित हो जायेगी । इस के मुख्य कारणों में एक है कि कट को राजस्थान का राज्य पशु की संज्ञा तो दे दी मगर उनके संरक्षण एवं सवर्धन हेतु किसी प्रकार की गाइड लाइन जारी नहीं की गई है । ना ही पशुपालन विभाग में इस हेतु किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है ।

किसानों की कमजोर माली हालात, दूषित वातावरण, पशुपालन में ग्रामीणों की अभिरूचि में कमी के साथ ही पशुओं में विशेषकर ऊंटो में फैल रहे संक्रमण के कारण बीमारी के कारण तीव्र गति से ऊंटों की संख्या में भयंकर कमी आ रही है । जिसका उदाहरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	1951	1956	1961	1966	1972	1977	1983	
ऊटों की संख्या (लाखों में)	03.41	04.36	05.70	06.54	07.45	07.52	07.56	07.19
वर्ष	1997	2003	2007	2012	2019			
ऊटों की संख्या (लाखों में)	06.69	04.98	04.22	03.25	02.13			

इस प्रकार हम देखें तो 1951 से 1966 तक संख्या में वृद्धि हुई थी और 1966 से लगातार कमी आ रही है । 1972 की संख्या में ऊंट 2012 में आधे हो गये है । यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है । यदि इसी प्रकार संख्या घटती गई तो एक दिन यह प्रजाति लुप्त प्राय हो जायेगी इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

राजस्थान सरकार ने साल 2012 में ऊंटों के प्रजनन में बढ़ावा देने हेतु विकास योजना शुरू की इस योजना में पशुपालकों को ऊंटनी के प्रसव पर (टोरड़ियों) ऊंटनी के बच्चे के पालन हेतु तीन किश्तों 10 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ।

राज्य पशु ऊंट का संरक्षण नितान्त आवश्यक है । यदि समय रहते सचेत नहीं हुए तो हमारी भावी पीढ़ी ऊट को डाईनासोर एवं अन्य लुप्त प्रजाति की भांति चित्रों में ही देखगी । मेरा विशेष आग्रह यह है कि केन्द्र सरकार को आवश्यक वितिय सहायता प्रदान कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने चाहिए कि ऊंट के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर कारगर कदम उठाकर उनका संरक्षण एवं संवर्धन करे । साथ ही जनता में जागरूकता एवं किसानों एवं पशु पालकों में ऊंट पालन हेतु रूचि पैदा करने हेतु आवश्यक कदम उठाये ।

मैं संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में ऊंट संरक्षण एवं सर्वधन केन्द्र खोलने की मांग करता हूँ ।

SHRIMATI SHAMBHAVI (SAMASTIPUR): Today, I would like to mention about a sector that holds the key to our rural economy, our food security, and the livelihood of millions Animal Husbandry, Dairy, and Fisheries in India.

- Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, this sector has seen remarkable transformations, bringing prosperity and sustainable development to our nation. In this speech, I will delve into the current state of these industries, highlight significant data, discuss the Budget 2024 allocations, and outline the positive steps taken by the Modi Government.
- Animal husbandry in India is a vital part of the agricultural economy. It contributes significantly to the livelihoods of rural families and the national economy. The sector includes livestock such as cattle, buffalo, sheep, goats, pigs, and poultry.
- Cattle and Buffaloes: India is the largest producer of milk globally, with a production of 209.96 million tons in 2020-21, up from 146.31 million tons in 2014-15.
- Sheep and Goats: With approximately 135 million goats and 74 million sheep, these animals are crucial for the livelihoods of small and marginal farmers.
- Poultry: The poultry sector has also seen tremendous growth, with egg production increasing to 122.05 billion in 2020-21 from 78.48 billion in 2014-15.
- In the Union Budget 2024, the Government has allocated Rs 4,500 crore for the animal husbandry and dairy sector. This represents a significant increase from previous years, reflecting the Government's commitment to strengthening this sector.
- National Livestock Mission: Launched to enhance livestock productivity and ensure the availability of quality feed and fodder. This mission focuses on breed improvement and health care of livestock.
- Rashtriya Gokul Mission: Aimed at the development and conservation of indigenous bovine breeds. It includes setting up Gokul Grams as integrated cattle care centers.
- E-Pashu Haat Portal: This online portal facilitates the trade of livestock, ensuring farmers get a fair price for their animals.
- The dairy sector is a major component of India's agricultural economy, contributing around 4% to the GDP.
- Dairy Cooperatives: Around 1.9 lakh dairy cooperative societies are operational in India, benefiting over 17 million farmers.
- National Dairy Plan: This plan focuses on increasing milk production, improving breeding and feeding practices, and providing better market access to farmers.
- Kisan Credit Card Scheme: Extended to dairy farmers, provides them with timely credit for their working capital needs.

- Dairy Entrepreneurship Development Scheme: Aimed at generating self-employment and providing infrastructure for the dairy sector.
- India's fisheries sector is the second-largest producer of fish in the world, contributing significantly to the national income and providing employment to millions.
- Fish Production:Fish production in India was 14.73 million tons in 2020-21, up from 10.07 million tons in 2014-15.
- Exports: The export value of fish and fish products was $6.68 billion in 2020-21.
- In the Union Budget 2024, Rs 2,500 crore has been allocated for the fisheries sector, a 15% increase from the previous year. Additionally, Rs 600 crore has been allocated for the National Green Hydrogen Mission, which indirectly benefits the fisheries sector by promoting sustainable practices.
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY); launched to enhance fish production and productivity, this scheme aims to achieve a fish production target of 22 million tons by 2024-25.
- Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF): Provides concessional finance to develop infrastructure facilities in fisheries and aquaculture.
- Kisan Credit Card Scheme: Extended to fish farmers, enabling them to access timely credit.
- Integrated Development and Future Directions;
- Technological Upgradation: The Government has focused on technological advancements in animal husbandry, dairy, and fisheries. This includes the use of genomics, biotechnology, and digital platforms to improve productivity and efficiency.
- Training and Skill Development: Numerous training programs have been initiated to educate farmers and fishermen about modern practices and techniques. This enhances their skills and increases productivity.
- Market Reforms: Digital marketing platforms and e-commerce have been promoted to provide farmers and fishermen with better market access and fair prices for their products.
- Health and Safety: Veterinary health services and vaccination programs have been intensified to ensure the health and well-being of livestock.
- Research and Development: Emphasis on R&D has led to the development of new and improved breeds of livestock and fish, better disease management practices, and sustainable farming techniques.
- Environmental Sustainability
- Sustainable Fisheries: The Government is promoting sustainable fishing practices to protect marine biodiversity and ensure the long term viability of the fisheries sector.
- Green Practices in Dairy: Solar energy initiatives and waste management systems are being implemented to reduce the environmental impact of dairy farming.
- Climate Adaptation: Strategies are being developed to mitigate the effects of climate change on animal husbandry, dairy, and fisheries. This includes the promotion of climate-resilient breeds and farming practices.
- Strengthening Cooperatives: The government is empowering cooperatives to provide better support and services to farmers and fishermen. This includes financial assistance, infrastructure development.
- Inclusive Growth: Special attention is being given to the upliftment of marginalized communities engaged in animal husbandry, dairy, and fisheries. This ensures inclusive growth and reduces poverty.

- India is also actively engaging in international collaborations to share knowledge, technologies, and best practices in animal husbandry, dairy, and fisheries. These collaborations help in adopting global standards and improving domestic practices.
- Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has made significant strides in the fields of animal husbandry, dairy, and fisheries. The comprehensive policies and initiatives introduced by the government have led to increased productivity, enhanced livelihoods, and sustainable development in these sectors. The Union Budget 2024 further reflects the Government's commitment to these sectors, with substantial allocations aimed at fostering growth and innovation.
- As we move forward, it is imperative to continue these efforts and build on the foundation laid by the Modi government. By embracing new technologies, promoting sustainable practices, and ensuring inclusive growth, we can transform the landscape of animal husbandry, dairy, and fisheries in India, making it a model for the world to emulate.

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I must thank our Honourable prime minister and our Honourable finance minister for allocating such a generous and well planned budget for the year 2024-2025.

Our Government has allocated funds for animal husbandry, dairy, and fisheries in the 2024-2025 budget as follows:

Animal Husbandry and Dairying Department: ₹4,521 crore

Fisheries Department: 22,585 crore

Ministry of Food Processing Industries (MoFPI): 3,290 crore

- **Comprehensive Programme for Supporting Dairy Farmers**: To improve milk productivity and reduce post-harvest losses.
- **Rashtriya Gokul Mission**: A scheme to enhance livestock health and dairy productivity.
- **National Livestock Mission:** Aims to improve livestock health and productivity.
- **Infrastructure Development Funds for Dairy Processing and Animal Husbandry:** To support infrastructure development in the dairy and animal husbandry sectors.
- **Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY):** A scheme for sustainable and responsible development of the fisheries sector, with a budgetary allocation of 2,352 crore. To strengthen India's shrimp farming industry globally, import duty reductions on key inputs are proposed for lowering production costs and increase revenues & profit margins.

To strengthen India's position as a leader in value-added fish processing, import duties on value-added fish processing ingredients-pre-dust breading powder duty has been removed. Finance Minister also announced that the Government will bring out National Co-operation Policy for systematic, orderly and overall development of the co-operative sector.

India is currently, the 2 largest fish producing country with around 8% share in global fish production and a record high fish production of 174.45 lakh tonnes (2023-24). India also stands at 2nd in aquaculture production and is one of the top shrimp producing and seafood exporting nations in the world. The sector provides sustainable livelihoods to over 30 million people mostly within the marginalized and vulnerable communities.

With the motto of 'Reform-Perform-Transform, GoI continues to prioritise the development of the fisheries sector as a key driver towards a Viksit Bharat by 2047. In continuation to the launch of transformative schemes and initiatives in the past, the Budget Announcement 2024-25 increases the budget allocation for the fisheries sector and provisions to address major sectoral challenge of high

operational and production cost. For the year 2024-25, Rs. 2,352 crore allocation this allocation is 56% more than the allocation of Rs. 1,500 crore made during the year 2023-24. To ensure availability of quality brood for quality seed, our honourable Finance. announced the financial support for setting up a network of Nucleus Breeding Centre (NBC) for shrimp brood stocks. Further, financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. Establishment of state-of-art facilities in NBCs will improve the genetic quality of aquaculture species for higher productivity and quality, reduce the dependence on import of shrimp brood stock. This is a welcoming step to promote the shrimp industry, Shrimp exports have significantly grown to Rs. 40,013 crore in 2023-24 from Rs. 8,175 Crore An increase of 20%

I come from Kalahandi' constituency in Odisha I have two districts i.e. Kalahandi & Nuapada in my constituency and we have lots of dams and ponds in our area. First I would like to discuss fisheries for my district. Development of fish farms and hatcheries to increase fish production and provide employment opportunities. Improvement of fishing infrastructure such as jetties, landing centers, and markets. Training and capacity building programs for fishermen and fish farmers. Introduction of new fish species suitable for Kalahandi and Nuapada climate and water bodies. Support for fish processing and value addition to increase income for fishermen and fish farmers. Training centres to encourage prawn and pearl culture in my constituency. Subsidies for fisheries to encourage them on a large scale.

Now to discuss animal husbandry, here are some suggestions: Establishment of veterinary hospitals and dispensaries to provide better healthcare for animals. Improvement of cattle breeding and dairy development programs to increase milk production and improve livestock quality. Introduction of new livestock species suitable for Kalahandi's climate and geography. Training and capacity building programs for livestock farmers and animal husbandry professionals. Support for animal feed and fodder development to improve livestock nutrition and productivity. I would request the Government to introduce and encourage the dairy farmers by giving them subsidies and encouraging them to buy Indian variety cows like Gir, Kathi and Sahiwal cows, cause people will get A2 milk products which is very find for health. Government had introduced a fabulous scheme called Gokut mission but the only problem in it is that it is implemented for farmer with 500 acres of land so I would request the government to facilitate this scheme even for farmers with land of 100 acres.

And finally my suggestions for dairying, establishment of new dairy processing units to enhance milk processing capacity and reduce waste. Improvement of existing dairy infrastructure such as chilling centers, bulk milk coolers, and milk testing laboratories. Introduction of high-yielding dairy breeds suitable for Kalahandi's climate and geography. Training and capacity building programs for dairy farmers, dairy cooperative societies, and dairy professionals. Support for dairy farming through subsidies, credit, and insurance schemes. Development of dairy-based value-added products such as cheese, butter, and ghee. Promotion of women's participation in dairy farming and entrepreneurship. Establishment of dairy demonstration and training centers to showcase best practices. Improvement of milk marketing and distribution channels to ensure fair prices for dairy farmers. Research and development initiatives to improve dairy productivity, and substantially. Support for dairy farmers during natural calamities. Government had introduced a fabulous scheme called Gokul mission but the only problem in it is that it is implemented only for people with 500 acres of land so I would request the Government to facilitate this scheme even for farmers with land of 100 acres. Hoping and wishing that our Honourable Minister will consider and help us to develop my Constituency of Kalahandi and Nuapada lead to overall development of my Constituency.

SHRIMATI ANITA SUBHADARSHINI (ASKA): I request Hon'ble Minister, Animal Husbandry for sanctioning adequate fund for a sanctuary for BlackBugs in my Constituency for ASKA (Ganjam. Odisha). Blackbugs a rare and beautiful animal spices are found in a huge numbers in my area but the number are going down because of lack of concern of the previous State Government. Please be mind for these Animal breed and take necessary steps for the Safety of Blackbugs.

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र कोकराझार असम के बक्सा जिले में कोकलाबाड़ी सीड फार्म की और दिलाना चाहता हूँ जिसे वर्ष 1971 में सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास के लिए बनाया गया था और यह संस्थान वर्ष 2001 तक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था किन्तु बिना किसी कारण के इसे 2001 के बाद मिलने वाली सहायता बंद हो गई और आज ये संस्थान बिना वजह बंद पड़ा है। पुरे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में केंद्रीय संस्थानो की पहले से ही भारी कमी है। इस क्षेत्र में सरकार ने बहुत कोशिशों के बाद कोकलाबाड़ी स्टेट सीड फ़ार्म को 6880 बीघा जमीन को अधिग्रहण करके स्थापना की थी। यह संस्थान स्थानीय लोगो और किसानो के लिए बहुत अच्छा था केवल इसके रखरखाव और ट्रेनिंग सेंटर को तकनीक और अच्छे वैज्ञानिक और उचित आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी किन्तु संस्थान बिना वजह बंद कर दिया गया।

इस कोकलाबाड़ी स्टेट सीड फार्म में कोकराझार और पुरे बोडोलैंड इलाके में पायी जाने वाले फल खासकर नीम्बू नारियल, सरसो के तेल और मछली पालन, सूरजमुखी, पिगरी और पेड्डी सीड जैसे बहुत सारे विभाग काम कर रहे थे और केवल अच्छे स्पेशलिस्ट प्रोफेसर की नियुक्ति करने की आवश्यकता थी जिससे कोकराझार और बोडोलैंड के क्षत्रीय निवासियों को इस कोकलाबाड़ी स्टेट सीड फ़ार्म का उचित फायदा मिल सके । मौजूदा कोकलाबाड़ी स्टेट सीड फ़ार्म के पुनरुद्धार (upgrade and promotion) और विस्तार की बहुत आवश्यकता है। यहां पर खेती के विस्तार और स्थानीय (लोकल) पाए जाने फल फ्रूट और अन्य चीजों के उचित विस्तार और विकास के लिए नए प्रोजेक्ट्स को लगाया जाना चाहिए पशुपालन, मछली पालन एवं डेयरी दुग्ध एवं अन्य सभी विभागों के अधिकारियो की नियुक्ति होनी चाहिए जिससे यहाँ के निवासियों और किसानो को उसका लाभ मिल सके ।

कोकलाबाड़ी स्टेट सीड फ़ार्म की वर्तमान स्थिति में बदलाव करके यहाँ पर बीज उत्पादन और खेती के विस्तार के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए । इस संस्थान में होने वाले रिसर्च और तकनीक के विस्तार के लिए ध्यान देते हुए केंद्र सरकार की और से इस संसथान को अलग से धन राशि उपलब्ध करानी चाहिए और नई परियोजना बनानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के किसानो को इसका उचित लाभ मिल सके और उनका आर्थिक विकास भी हो सके ।

DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR): I would like to express my views on the Demand for Grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

Budget Allocation

- UPA 2013-14: 2110 Cr (at that time it was a department under the Ministry of Agriculture)
- NDA present budget-7137 Cr
- Almost a **250% increase in budget**
- Showcasing focus of the Government on providing farmers and allied workers with alternate livelihood opportunities and making them financially independent.
- Made a separate ministry under the Modi Government in 2019.

The leadership understood that the sector needed separate and dedicated attention for its growth.

Comparison with UPA Government and Important Statistics

- Livestock Sector

a. From 2014-15 to 2022-23, the livestock sector grew at an impressive Compound Annual Growth Rate of 7.38 per cent at constant prices,

b. In 2022-23, the livestock sector contributed 4.66 per cent of the total GVA of the country.

- Milk Production

a. 2012-13, milk production was 132.43 million tonnes (mt) and average year-on-year growth rate of milk was 4.04.

b. 2022-23, milk production 230.6 mt, a 75% increase and the average growth reached approximately 10% under NDA's tenure.

- Egg Production
    a. 69.73 billion in 2012-13
    b. 138 billion in 2022-23
    c. Almost doubled in 10 years
- Fish Production
    a. 9.04 mt in 2012-13 & India about 5.4% of global fish production
    b. 17.5 mt in 2022-23 & 8% share of global production
    c. The fisheries sector, a crucial contributor to the Indian economy, makes up about 6.72 per cent of the agricultural GVA

Budget Provisions

Fisheries

- Government has identified a motto of 'Reform-Perform-Transform' to develop the fisheries sector as a key driver for Inclusive growth under Viksit Bharat 2047.
- 56% more allocation for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana compared to last year?s revised estimates.
- Import and custom relaxations for multiple commodities to reduce input prices.
- Development of Fisheries Cooperatives under the National Cooperation Policy will empower the fishers.
- Target to train 80 thousand Individuals for capacity building in fisheries.
- Creation of 10 organized fish harbours and fish landing centres.

Animal Husbandry and Dairying

- FMD vaccination for 5000 Lakh livestock under the Livestock Health and Disease Control Programme with an increased allocation.
- The budget targets 4,145 Mobile Veterinary Units by 2025
- Increased allocation for Rashtriya Gokul Mission to work towards
    a. Development and Conservation of Indigenous Breeds
    b. Breed improvement through modern technology
    c. Expansion of Artificial Insemination.

I fully support the budget and want to further make a national level request to the Government to further focus on cross-ministry Integrated Coastal Zone Management, such as the programme undertaken by the Government in collaboration with the World Bank. Coastal villages including fishermen communities are the most vulnerable communities being affected by coastal erosion at risk of displacement.

Potential Recommendations:

- Focus on Marine Protected Areas: to conserve marine biodiversity, protect critical habitats, and promote sustainable fishing practices
- Promote Climate-Resilient Aquaculture Practices: Adoption of techniques to help diversify livelihoods for communities while reducing pressure on wild fish stocks.
- Invest in Climate-Adaptive Infrastructure: Such as mangrove restoration & shoreline protection measures.

I would also like to commend the NDA Government for sanctioning 1071 crores for the fisheries sector in Odisha for the welfare of fishermen in January. I request that this sanctioned amount should also be utilized in Ganjam for the upliftment of fishermen along the Ganjam coast facing some of the most severe issues in the state. Timely provisions are necessary to address the trend of forced and distress migration of fishermen communities from Ganjam to other states for their livelihoods.

Now that Odisha has given the NDA a mandate of a double engine Government, I request the quick development of the Aryapalli Fishing Harbour which suffered severe delays under the BJD Government.

Currently fishermen in the Ganjam coast struggle to use Trawlers due to the lack of a harbour in the region. This decreases productivity of fishermen affecting their economic status severely. The port would directly contribute to the upliftment of the fishermen in the district who lag behind other areas with harbour. Further, the fishermen require subsidies to switch to trawlers to afford them.

My constituency requires an integrated package for fishermen with: Fishing harbour and sea mouth near Sunapur, digging of Chilika Lake near Sumandi, aquapark at Harbhangi Project in Gajapati, establishment of modern labs in fisheries college in Rangeilunda for research and cold storages, market linkages, fish processing units.

Animal husbandry in Odisha is crucial to rural households as around 80% own livestock of at least one species to earn extra income for the family. Hence, the sector requires great emphasis.

A sample study by the Orissa University of Agriculture and Technology revealed that the average annual income of goat farmers in the Ganjam district was just 45,000. The situation is made even worse by the fact that in the study the average family size was found 7.68. How can a family of 7-8 members achieve a higher standard of living with an income of 45,000.

Initiatives like increased subsidies to cooperatives, vaccinations and breed improvement programmes could help significantly increase people's income. I also request set-up of Mobile Veterinary Units in my constituency, as provided for in this budget as this could help reduce fatality of animals due to accidents such as on highways and also illness and diseases.

I thank the Prime Minister and the Finance Minister once again for a budget that covers several concerns and needs of the fisheries and animal husbandry sector to ensure its development as an alternate source of livelihood to millions of people.

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी की 2024- 25 की अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखता हूँ ।

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में देश के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र मे देश वासियों के लिए अनेक योजनाओं चला रही हैं और अनेक योजनाएं लाई है। लेकिन इन योजनाओं का सही से इंप्लीमेंट नही हो पा रहा है। पर हमारे प्रदेश के लिए हर बार की तरह इस बार भी इस बजट में विशेष कुछ नहीं है। हम केन्द्र से संचालित हैं तो हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए था।

आज हम देश के नक्शे पर एक चावल के दाने जितने छोटे से प्रदेश के रुप में देश का अभिन्न अंग बनकर बहुत खुश हैं। दमन एवं दीव पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां लाखों लोग वर्ष पर्यन्त आते रहते हैं।

हमारा प्रदेश समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। यहां नदियों का संगम है। मत्स्य पालन यहां के क्षेत्र वासियों का आय का प्रमुख साधन और स्रोत है। लेकिन क्षेत्र के मच्छीमारो की सुविधाओं में दिनों दिन कटौती की जा रही है।

दमण एवं दीव प्रदेश के मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एवं मच्छीमारो के विकास के लिए चलाए जा रही अन्य योजनाओ के तहत जीपीएस, इंजन, वायर, लैंप, फ्रिज, जनरेटर, नई नौकाएं और अन्य बहुत सी सामग्री की खरीदारी हेतु सरकार से सहायता (सब्सिडी) मिलती थी । लेकिन कुछ वर्षों से यह सहायता सरकार द्वारा बंद कर रखी है। साथ ही नाव पर चढ़ने, उतरने, तूफान और आग लगने की घटनाओं से होने वाले किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर मालिक अथवा परिवार के सदस्यों को अनुदान मिलता है। वह भी बंद है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि प्रदेश के मछुआरों को मच्छीमारी के काम धंधे मे उपयोग होने वाली हर वस्तु एवम साधन सामग्री पर पड़ोसी राज्य गुजरात जैसी सब्सिडी और सुविधा मिलनी चाहिये।

ये सभी प्रकार की सब्सिडी अतिशीघ्र मिलनी चाहिए। वर्ष 2022-23 एवम 2024 के 14 महीनों की बकाया डीजल की सब्सिडी के पैसे भी चुकाया जाए और तोकते तूफान में हुए माछुआरों के नुकसान की भरपाई भी जल्दी हो। साथ ही दीव बारा का ड्रेजिंग का कार्य का बजट भी रिलीज कर कार्य जल्द शुरू करवाने की कृपा करें, जिससे प्रदेश के गरीब मछुआरों के साथ न्याय हो सके। ***श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) :** भारत दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है लेकिन यहां उत्पादकता कम है दुधारू पशु की कमी है इसी समस्या के निदान के लिए सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी प्रोसेसिंग और पशुपालन की योजनाएं चला रही हैं। देश में पशुपालकों को इससे बहुत लाभ मिलता है। मैं सरकार का ध्यान पशुओं की कुछ बीमारियों ऐसी हैं जो कॉमन है जिसके लिए ग्रामीण में व्यवस्था होनी चाहिए साथ ही कुछ असाध्याय बीमारियां हैं जैसे खुर पका, मुंह पका, लम्पी आदि इसका नियंत्रण अतिआवश्यक है। यह पशुपालकों के लिए गंभीर समस्या है। पशुपालक किसानों को अधिक उत्पादन देने वाली अच्छी नस्लों के पशुओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। किंतु देश के सभी भागों के जलवायु अनुसार इस पर विचार होना चाहिए। ग्रामीण स्तर तक पशुओं के लिए निशुल्क पशु उपचार केंद्र जरूरी है। आज देश में पशु चिकित्सकों की भी कमी है। देश में सरकारी एनिमल रिसर्च सेंटर की भी कमी है, इसे खोला जाए। शिक्षण संस्थानों की कमी है, डेरी फार्म की कमी है, और पशुओं के लिए जरूरी दवाओं की कमी है एवं जो दवाई उपलब्ध हो रहे हैं उसकी कीमत ज्यादा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि सरकारी केंद्र में इलाज हेतु निशुल्क दवाएं उपलब्ध हो, पशुपालकों को वितरित हो। यह किसानों के लिए लाभकारी होगा। मैं खरगौन बड़वानी लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के पशुपालन लोन योजना संचालित है। यह योजना पशुपालकों के साथ युवाओं को भी रोजगार देने में सार्थक साबित हो रही है। 10 लाख तक का लोन से पशुपालकों की आय में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जनजातियों के लिए 20 लाख लोन मिलने के साथ आधा अनुदान व सब्सिडी मिले।

10 लोन -10 सब्सिडी एवं 10 भी 10 वर्षों में लौटने का प्रावधान हो जिससे जनजातीय परिवारों का जीवन स्तर ठीक होगा और पशुपालन भी बढ़ेगा। मेरा संसदीय क्षेत्र खरगौन बड़वानी कृषि की अधिकता एवं वन होने से पशुपालन की काफी समस्याएं हैं एवं खरगोन बड़वानी में एक एनिमल रिसर्च सेंटर की स्थापना की मांग करता हूं।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to express my views on the Demand for Grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the FY 2024-25.

Today we are discussing a Ministry that involves 65 percent of the people in India who are engaged in Fisheries, Animal Husbandry, Dairying which is a crucial sector for our economy, because it has the potential to double our farmers income and realize the vision of our Hon'ble Prime Minister of a Viksit Bharat.

We belong to a culture that worships animals and whether its Maa Durga, Lord Vishnu, Lord Shiva or Lord Ganesh, all Animals were represented as deities and vahanas/ carriers of deities. Worshiping and preserving animals is not just our religious duty, it is our

constitutional duty also because Article 48 of the constitution imposes a duty on the state to organize agriculture and animal husbandry on modern lines which includes taking steps for preserving and improving the breeds along with prohibiting the slaughter of cows.

The Government has allocated a budget of Rs. 4521 crore to the Department of Animal Husbandry and dairying, which is 194 crore higher than 2023-24.

As per the Economic Survey, India is the largest producer of milk in the world contributing 25% of global milk production. 5% percent to the national economy and directly employing more than 8 crore farmers. Milk production is growing at an annual growth rate of about 6%. Over the last nine years, India's milk output has increased by 58%, reaching 208,984,430 tons in 2022-23.

A notable aspect of India's dairy industry is the substantial involvement of women, with 35 percent of women participating in dairy cooperatives. There are 48,000 women dairy cooperative societies operational at the village level nationwide, fostering inclusive growth and empowering women in rural areas.

The Rashtriya Gokul Mission has been allocated 700 crore rupees this year and through this scheme the Government works exclusively for development and conservation of indigenous bovine breeds in a scientific holistic manner. As on date, 7.13 crore animals have been covered, 8.81 crores Artificial Inseminations have been performed and 4.75 crores farmers benefitted under the programme.

The first free vaccination campaign is underway to protect animals from foot and mouth diseases. So far, more than 50 crore doses have been administered to animals in four phases.

The National Programme for Dairy Development (NPDD) has been allocated 371 crores for implementation across the country to create and strengthen infrastructure for production of quality milk. Under the scheme, 17.45 lac new farmers were given membership of dairy co-operative societies and 83.56 lac litre of additional milk procured under the projects. About 24.82 lac litres per day new milk processing capacity has been established and 4193 Bulk Milk Coolers with 94.12 lac litres chilling capacity has been created at village level. About 233 dairy plant laboratories have also been equipped to detect adulterants in milk and milk products and about 10 State Central laboratories have been established to maintain the quality of milk and milk products.

Livestock Health and Disease Control Programme (LHDCP) has been allocated 2465 crore rupees and through this Government supplements the efforts of the State Governments / Union Territories by way of financial assistance.

Kisan Credit Cards (KCC) for Dairy Farmers of Milk Cooperatives and Milk Producer Companies has been made available to livestock and dairy farmers for the first time since 2019 enabling easy and increased access of institutionalized credit facility to them. As of March 31, 2024, 3.49 lac KCC and 34.5 lac KCC were issued to fisheries and animal husbandry activities, respectively.

As per the Economic Survey, India achieved a record fish production of 17.54 million tons, ranking third globally and accounting for 8 per cent of global production. This sector is a crucial contributor to the Indian economy making up about 6.72% of the agricultural GVA and has grown at a compound annual rate of 8.9% between 2014-15 and 2022-23 (at constant prices). This "sunrise sector" supports approximately 30 million people, particularly marginalised and vulnerable communities.

The Department of Fisheries has been allocated Rs. 2616 crores which is Rs. 368 crores higher than the last year. To address the sector's infrastructure needs, the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) was introduced in 2018-19 with a total fund size of Rs 7.52 thousand crores. So far, 121 proposals have been recommended for Rs 5.59 thousand crores as a concessional rate.

The Department of Fisheries has allocated Rs. 2,352 crores for the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) which is 5 times higher than the last FY. Projects worth of Rs.179.50 crore have been approved under PMMSY for activities including genetic improvement programme of Penaeusindicus, Broodstock Multiplication Centre (BMC) of P. monodon, construction of brackish water ponds in 1381 hectare of land and 20 shrimp hatcheries.

As reported by Coastal Aquaculture Authority (CAA), during last three years, 5544 coastal aquaculture farms have been established in coastal State and UTs. And I am proud to say that the second highest number of coastal aquaculture farms have been established in Odisha. The shrimp production from brackish water aquaculture has been increased to 11.84 lakh tonne during 2022-23. The brackish water aquaculture has positively impacted the Seafood Industry by increasing the seafood export to Rs.63,969 crore during 2022-2023. Out of Rs.63,969 crore seafood export, shrimp alone has contributed to Rs. 40,013 crores. To strengthen India's shrimp farming industry globally, import duty reductions on key inputs are proposed for lowering production costs and increase revenues and profit margins.

To strengthen India's position as a leader in value-added fish processing, import duties on value-added fish processing ingredients pre-dust breading powder duty has been removed.

To ensure availability of quality brood for quality seed, Finance Minister Smt. Sitharaman announced the financial support for setting up a network of state-of-art facilities Nucleus Breeding Centre (NBC) to improve the genetic quality of aquaculture species for higher productivity and quality, reduce the dependence on import of shrimp brood stock. Further, financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. Shrimp exports have significantly growth to Rs. 40,013 crores in 2023-24.

Finance Minister also announced that the Government will bring out National Co-operation Policy for systematic, orderly and overall development of the co-operative sector.

Inland fisheries production has increased from 61 lakh metric tonnes to 131 lakh metric tonnes. Exports in fisheries sector has more than doubled from Rs 30 thousand crore to Rs 64 thousand crore.

Even as milk production in Odisha has increased almost threefold in last two decades - from 8.75 lakh tonne in 2000 to around 24 lakh tonne now, per capita availability is much lower as compared to the national average and ICMR recommendation for basic nutritional requirement. The per capita availability in the State is 144gm/day which is much below the National average of 444gm/day and also the ICMR recommendation of 300 gm/day.

I would request the Hon'ble Minister to provide special assistance to the State of Odisha which has tremendous potential for dairy and fisheries sector which can not only help in improving the human development index but also act as a catalyst for economic development. The issues that also need attention in the dairy sector are low production capacity of existing cattle stock in the state, less availability of fodder, required veterinary services, lack of timely artificial insemination service delivery, less number of milk routes and higher number of dormant/less functional milk co-operative societies.

To sum up the strategic support for the animal husbandry, dairies and fisheries sector in the Budget 2024-25 will lead to inclusive and holistic development of the sector by providing the required fillip to enhance production and productivity of milk, fish, fish seeds and fish value added products.

The allied sectors of Indian agriculture are steadily emerging as robust growth centres and promising sources for improving farm incomes.

I support the Demand for Grants.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : भारत दुनियाँ का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है । भारत में मत्स्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लाखों मछुआरों की आजीविका प्रदान करता हैं। भारत में नीली क्रांति ने मत्स्य पालल और जलीय कृषि क्षेत्र के महत्व को प्रदर्शित करता हैं। राज्यवार आप देखे तो हरेक राज्य अपने-अपने स्तर पर मत्स्य पालन ओर विपणन का कार्य कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल मछली उत्पादन में आज पहले स्थान पर हैं, वही बिहार राज्य में सारी संभावनाओ के रहते हुए मछली पालन और उत्पादन में बहुत पीछे हैं। बिहार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 1500 (एक हजार 500 करोड़ रूपए) का मछली आयात करता हैं। जिसमें आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल बड़े पैमाने पर मछली बिहार को निर्यात करता हैं। बिहार नदियों से भरा पड़ा हैं। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण 6 लाख से अधिक छोटे-बडे तालाबों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर इन तालाबों का सही उपयोग होता तो मछली उत्पादन में बिहार आज आत्म निर्भर होता।

वहीं बिहार राज्य का कोशी, सीमांचल, मिथिलांचल के क्षेत्र पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। जिसमें पशुपालन स्थानीय लोगों की जीविका का साधन हैं। राज्य स्तर पर पशुपालकों को सरकार का सहयोग नगण्य हैं। क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी दुग्ध डेयरी का नहीं होना पशुपालकों के लिए दूध की बिक्री कर पाना कठिन हैं। वहीं लागत के अनुपात में किसानों को दूध का मूल्य नहीं मिल पाता हैं। स्थानीय निजी क्षेत्र बाजार अपनी मनमानी से दूध का मूल्य देते हैं। जिसके कारण पशुपालकों में पशुपालन के क्षेत्र में , भारी उदासीनता दिखाई देती है । बिहार राज्य को पशुपालन एवं मत्स्यपालन में सर्वाधिक आर्थिक सहयोग भारत सरकार को देना चाहिए ताकि राज्य सरकार पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्य कर सकें।

नेशनल ब्यूरो ऑफ़ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 53 नामांकित नस्ल के गाय और भैंस हैं, लेकिन गाँव में शहरों में नहीं दिखता।

पहले ठंडा में फिर मैगी में केमिकल मिले, अब तो दूध में भी केमिकल मिल रहा है जैसे ऑक्सीटोक्सीन. जिससे बच्चों को मानसिक बीमारी हो रही हैं।

फ़ूड प्रोसिसिंग यूनिट की कमी

दूध से चीज, बटर, चोकलेट क्रीम सब बन सकते हैं, लेकिन कितना बना पा रहे हैं, कैसे किसानों का इनकम डबल होगा।

कुछ योजनायें जो बनी कभी ठीक से लागु ही नहीं हुई, जैसे SPAWN FISH DEVELOPMENT MISSION, RASHTRIYA GOKUL MISSION, जलछाजन योजना, SHYAMA PRASAD MUKHERJEE RURBAN YOJANA और राष्ट्रीय जलवायु मिशन।

हम मिक्स्ड फोर्मिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जैसे मखाना और मत्स्य पालन एक साथ, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन एक साथ हो सकता है।

SHRI SASIKANTH SENTHIL (TIRUVALLUR): I would like to express my views on budget allocation for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. The total budget outlay for this ministry for the fiscal year 2024-25 stands at Rs. 7,137 Crores compared to Rs. 5,614 crores RE of fiscal year 2023-24 which highlight the critical importance of this sector.

Animal husbandry, fisheries, and dairying are vital sectors for our economy, particularly in rural areas, where they serve as major sources of employment and income. These sectors contribute around 25% to the agricultural GDP and play a crucial role in the socio-economic development of millions of rural households. Despite this, the modest increase in the budget allocation does not reflect the importance of these sectors or the challenges they face.

Inflation in the agriculture sector, including inputs like feed, veterinary services, and transportation costs, has been soaring. Recent reports indicate that the inflation rate for agricultural inputs, including animal feed, has reached around 10-12% annually. This surge in costs

places a tremendous financial burden on our farmers. So the proposed increase in the budget allocation does not sufficiently address these rising costs, nor does it help in mitigating the financial stress faced by farmers.

The allocation falls short of the needs outlined in the National Action Plan for Dairy Development, which aims to increase milk production to meet the rising demand and improve dairy infrastructure across the country. The plan requires significant investments in modernizing dairy farms, enhancing milk processing capacities, and improving the quality of milk and milk products. However, after going through budgetary provision of various schemes it looks like the budgetary allocation falls short of the needs. So I would ask about the current status of various targets under the National Action Plan for Dairy development.

National Action Plan for Dairy Development is targeted to increase organized milk handling from 20% at present to 41% by 2022 to 50% by 2023-24. The milk handling by cooperatives has been targeted to increase from 10% to 20% and the private sector from 10% to 30% Similarly, the budget for the National Livestock Mission, aimed at sustainable growth and development of the livestock sector, has also been decreased. This mission, which is essential for improving livestock productivity, enhancing milk, meat, and egg production, and ensuring a sustainable supply of quality livestock products, has an allocation of Rs. 324 Crores for 2024-25, compared to Rs. 410 Crores in 2023-24.

The allocation for the Rashtriya Gokul Mission, which is crucial for the development and conservation of indigenous breeds, has seen a deduction in budget. The budget for this mission is Rs. 700 Crores for 2024-25 as a central sector Scheme/Project, below from Rs. 869 Crores RE in 2023-24 as centrally sponsored scheme, a drastic decrease. This undermines our efforts to enhance the genetic potential and productivity of livestock. Similarly, the budget for the National Livestock Mission, aimed at sustainable growth and development of the livestock sector, has also been decreased. This mission, which is essential for improving livestock productivity, enhancing milk, meat, and egg production, and ensuring a sustainable supply of quality livestock products, has an allocation of Rs. 324 Crores for 2024-25, compared to Rs. 410 Crores RE in 2023-24.

The Animal Husbandry Infrastructure Development Fund, which is crucial for the modernization of infrastructure and ensuring quality in animal husbandry practices, has also not received the necessary boost. This fund, critical for building supply chains, processing facilities, and other infrastructure that can help increase farmers' income and improve productivity, stands at Rs. 370 Crores for 2024-25, compared to 340 RE Crore for 2023-24.

I urge the Government to revisit these allocations and consider a more substantial increase to support the animal husbandry and fisheries sectors adequately. Here are a few recommendations:

- Increase in Budget Allocation: Substantially increase the budget allocation for the Ministry to address the inflationary pressures and ensure sustainable growth in these sectors.
- Focus on Infrastructure Development: Enhance funding for the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund to modernize infrastructure and ensure quality in animal husbandry practices.
- Support for Indigenous Breeds: Provide more substantial support for schemes like the Rashtriya Gokul Mission to promote the conservation and development of indigenous breeds.
- Comprehensive Insurance Coverage: Implement comprehensive insurance schemes for livestock and fisheries to protect farmers against unforeseen losses due to diseases, natural disasters, and market fluctuations.

The current budget for the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying lacks the vision and commitment needed to support these crucial sectors. It falls short in addressing the pressing needs of inflation, infrastructure development, and sustainable growth. I urge the Government to reconsider these allocations and ensure that the budget truly reflects the importance of animal husbandry and fisheries in our economy and the livelihoods of millions of farmers.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखता हूँ।

आम बजट वर्ष-2024-25 में मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के लिए जितने बड़े पैमाने पर राशि का आवंटन किया गया है उसके लिए मैं माननीया वित्त मंत्री जी एवं माननीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

इस बजट में जिस प्रकार से मत्स्य पालन विभाग के लिए 2,616.44 करोड़ रूपये जो पिछले वर्ष-2023-24 में आवंटित राशि से 54% अधिक है एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2,352 करोड़ रूपये जो वर्ष-2023-24 में आवंटित राशि से 56% अधिक है। यह बढ़ोतरी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाली है। इससे जलीय कृषि में कई गुना बढ़ोतरी होगी।

बजट में प्रावधानित मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के तहत निजी उद्यमियों और निवेशकों को झींगा जल कृषि सुविधायें, प्रसंस्करण संयंत्र और निर्यात सम्बन्धी अवसंरचना स्थापित करने के लिए रियाती वित्तीय सहायता प्रदन की गई है। यह भी एक क्रांतिकारी कदम है इससे अवसंरचना में किये गए निवेश, किये गए प्रौद्योगिकी को अपनाने और मत्स्य पालन की कार्यप्रणालियों में सुधार से झींगा मूल्य श्रृखंला में उच्च उत्पादन एवं उत्पदाक्ता , वेहतर गुणवत्ता और बढ़ी हुई दक्षता प्राप्त होगी। इस कदम से वैश्विक और घरेलू बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण झींगा मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के साथ नये रस्ते खुलेंगें।

हम यह जानते हैं कि भारत वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 174.45 लाख तन (वर्ष-2023-24) के रिकार्ड उच्च मछली उत्पादन दर के साथ इसकी वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी है। भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दुसरे स्थान पर है और दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री भोजन निर्यात करने वाले देशों में से एक है। यह क्षेत्र 3 करोड़ से अधिक लोगों को स्थाई आजीविका प्रदान करती है, जिनमें से ज्यादातर हाशिय पर एवं कमजोर समुदायों के लोग है। इस स्थिति में वर्ष 2024-25 के आम बजट में मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के लिए बजट राशि में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करना यह दर्शाता है कि हमारी NDA सरकार और दुनिया में डंका बजाने वाले यशश्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी एवं गरीबों के कितने बड़े शुभचिंतक हैं।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे बिहार प्रदेश में मत्स्य पालक एवं जलीय कृषि करने वाले करोड़ों परिवार निवास करते हैं। ऐसे में मत्स्य पालन विभाग के लिए बजट आवंटन में की गई भारी वृद्धि से हमारे प्रदेश के भी हाशिय पर रहने वाले लोगों के साथ पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित, आदिवासी एवं गरीबों को भारी पैमाने पर लाभ होगा। इसके लिए मैं पुन: माननीया वित्त मंत्री जी एवं माननीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ साथ ही मैं अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के अंतर्गत इन कार्यों को कराने के लिए माननीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय (वेटनरी कॉलेज) खुलवाया जाये; महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रखंड मुख्यालयों पर दूध शीतलीकरण केंद्र स्थापित कराया जाये; परिस्कृत एवं आधुनिक ढंग से मत्स्य बीज एवं झींगा बीज की उत्पादन ईकाई स्थपित की जाये; मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण एवं सिवान जिला के बनियापुर, मशरक एवं भगवानपुर हाट के प्रखंडों में लगभग पांच हजार एकड़ वाले जल भराव के क्षेत्र में (बहिआरा चवर) में आधुनिक किस्म से मत्स्य पालन एवं झींगा पालन कराया जाये; मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण जिला के एकमा प्रखंड के अंतर्गत हजारों एकड़ वाले जल भराव के क्षेत्र में (धुरदह चवर) में आधुनिक किस्म से मत्स्य पालन एवं झींगा पालन कराया जाये और मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत हजारों एकड़ वाले जल भराव के क्षेत्र में (पन्दाहाँ चवर) में आधुनिक किस्म से मत्स्य पालन एवं झींगा पालन कराया जाये।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): I want to congratulate the Government, and especially the Ministry for the great job that it has done in completely destroying the potential for husbandry in India. Forget all other areas like fisheries or poultry, your so-called love for cows is also not showing in how your policies have worked so far. Cow population has continued to decline, and indigenous cattle breeds are declining at an even faster rate. BJP's former Bengal state president had once remarked that foreign breeds are "aunties" while indigenous cows are sacred. Unfortunately, neither mother nor aunt seems to be doing well. There is a mixed feeling in this Government.

On one end, the PM demonises those who eat meat during a particular festival, they shut down shops that sell meat, they want to promote vegetarianism. On the other hand, the ruling party has received 2 crores from beef exporting companies. Your Government had

announced a subsidy of 29610 crores for the promotion of meat processing units. If you want meat processing to increase, then the population of animals also has to increase. You cannot do that if gau rakshaks kill people who transport animals, you cannot do that if your Government prohibits farmers from selling cattle when it stops giving milk.

Basically, a farmer raises any cattle till it is productive. The moment it stops being productive, the farmer sells it to the butcher and recovers 1/3rd of the original cost of the cattle. This is then used to partially offset the cost of buying new productive cattle. Now, the new law makes it a crime to sell cattle knowing that it will be slaughtered. Plus, due to gau rakshaks, no one is willing to buy these unproductive cattle and therefore, the farmer is left with no money.

Cattle ownership as a percentage of total livestock ownership in India has declined from 37% in 2007 to 35% in 2019, In contrast, ownership of other livestock (buffalos, goats, sheep) has increased. It looks like this Government failed in Desh Raksha as well as Gau Raksha (2019 Livestock Census)

The population of total indigenous cattle has declined by 6% from 151.17 million in 2012 to Hissim. 142.11 million in 2019. The population of male animals in this category has declined from 61.95 million in 2012 to 43.94 million in 2019.

Livestock Census points out that there is a significantly lower percentage increase in the female cattle population during 2012-2019, as compared to 2007-2012, in states which have tightened their slaughter laws, as compared to states with no ban on cow slaughter.

There is substantial increase in stray cattle population in states with higher anti-cow slaughter activity (whether by Government or by mobs) such as Uttar Pradesh (17.34 per cent), Madhya Pradesh (95 per cent), Rajasthan (34.48 per cent), Gujarat (17.59 per cent), Chhattisgarh (33.93 per cent) and Punjab (38.69 per cent) in 2019 in comparison to 2012. States with weaker cattle slaughter laws seem to have fewer stray cattle.

In other words, the fear of gau rakshaks and the pressure of not being able to sell unproductive cattle has resulted in a situation where (a) cows are abandoned (b) farmers are not raising cows anymore (c) bulls/bullocks are not being bred (which means the future of many cow species will be at risk)

Stricter laws will mean the eventual extinction of cows. Data says that 40% of buffalos are slaughtered each year, and still buffalo population has increased by 150% since 1951-2019. In contrast, cow population has only increased by a modest 5 lakh per year.

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : मेरे क्षेत्र में पशुपालन एवं डेयरी हेतु मेरी मांग हैं कि जो गाय गौशाला व गो संवर्धन केंद्र में है देशी हैं उन्हें हाइब्रिड सीमेन क्रॉस करके अच्छी किस्म पैदा की जा सकती है; दुग्ध संरक्षण के लिए दुग्ध संरक्षण केंद्र बनाया जाए ; अच्छे नस्ल की गाय, भैंस व बकरी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को दिया जाए और अच्छे क्वालिटी के फीड (पशु) मिले इस हेतु संयम स्थापित किया जाए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): In the budget that are good initiatives with regard to the Reduction in duty on food providing hostel facilities for women working in processing industry. MUFPI has done exceedingly well in increasing processing capacity in India.

With regards to Fisheries Infrastructure development fund most of it is used by the State Governments. It is not nudging private players who does 90% of production, processing and exports to utilize this fund. We need to encourage private players and farmers to utilize this fund to come up with better aqua culture practices which will result in higher yield for farmers. Under PMMSY 5 lakhs is given to cage farming, farm upgradation, nursery.

We need to keep in mind that majority of farmers are holding above 10 acres of farm ponds and 5 lakhs is too less for any proper intervention to be made by farmers.

Indian farmers are producing 2-2.5 ton per acre where as farmers in Vietnam producing 5-6 ton per acre.

We need to come up with new scheme or make another provision for farmers in PMMSY so that farmers can upgrade their farms by adding new technologies which will be costing 2-2.5 lakh per acre.

Coming to animal husbandry infrastructure development funds and NCM Scheme there are lot of entrepreneurs who have applied for dairy processing, meat processing, breed multiplication and thus were approved for the loan 2 years back. Till now the loan has not be released. So I request the Minister to look into it so that entrepreneurs and farmers can avail these loans in time without losing interest.

SHRI NARESH GANPAT MHASKE (THANE): I would like to express my views on the Demand for Grants on the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

Today we are discussing a Ministry that involves 65 percent of the people in India who are engaged in agriculture and allied activities directly. Animal Husbandry, Dairy and Fisheries is a crucial sector for our economy, because it has the potential to double our farmers income and realize the vision of our Hon'ble Prime Minister.

I represent Odisha, where the BJP was blessed with a huge mandate and we had our own Government for the first time and this was possible only because the farmers and most importantly the fishermen of Odisha blessed us and gave us an opportunity to serve them.

Livestock sector is the second largest sub-sector next to crop production, contributing nearly 15 per cent of the total gross value added (GVA) of agriculture and allied activities in the State of Odisha.

To ensure availability of quality brood for quality seed, Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman announced the financial support for setting up a network of Nucleus Breeding Centre (NBC) for shrimp brood stocks.

Further, financing for shrimp farming, processing and export will be facilitated through NABARD. Establishment of state-of-art facilities in NBCs will improve the genetic quality of aquaculture species for higher productivity and quality, reduce the dependence on import of shrimp brood stock.

This is a welcoming step to promote the shrimp industry, as shrimp is a major contributor to seafood export. Shrimp exports have significantly growth to Rs. 40,013 crore in 2023-24 from Rs. 8,175 Crore in 2011. In 2023-24, the export of frozen shrimp was to the tune of 7.16 lakh ton worth Rs. 40,013 crore.

Of the total agriculture production, milk alone accounts for eight per cent of the total output. Cattle in the state account for 5.12 per cent of the total cattle population in the country.

From 2014-15 to 2022-23, the livestock sector grew at an impressive Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 7.38 per cent at constant prices. The contribution of livestock to the total GVA (at constant prices) in agriculture and allied sectors increased from 24.32 per cent in 2014-15 to 30.38 per cent in 2022-23.

In 2022-23, the livestock sector contributed 4.66 per cent of the total GVA, significantly boosting the per capita availability of milk, eggs, and meat.

The fisheries sector, a crucial contributor to the Indian economy, makes up about 6.72 per cent of the agricultural GVA and has grown at compound annual rate of 8.9 per cent between 2014-15 and 2022-23 (at constant prices).

The Government has allocated a budget of Rs. 4521 crore to the Department of Animal Husbandry and dairying, which is 194 crore higher than 2023-24.

Economic Survey states that the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) facilitates investments and government provides a 3 per cent interest subvention to the borrower and a credit guarantee of up to 25 per cent of total borrowing.

As of May 2024, 408 projects have been sanctioned by the lending banks/ NABARD/NDDB worth 13.861 Crore, generating 40,000 direct employment opportunities and benefiting more than 42 lakh farmers.

The Rashtriya Gokul Mission has been allocated 700 crore rupees this year and through this scheme the government works exclusively for development and conservation of indigenous bovine breeds in a scientific holistic manner. As on date7.13 crore animals have been covered, 8.81 crores Artificial Insemination have been performed and 4.75 crores farmers benefitted under the programme.

National Programme for Dairy Development (NPDD) has been allocated 371 crore is being implemented across the country with an objective of creating/strengthening of infrastructure for Production of quality milk.

Under the scheme, 17.45 lakh new farmers were given benefit of membership of dairy co-operative societies and 83.56 lakh litre of additional milk procured under the projects. About 24.82 lakh litres per day new milk processing capacity has been established and 4193 Bulk Milk Coolers with 94.12 lakh litres chilling capacity has been created at village level.

About 233 dairy plant laboratories have also been equipped to detect adulterants in milk and milk products and about 10 State Central laboratories have been established for detection of residues, contaminants, heavy metals, adulterants, chemical and microbiological quality of milk and milk products.

Livestock Health and Disease Control Programme (LHDCP) has been allocated 2465 crore rupees and through this government supplements the efforts of the State Governments/Union Territories by way of financial assistance, which is a Central sector scheme, with the aim of reducing risk to animal health by prophylactic vaccination against diseases of animals, capacity building of Veterinary services, discase surveillance and strengthening Veterinary infrastructure.

The Department of Fisheries has been allocated Rs. 2616 crore which is Rs. 368 crore higher than the last year.

To address the sector's infrastructure needs, the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) was introduced in 2018-19 with a total fund size of 7.52 Thousand Crore. So far, 121 proposals have been recommended for 5.59 Thousand Crore as a concessional rate.

The Department of Fisheries, (DoF) Government of India (Gol) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) is promoting coastal aquaculture in all coastal States and Union Territories (UTs). Rs. 2,352 crore has been allocated for Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana scheme.

Projects worth Rs.179.50 crore have been approved under PMMSY for activities including genetic improvement programme of Penaeusindicus, Broodstock Multiplication Centre (BMC) of P. monodon, construction of brackish water ponds in 1381 hectare of land and

20 shrimp hatcheries.

As reported by Coastal Aquaculture Authority (CAA), during last three years, 5544 coastal aquaculture farms have been established in coastal State and UTs. And I am proud to say that the second highest number of coastal aquaculture- 1913- have been established in Odisha.

The shrimp production from brackish water aquaculture has been increased from 8.42 lakh tonne during 2020-21 to 11.84 lakh tonne during 2022-23.

The brackish water aquaculture has positively impacted the Scafood Industry by increasing the seafood export from Rs.43,721 crore during 2020-21 to Rs.63,969 crore during 2022-2023. Out of Rs.63,969 crore seafood export, shrimp alone has contributed to Rs. 40,013 crores.

To strengthen India's shrimp farming industry globally, import duty reductions on key inputs are proposed for lowering production costs and increase revenues and profit margins.

To strengthen India's position as a leader in value-added fish processing, import duties on value-added fish processing ingredients - pre-dust breading powder duty has been removed.

Finance Minister also announced that the Government will bring out National Co-operation Policy for systematic, orderly and overall development of the co-operative sector.

I would request the Hon'ble Minister to provide special assistance to the State of Maharashtra which has tremendous potential for dairy and fisheries sector which can not only help in improving the human development index but also act as a catalyst for economic development.

To sum up the strategic support for the animal husbandry, dairies and fisheries sector in the Budget 2024-25 will lead to inclusive and holistic development of the sector by providing the required fillip to enhance production and productivity of milk, fish, fish seeds and fish value added products.

The allied sectors of Indian agriculture are steadily emerging as robust growth centres and promising sources for improving farm incomes.

I support the Demand for Grants.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : मैं मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों पर अपने विचार रखता हूँ।

देश की अर्थव्यवस्था और देश के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे नागरिको की आजीविका के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है और इस बात को समझने के बाद जब आजादी के 75 वर्षों बाद हम देश के पशुपालको के बारे में सोचते है और देखते है तो यह सामने आता है की पशुपालको के लिए सरकारों ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक हो।

आज जब हम रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं तो वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64 प्रतिशत योगदान देकर भारत दूध उत्पादन में पुरे विश्व में अग्रणी एक नंबर पर है, मैं पूर्व पशुपालन और डेयरी मंत्री बाल्यान जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमे उन्होंने कहा की देश की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र का 5% योगदान है और 8 करोड़ लोगो के रोजगार का साधन डेयरी क्षेत्र है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ की विभिन्न योजनाओ के बाद भी किसानो और पशुपालको के जीवन मे आमूलचूल परिवर्तन क्यों नहीं आया ? खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है ऐसे में सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरुरत है।

मेरा राजस्थान राज्य भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका लोगो को रोजगार देने और राज्य की अर्थव्यवस्था में है, ये क्षेत्र न केवल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि यहां की बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं लेकिन इन विभागों में कर्मचारियों और अनुभवी अफसरों की कमी के कारण पशुपालको को योजनाओ का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता ।

मैं मंत्री जो बताना चाहता हूँ कि नाबार्ड एक शिर्ष नियामक निकाय है जिसके माध्यम से पशुपालन हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है लेकिन दुर्भाग्य इस बात है की आज जिलों में नाबार्ड में एक- एक कोर्डिनेटर लगे है, जो अपनी मर्जी से कार्यालयों का संचालन करते है, लोगो को ध्यान ही नहीं है की इसका भी कोई ऑफिस है क्या ? मंत्री जी जिला कलक्टर कार्यालय के परिसर में या कृषि विभाग के कार्यालय में नाबार्ड के ऑफिस का संचालन हो इसके निर्देश आवश्यक रूप से जारी हो।

आज पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा हो रही है। मैं पशुपालन मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की मेहनतकश और बड़ी पशुपालक कौम देवासी समाज जिन्हे रैबारी या राइका भी कहा जाता है, उनकी स्थिति की तरफ आकर्षित करूंगा, देवासी समाज भेड़, बकरी व ऊंट का पालन करता है, उन्हे चराने के लिए वो राजस्थान से एमपी के मालवा और अन्य स्थानों पर जाते है, इस समाज के साथ जाट व गुर्जर समाज भी राजस्थान की मुख्य पशुपालक कौमे है, इनके हितों के लिए आपको कदम उठाना चाहिए, आज भेड़, बकरी और ऊंट के अस्तित्व के संरक्षण के लिए भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, जोधपुर में उप नगरीय रेलवे स्टेशन राईका बाग स्टेशन जिसके साथ देवासी समाज की भावनाएं जुड़ी है, राई और का शब्द के मध्य रेलवे की गलती से स्पेस रह गया उस स्पेस को खत्म करके त्रुटि सुधार के आदेश निकलवाने के लिए आप रेल मंत्री जी से बात करे ताकि इस पशुपालक कौम, देवासी समाज की भावनाओ का सम्मान हो सके।

आज आजादी के दशकों बाद देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र का बड़ा योगदान होने के बावजूद जब देश में लम्पी स्किन बीमारी आई, और गौ वंश तड़प-तड़प कर मर रहे थे और चाहे स्टेट हो चाहे केंद्र हो उन सभी को योजनाओ की पोल खोल गई जिसमे वो दावा करती है की हम पशुधन की बीमारियों को नियंत्रित करने में व उनके उपचार में सफलता हासिल कर ली, एक तरफ भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्स्व मना रही थी दूसरी तरफ लाखो गाये तड़प-तड़प कर दम तोड़ रही थी और पुरे देश का सिस्टम बेबस नजर आ रहा था।

मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र के बैल, जिन्हें नागौरी बैल कहा जाता है उनकी उन्नत नस्ल पुरे देश में विख्यात है, खेती के लिए लोग नागौरी बैल महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश, सहित कई राज्यों में लेकर जाते थे। वहां बहुत बड़ा पशु मेला लगता है लेकिन दुर्भाग्य से जब से हाईकोर्ट ने 3 वर्ष या उससे कम उम्र के गौ-वंश के विक्रय और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया है तब से नागौरी बैल की नस्ल पर संकट आ गया है।

यह दुर्भाग्य है की हाईकोर्ट ने जब इस संबंध में प्रतिबंध लगाया तो जिम्मेदार अफसर बछड़े और बैल की परिभाषा की व्याख्या ही नहीं कर पाए ऐसे में आप संज्ञान लेवे और ऐसे प्रतिबंध को हटाएं। साथ ही मंत्री जी पशु मेले में से जब कोई किसान, पशुपालक कृषि कार्य के लिए बैल खरीदकर ले जाते हैं, उनके पास पुरे सर्टिफिकेट होते है बावजूद इसके उन्हें अन्य राज्यों की सीमाओं पर रोक लेते है, हाल ही मेरे नागौर के मेड़ता में हुए पशु मेले से बैल खरीदकर ले जाने वाले पशुपालको को एमपी में प्रताड़ित किया गया, ऐसा ही चलता रहा तो पशु मेलों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, जबकि पशु मेलो से भी किसानो और पशुपालकों को आय होती है।

मंत्री जी मेरे कुछ सुझाव हैं:

- सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की है, राज्य सरकारों को पर्याप्त नियमित स्टाफ के लिए पाबन्द किया जाए।
- ग्रामीण इलाकों में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सरकार विफल रही है। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगो, पशुपालको की बुनयादी समस्याओ का स्थाई हल निकाला जाये।
- कृषि में पशुपालन का एक तिहाई योगदान है, किसानों को भारत सरकार किसान सम्मान निधि देती है, मेरी मांग है की पशुपालको के लिए भी पशुधन सम्मान निधि जैसी योजना बनाई जाये ताकि पशुपालको को मदद मिल सके ।
- आज पूरा देश बेसहारा पशुओ की समस्या से झुंझ रहा है और सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारण है इस पर ध्यान दिया जाए।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ती है इस पर मंत्री जी ध्यान देवे।
- कृषि और पशुपालन क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए है लेकिन दोनों विभागों में आपसी तालमेल के अभाव के कारण नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित होता है।
- सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व डेयरी विकास से के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने चाहिए।

- केसीसी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, किसानों को बैंक की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते कई ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं अभी भी सीमित हैं। किसानों को बैंक तक पहुंचने में कठिनाई होती है, जिससे वे केसीसी योजना का लाभ नहीं उठा पाते, कई किसानों के पास पर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, जिससे बैंक उन्हें ऋण देने में हिचकिचाते और जिस किसने के जमीन है उसे तो पशुपालन हेतु केसीसी के साथ कुछ राशि अलग से लोन के रूप में दी जाती है लेकिन भूमिहीन पशुपालको को बैंक लोन नहीं देती , आनाकानि करती है, आप गंभीरता से इस संबंध में वित्त मंत्री जी बात करके समाधान निकाले ताकि गरीब पशुपालको को भी लाभ मिल सके।
- ग्रामीण क्षेत्रो में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी से डेयरी उत्पादों का सही तरीके से संरक्षण नहीं हो पाता और प्रसंस्करण इकाइयों के अभाव के कारण भी उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्यवर्धन में कमी आती है इस पर सरकार को ध्यान देने की जरुरत है।
- पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में अनुसंधान और विकास के लिए कम निवेश किया जाता है इन क्षेत्रो में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जाये। विशेषकर गाँवों में डेयरी क्षेत्र में नई और उन्नत तकनीक से पशुपालकों को जोड़ा जाये।
- पशुओं की विलुप्त होती प्रजातियों के अस्तित्व को बचाया जाए।

प्रमुख मांगें:

- राजस्थान और कृषि प्रधान और पशुपालन प्रधान राज्य है, मेरी मांग है की पशुओं में वायरस जनित रोगो की जाँच और पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर की लैब राजस्थान में स्थापित की जाये।
- मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में राष्ट्रीय स्तर की वेटनरी कॉलेज खोला जाए।
- राजस्थान में डेयरी क्षेत्र से जुड़ा राष्ट्रीय स्तर का अनुसन्धान केंद्र खोला जाए।
- नागौर में प्रत्येक वर्ष होने वाले रामदेव पशु मेले में पशुओं के अन्य राज्यों के परिवहन के लिए ट्रेन संचालन की दिशा में पशुपालन मंत्री जी को रेल मंत्रालय से बात करनी चाहिए।
- हमारे राजस्थान में ऊंट के अस्तित्व पर संकट है, ऊंट न केवल पशुपालको के लिए बल्कि बाड़मेर-जैसलमेर से लगी पाकिस्तान की सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए भी फौज के काम आता है, मेहनतकश कौम देवासी समाज ऊंट पालन में रूचि रखते है, आप ऊंट प्रजाति के संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम उठायें और केंद्र द्वारा ऊंट पालने वाले पशुपालकों को विशेष आर्थिक सहायता देने की जरुरत है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : भारत में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन क्षेत्रों में कई सुधार और विकासात्मक योजनाएँ लागू की गई हैं। हम इन योजनाओं, उनके प्रभाव और भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
- भारत में पशुपालन एक प्रमुख कृषि गतिविधि है, जो लाखों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का स्रोत है।
- भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। 2020-21 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन 209.96 मिलियन टन था, जो 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से काफी अधिक है।
- भारत में लगभग 135 मिलियन बकरियों और 74 मिलियन भेड़ें हैं। ये छोटे रुमिनेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और पोषण सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने, उनकी नस्ल सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- देशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए यह एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का उद्देश्य देशी गायों की नस्लों की उत्पादकता बढ़ाना और उन्हें उन्नत बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना है।
- भारत का डेयरी उद्योग विश्व का सबसे बड़ा है और यह कृषि जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दुग्ध उत्पादनः 2020-21 में कुल दुग्ध उत्पादन 209.96 मिलियन टन था, जो 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से 43% अधिक है।
- भारत में लगभग 1.9 लाख डेयरी सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 17 मिलियन से अधिक किसान सदस्य हैं।
- भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है और यह लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। मत्स्य उत्पादनः 2020-21 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 14.73 मिलियन टन था, जो 2014-15 के 10.07 मिलियन टन से 46% अधिक है।

- 2020-21 में भारत का कुल मत्स्य निर्यात मूल्य 6.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना, समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों की खेती को बढ़ावा देना और मछुआरों की आजीविका में सुधार करना है।
- मत्स्य सहकारी समितियां: मछुआरों को सहकारी समितियों के माध्यम से संगठन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 2024 के केंद्रीय बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।
- पशुपालन और डेयरी: 2024-25 के बजट में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए 4,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% अधिक है।
- मत्स्य पालन: 2024-25 के बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15% अधिक है।
- पशुपालन और डेयरी में तकनीकी उन्नयन, जैसे जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।
- किसानों और मछुआरों को बेहतर बाजार सुविधाएँ और उचित मूल्य दिलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
- पशुओं और मछलियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अधिक स्वास्थ्य सेवाओं और टीकाकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- किसानों और मछुआरों को नवीनतम तकनीकों और पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से इन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और स्थिरता में वृद्धि हुई है।
- भविष्य में भी इन प्रयासों को जारी रखते हुए, हमें देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना है।

SHRI ARUN BHARTI (JAMUI): I support the Demand for Grants regarding the critical and transformative sectors of Animal Husbandry, Dairy, and Fisheries in India. These sectors not only play a pivotal role in the country's rural cconomy but also significantly contribute to food security, employment, and the overall growth of our nation.

- Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, substantial progress has been made in these areas over the past decade.
- Animal husbandry is a cornerstone of India's agricultural economy, providing livelihood to millions of rural houscholds. The sector includes a diverse range of livestock such as cattle, buffalo, sheep, goats, pigs, and poultry.
- In the Union Budget 2024, the Government has allocated Rs 4,500 crore for the animal husbandry and dairy sector. This is a significant increase from previous years, reflecting the Government's commitment to strengthening this sector.
- National Livestock Mission: Launched to enhance livestock productivity and ensure the availability of quality feed and fodder. This mission focuses on breed improvement and healthcare of livestock.
- Rashtriya Gokul Mission: Aimed at the development and conservation of indigenous bovine breeds. It includes setting up Gokul Grams as integrated cattle care centers.
- E-Pashu Haat Portal: This online portal facilitates the trade of livestock, ensuring farmers get a fair price for their animals.
- Animal Health and Disease Control Program: Intensified efforts to control animal diseases through regular vaccination and treatment programs.
- Livestock Insurance Scheme: Providing insurance coverage to farmers to protect against the loss of their livestock.
- The dairy sector is a major component of India's agricultural economy, contributing around 4% to the GDP.
- Milk Production: As mentioned earlier, milk production reached 209.96 million tons in 2020-21, showing a steady growth.
- Dairy Cooperatives: Around 1.9 lakh dairy cooperative socicties are operational in India, benefiting over 17 million farmers.

- National Dairy Plan: this plan focuses on increasing milk production, improving breeding and feeding practices, and providing better market access to farmers.
- Kisan Credit Card Scheme: Extended to dairy farmers, this scheme provides them with timely credit for their working capital needs.
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme: Aimed at generating self employment and providing infrastructure for the dairy sector.
- Dairy Processing and Infrastructure Development Fund (DIDF): Established to provide support for the modernization of milk processing units and value addition.
- Milk Chilling Centres: Establishing village-level milk chilling centres to ensure the quality and longevity of milk.
- India's fisheries sector is the second-largest producer of fish in the world, contributing significantly to the national income and providing employment to millions.
- Fish Production: Fish production in India was 14.73 million tons in 2020-21, up from 10.07 million tons in 2014-15.
- Exports: The export value of fish and fish products was $6.68 billion in 2020-21.
- Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): Launched to enhance fish production and productivity, this scheme aims to achieve a fish production target of 22 million tons by 2024-25.
- Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF): Provides concessional finance to develop infrastructure facilities in fisheries and aquaculture.
- Kisan Credit Card Scheme: Extended to fish farmers, enabling them to access timely credit.
- Blue Revolution: Promotes sustainable fishery practices and increasing fish production through various initiatives.
- Harith Matsya Kranti: Aimed at promoting sustainable and eco-friendly practices in the fisheries sector.
- Technological Upgradation: The Government has focused on technological advancements in animal husbandry, dairy, and fisheries. This includes the use of genomics, biotechnology, and digital platforms to improve productivity and efficiency.
- Training and Skill Development: Numerous training programs have been initiated to educate farmers and fishermen about modern practices and techniques. This enhances their skills and increases productivity.
- Market Reforms: Digital marketing platforms and e-commerce have been promoted to provide farmers and fishermen with better market access and fair prices for their products.
- Health and Safety: Veterinary health services and vaccination programs have been intensified to ensure the health and well-being of livestock.
- Research and Development: Emphasis on R&D has led to the development of new and improved breeds of livestock and fish, better discase management practices, and sustainable farming techniques.
- Sustainable Fisheries: The Government is promoting sustainable fishing practices to protect marine biodiversity and ensure the long-term viability of the fisheries sector.
- Green Practices in Dairy: Solar energy initiatives and waste management systems are being implemented to reduce the environmental impact of dairy farming.
- Climate Adaptation: Strategies are being developed to mitigate the effects of climate change on animal husbandry, dairy, and fisheries. This includes the promotion of climate-resilient breeds and farming practices.

India is also actively engaging in international collaborations to share knowledge, technologies, and best practices in animal husbandry, dairy, and fisheries. These collaborations help in adopting global standards and improving domestic practices.

- The focus on technological advancements, capacity building, and market reforms has not only improved productivity but also ensured better livelihood opportunities for millions of farmers and fishermen.

In conclusion, the Modi Government's strategic initiatives and substantial investments have transformed the dairy and fisheries sectors in India, driving growth, sustainability, and prosperity. As these sectors continue to evolve, they hold the promise of further strengthening India's rural economy and ensuring food security for the nation. Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : मैं मछली, पशु-पालन एवं डेयरी मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखता हूँ।

कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत की प्रगति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक विशेष उल्लेखनीय रही हैं। इस क्षेत्र में क्रांतिकारी दौर आए, जिन्होंने देश के नाते खाद्यान उत्पादन और उपभोग आदि पर हमारी आत्मनिर्भरता बढाई हैं। सुखद बात यह हैं कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जेसे दौर के बाद अब यह सेक्टर तकनीक कि क्रांति से लाभान्वित हो भारत को इस क्षेत्र में मजबूत धरातल दे रहा हैं। 18.2% की हिस्सेदारी हैं कृषि की देश के सकल घरेलू उत्पादन मे, (economic survey 2023-24)।

अब अगर हम विशेषकर कृषि के अन्य क्षेत्र जैसे पशु-पालन, मछली- पालन तथा डेयरी की बात करे। भारत दूध उत्पादन में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान रखता है, जो दुनिया के कुल का लगभग 25% योगदान देता है। पिछले आठ वर्षों में, देश ने दूध उत्पादन में 51% की वृद्धि हासिल की है। डेयरी क्षेत्र, कृषि मंत्रालय के भीतर सबसे बड़ा एकल क्षेत्र, राष्ट्रीय आय में 5% का योगदान देता है और पिछले पांच वर्षों में 6.4% (CAGR) का अनुभव किया है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के डेयरी उद्योग की जड़ें गहरी हैं। डेयरी फार्मिंग के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं, जहां ज़ेबू मवेशियों को पालतू बनाया गया था। वैदिक काल के दौरान, डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से दूध, को आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। प्राचीन ग्रंथों में 'पलाश' पौधे का भी उल्लेख है, जिसके पदार्थों का उपयोग दही बनाने के लिए किया जाता था। बौद्ध और जैन ग्रंथ इसी तरह चावल और दूध को महत्वपूर्ण आहार स्टेपल के रूप में उजागर करते हैं।

1940 के दशक में, एक आधुनिक डेयरी उद्योग के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, श्री त्रिभुवनदास पटेल को डेयरी और दूध प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करने का काम सौंपा गया था। इससे 1946 में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में अमूल की स्थापना हुई, जिसने भारत में संगठित डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की।

भारत में दूध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

In 1951-17 million tonnes,

in 2011-121.8 million tonnes and

in 2021-210 million tonnes.

India's dairy industry is projected to expand to $380 billion by 2028, up from $182 billion in 2022, with a CAGR of 13.2% from 2023 to 2028. और मुझे इस बात पर को कहने मे भी बहुत खुशी हो रही हैं उत्तर प्रदेश भारत मे दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं जो कि कुल भारत के उत्पादन का 15% उत्पादित करता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच अभी तक राजनीतिक अनिश्चितताएं, भारत की आर्थिक वृद्धि कम और stable inflation rate के साथ अच्छी बनी हुई है। आने वाले वर्षों में विकास मजबूत रहने की उम्मीद है।

कृषि के तहत संबद्ध क्षेत्रों के बीच 8.9% (वित्त वर्ष 2014-2023) की उच्चतम औसत दशकीय वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के 'sunrise sector' के रूप में जाना जाता है,

भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र अपनी पहचान बना रहा है और बहुत स्वस्थ गति से बढ़ रहा है।

विश्व में भारत की स्थिति भारत के दूध उत्पादन में पिछले नौ वर्षों के दौरान यानी वर्ष 2014-15 और 2022-23 के दौरान 58% की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2022-23 में बढ़कर 230.58 मिलियन टन हो गया है। (राज्य में उत्तर-प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर)

भारत वर्तमान में वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी और 174.45 लाख टन (2023-24) के रिकॉर्ड उच्च मछली उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत जलीय कृषि उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है और दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री खाद्य निर्यातक देशों में से एक है। यह क्षेत्र 30 मिलियन से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है, जो ज्यादातर हाशिए पर और कमजोर समुदायों के भीतर हैं।

भारत में पशुधन और मुर्गी पालन का एक विशाल संसाधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Budgetary allocation

इस बजट में कुल बजटीय आवंटन 7,347.68 करोड़ है।

Department	Budgetary allocation 2024-25	Revised estimate 2023-24	Change in %
Fisheries	2,616 crore	1,701 crore	54% increased
Animal husbandry	4.931 crore	4,183 crore	17.88% increased

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात 57 से अधिक देशों को 134.04 मिलियन डॉलर के कुल मूल्य के साथ उल्लेखनीय 6,64,753 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। **'Reform-Perform-Transform'** के आदर्श वाक्य के साथ, भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक प्रमुख चालक के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखती है।

Since First Five Year Plan to 2013-14 Rs. 3,680 crore 2014-15 to 2023-24 Rs.6,378 crore has already been released for various fisheries developmental activities in the country. वर्ष 2024-25 के लिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) योजना के लिए 2,352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन से 56% अधिक है। **'Reform-Perform-Transform'** के आदर्श वाक्य के साथ, भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक प्रमुख चालक के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2021-22 तक 13.36% की CAGR से बढ़ा।

The total contribution of allied sector in agriculture

2014-15-24-32%

2022-23-30.13%

पशुधन क्षेत्र ने 2020-21 में कुल GVA में 4.90% का योगदान दिया।।

भारत में पशुधन और मुर्गी पालन के विशाल संसाधन हैं, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 303.76 मिलियन गोजातीय (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक) हैं। देश में 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और 851.81 मिलियन कुक्कुट हैं।

डेयरी सबसे बड़ी कृषि वस्तु है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करती है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे रोजगार देती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 24.64% का योगदान देता है। पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 51.05% की वृद्धि हुई है, 2014-15-146.3 Mn tonne, 2021-22-221.06 Mn tonne. पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है जबकि विश्व दूध उत्पादन प्रति वर्ष 1.2% की दर से बढ़ रहा है। 2021-22 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 444 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि 2021 के दौरान विश्व औसत 394 ग्राम प्रतिदिन है।

Milk production- change 67.4% increase since 2013-14.

Year	In million tonnes	Per capita availability
2013-14	137.7	307 gm
2022-23	230.6	459gm

सरकार की पहल जो विशेष क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होती है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन-

2014 में शुरू हुआ। इस योजना को अम्ब्रेला स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत 2021 से 2026 तक 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ जारी रखा गया है। इस योजना के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और इस कार्यक्रम का लाभ डेयरी उद्योग में लगे 80 मिलियन किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचेगा।

2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में स्वदेशी नस्लों में सुधार के लिए की गई उपलब्धियों का विवरण इस प्रकार है:

- **आईवीएफ का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम:**

त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 2 लाख आईवीएफ गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे। किसानों को 5000 रुपये प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

- **लिंग क्रमबद्ध वीर्य उत्पादन :**

अगले पांच वर्षों के दौरान 51 लाख गर्भधारण स्थापित किए जाएंगे और किसानों को सुनिश्चित गर्भावस्था पर 750 रुपये या छांटे गए वीर्य की लागत की 50% सब्सिडी उपलब्ध होगी।

- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** :

प्रमुख कार्यक्रम "राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP)" माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2019 को 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज वाले 605 जिलों में शुरू किया गया था। अब तक, 4.41 करोड़ जानवरों को कवर किया गया है, 5.44 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, और कार्यक्रम के तहत 2.93 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। 2023-2024 के दौरान 592 जिलों में 3 करोड़ पशुओं के गर्भाधान का लक्ष्य रखा गया है।

- **Establishment of Gokul Gram**
- **National Gopal Ratna Award 2022**

2. NATIONAL PROGRAMME FOR DAIRY DEVELOPMENT:

फरवरी 2014 से, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) द्वारा गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और दूध और दूध उत्पादों के विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने / मजबूत करने का उद्देश्य।

NPDD के तहत उपलब्धियां:

185 projects in 28 States and 2 Union Territory have been approved with the total cost of Rs. 3015.35 crore (Central Share Rs. 2297.25 crore) from 2014-15 to 2022-23. A total sum of Rs. 1,690 crore has been released for implementation of new projects approved

under the scheme up to 2023. An amount of Rs. 1,195 crore has been utilized under the projects approved.

Physical Process:

15.01 लाख नए किसानों/दूध उत्पादकों के नामांकन और किसानों से 39.12 लाख लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद के साथ 15,054 डेयरी सहकारी समितियों का संगठित / पुनरुद्धार किया गया। 23,798 डेयरी सहकारी समितियों को स्वचालित दूध संग्रह इकाई की स्थापना के साथ मजबूत किया गया- किसानों को दूध परीक्षण और भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए। किसानों को बाजार तक पहुंच प्रदान करने और दूध को खराब होने से बचाने के लिए 64.20 लाख लीटर शीतलन क्षमता वाले 3220 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए हैं। दूध और दूध उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए 4,243 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण और 120 FTIR प्रौद्योगिकी आधारित दूध विश्लेषक / खाद्य स्कैन / NIRS टेक दूध पाउडर विश्लेषक स्थापित किए गए हैं। इससे किसान गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किसानों से खरीदे गए अतिरिक्त दूध को संसाधित करने और विपणन के लिए 22.90 लाख लीटर प्रतिदिन नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई। 15 राज्यों में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना और दूध की गुणवत्ता की जांच करने, उपभोक्ता स्वीकृति और बाजार बढ़ाने के लिए जिला सहकारी दुग्ध संघों की दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करना।

3. National Livestock Mission

डेयरी और कुक्कुट क्षेत्रों में प्रजातियों और क्षेत्रों में प्राप्त सफलता का अनुकरण करके पशुधन क्षेत्र के सतत और निरंतर विकास के लिए, 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) शुरु किया गया था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पहली बार, केंद्र सरकार व्यक्तियों, SHGs, JLGs, FPOs, धारा 8 कंपनियों, एफसीओ को हैचरी और ब्रूडर मदर यूनिटों के साथ पोल्ट्री फार्म, भेड़ और बकरी नस्ल गुणन फार्म, सुअर पालन और चारा इकाइयों के साथ पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के लिए सीधे 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन गतिविधियों के लिए सब्सिडी इकाइयां निम्नानुसार हैं: पोल्ट्री फार्म गतिविधियाँ: रु. 25 लाख तक, भेड़ और बकरी नस्ल गुणन फार्मः 50 लाख रुपये, पिगरी नस्ल गुणन फार्मः 30 लाख रुपये और चारा और चारा इकाई: 50 लाख रुपये। NLM के तहत लागू उद्यमिता घटकों के तहत, 2023 तक, DAHD द्वारा 439 आवेदनों को मंजूरी दी गई है, SIDBI को 22.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 20.52 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। Under NLM, 33,310 **Rural Backyard Sheep & Goat Development Units** were established. 21.16 lakh animals were covered under **cluster based mass deworming programme. 71 lakh animals were insured under NLM.** Under Entrepreneurship Development and Employment Generation (EDEG), till date, total 71,637 beneficiaries are given subsidy of Rs 64,525 Lakh.

4. KISAN CREDIT CARDS (KCC) FOR DAIRY FARMERS OF MILK COOPERATVES AND MILK PRODUCER COMPANIES.

भारत सरकार ने पहली बार 2019 के दौरान पशुपालन और डेयरी किसानों को केसीसी का लाभ दिया है। आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में। वर्ष 2023 तक DFS (वित्तीय सेवा विभाग) की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान के तहत 22,63,424 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21,87,347 आवेदन स्वीकार किए गए और 11,38,834 स्वीकृत किए गए। livelihood यह क्षेत्र 30 मिलियन से अधिक लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करता है, जो ज्यादातर हाशिए पर और कमजोर समुदायों के भीतर हैं।

कृपया राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तरह पूरे वर्ष राष्ट्रीय गोकुल मिशन को खोलें। वर्तमान में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन केवल उन किसानों का समर्थन करता है जिनके पास 200 से अधिक गायों की स्थापना है। मेरा सुझाव है कि कम से कम 50 गायों वाले किसानों को शामिल करने के लिए इस आवश्यकता को संशोधित किया जाए। इस समायोजन से गरीब और सीमांत किसान मिशन से लाभान्वित होंगे। भारत में राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर कोई प्राधिकरण नहीं है जो पशु आहार की गुणवत्ता और मानकों को विनियमित करता है, इसलिए मैं सरकार को एक प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव देता हूं जो पशु फ़ीड को विनियमित करता है। अभी तक दूध के लिए कोई तय मूल्य तय नहीं किया गया है। देश में कुछ स्थानों पर दूध 30 रुपये प्रति लीटर और कई स्थानों पर दूध 80 रुपये प्रति लीटर में उपलब्ध है। तो मेरा सुझाव है कि देश में दूध की न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, जिससे नीचे दूध नहीं बेचा जा सकता है।

मैं अपने इन्ही शब्दों के साथ इस मछली, पशु-पालन एवं डेयरी मंत्रालय अनुदानों कि मांगों का पूर्ण रूप से समर्थन देता हूँ।

SHRI BIBHU PRASAD TARAI (JAGATSINGHPUR): I would like to share my thoughts and views on the Union Government's Budget for Fisheries sector for the financial year 2024-25.

I want to draw the attention of the hon'ble Members regarding this historic Union Budget for the financial year 2024-25, specifically for the fisheries sector.

With the able leadership of our hon'ble Prime Minister and the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, the country has witnessed a tremendous success during last 10 years. The country had achieved a record fish production of 17.54 million tons, ranking third globally and accounting for 8.92 per cent of the global fish production. This sector not only play a pivotal role nationally, but also hold a crucial role in positioning the country globally. The country has been successfully leading from the front in the production of shrimp, fish producer and marine capture fish producer due to the vision of our hon'ble Prime Minister.

During last five years, the budget allocation for the Department of Fisheries has increased from Rs. 651 crores in 2019-20 to Rs. 2616 crores in the current budget, which is 300 times more-signifying the priority given to this sector in the Union Budget 2024-25. As a result of the boost in budgetary allocation to this sector, India is among the top five fish exporting countries in the world. This sector contributes 1.1 % to the overall Indian economy and 6.72 % within agriculture and allied sectors. In the year 2022-23, the country exported 1.73 million MT of seafood worth 8.09 billion dollar, which is all time high on fisheries export.

Just to quote numbers from the Economic Survey of India 2023-24, as on March 31, 2024, 3.49 lakh KCC were issued to fisheries activities. The fisheries sector has been supported through programmes for improving productivity, access to institutional credit, and infrastructure development through the Fisheries Infrastructure Development Fund (FIDF) with a total fund size of Rs. 7,52 thousand Crore. The provision is meant for the benefit of fishermen in the country. So far, Government had approved 121 proposals and recommended for Rs. 5.59 thousand Crore as a concessional rate 4 per cent interest.

The commitment of the Government to bolster this sector, a comprehensive intervention has been developed in the form of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) with the objective to enhance seed and fish production and other extension services. The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) aimed at strengthening fisheries infrastructure, enable technology infusion, promote optimal water management and for sustainable fishing for the overall development of fishing communities in the country.

The Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is a scheme to bring about Blue Revolution through sustainable and responsible development of fisheries the budget has been proposed at Rs. 2352 crores in the current year budget, i.e, 2024-25, almost 100 percent growth compared to 2022-23 financial year for the holistic development of fisheries sector including welfare of fishers. The scheme is being implemented in all the States and Union Territories benefiting millions of fishing communities. Since the scheme is designed to address critical gaps in the fisheries value chain from fish production, productivity and quality to technology, post-harvest infrastructure and marketing. It aims to modernize and strengthen the value chain, enhance traceability and establish a robust fisheries management framework while simultaneously ensuring the socio-economic welfare of fishers and fish farmers. As a result of these interventions in fisheries sector have resulted in increasing fish production by an average annual growth of 7.4 per cent in 2022-23 from 2020-2021.

Keeping the view of harnessing the potential of the fisheries sector in a sustainable, responsible, inclusive and equitable manner and to enhance fish production and productivity through expansion, intensification, diversification and productive utilization of land and water, the budget 2024-25 sets the context for a prosperous fisheries sector for India. Sir, towards enhancing the contribution of the fisheries sector and to ensure social, physical and economic security for fishers and fish farmers, increasing the per capita domestic fish consumption and export, private investment led growth of entrepreneurship has been given the top priority by the Government.

Further, doubling the incomes of fishers and fish farmers as well as creating direct and indirect employability opportunities, the Union Budget 2024-25 for the Fisheries sector has set a historic direction by giving top priority in budgetary allocation.

In the end, I want to conclude my intervention by giving other numbers from the budget documents for the sector. In the light of keeping promises of a healthy, cooperative and competitive spirit of federalism, the Government had increased the share of Grants in Aid to States and Union Territories from Rs. 900 crores in 2022-23 to Rs. 1900 crores in this budget for the Fisheries sector, which is the testimony of the thrust of the Government: Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas.

I am sure, my State Odisha, having 485 kms of long coastline, will also get ample scope and opportunity in reaping the benefits of this increased budgetary allocation for the Fisheries sector and the outcomes of this investment will be reaching the fishing communities of Odisha.

श्री राम प्रसाद चौधरी (बस्ती) : माननीय सभापति जी, हम आपके आभारी हैं। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र की महान जनता के आभारी हैं।

मान्यवर, यह जो कृषि से जुड़ा हुआ मत्स्य पालन और पशुपालन की अनुदानों की मांगें हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपने देश की चिन्ता कीजिए।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what the hon. Member Shri Ram Prasad Chaudhary ji is speaking.

? (Interruptions) ? *

श्री राम प्रसाद चौधरी : मुझे इस पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।

मान्यवर, यह जो बजट है, पूरे देश के बजट का 0.15 परसेंट, जो हिन्दुस्तान के पशुपालक, मत्स्यपालक और देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, यह बजट बहुत ही कम है।

मान्यवर, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, जब किसानों के बीच में, किसान गोष्ठी में बात करते थे, तो कहा करते थे कि जिस परिवार में दो, तीन या चार सदस्य हों, उसे खेती पर भार नहीं रखना चाहिए। खेती से जुड़े हुए पशुपालन, मत्स्यपालन जैसे और भी रोजगार में बाकी परिवार को लगना चाहिए।

आज पशुपालन और मत्स्यपालन के विषय पर, जिस पर आज चर्चा हो रही है, उस पर धीरे-धीरे तमाम सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं। पशुपालन पर सरकारों द्वारा कोई सुविधा न होने के कारण धीरे-धीरे गांवों में दूध का उत्पादन कम हो रहा है। आज खेती से जुड़े हुए उद्योग-धंधों पर 40 परसेंट तक सब्सिडी है, लेकिन जो छोटे किसान परिवार हैं, जिनमें गांवों की बहन-बेटियां भी पशुपालन में लगी रहती हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं देने का काम नहीं हो रहा है।

आज जिसके पास चार जानवर, भैंस-गाय हैं और उनमें से एक-दो का बीमारी के कारण देहांत हो जाता है, वे मर जाती हैं, तो पशुपालक इंश्योरेंस कंपनियों में दौड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों में दौड़ते-दौड़ते उनकी हवाई चप्पल, जिसके बारे में मौजूदा सरकार ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज से चलेंगे, इंश्योरेंस लेने में उनकी चप्पलें टूट जाती हैं, लेकिन उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है।

आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, माननीय श्री अखिलेश यादव

जी की सरकार रही है, तब कामधेनु योजना, लेयर फार्मिंग, मत्स्यपालन, 25 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक बिना ब्याज के पांच वर्ष के लिए किसानों को देने का काम हुआ था। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह काम किया था।

आज हम आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करेंगे, तमाम सम्मानित सदस्यों ने, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जो गांवों में पशुपालन का काम करते हैं, जिसमें उनका पूरा परिवार लगा रहता है, आप खेती से जुड़े हुए उद्योग-धंधों को सब्सिडी देने का काम कीजिए, अनुदान देने का काम कीजिए। लेकिन जो किसान सीधे इस काम से जुड़े हुए हैं, उनकी बहन-बेटियां मिल जुलकर पशुपालन का काम करती हैं, उन्हें सीधे अनुदान देने का काम हो।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी मांग रखिए, क्योंकि 20 स्पीकर्स और हैं। समय की कमी है, इसलिए, आप कृपया संक्षिप्त में अपनी मांग रखिए।

? (व्यवधान)

श्री राम प्रसाद चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज डॉक्टरों की बहुत कमी है। पशुपालन में आज पशुओं के डॉक्टरों की भी बहुत कमी है। मैं चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर, जो मेरा बस्ती निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

इसके साथ ही मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह से किसान के लिए धान, गेहूं, तिलहन, दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, उसी तरह से दूध का भी इस देश में समर्थन मूल्य घोषित हो।

यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Aga Syed Ruhullah Mehdi.

Kindly try to conclude in three minutes because there are 20 speakers and we have only one hour left. At 5 o?clock, the Minister will reply and at 6 o?clock, the guillotine will take place. So, I request all of you to cooperate.

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): Sir, I will try to conclude in three minutes or a maximum of four minutes.

थैंक यू सो मच। यहाँ पर सभी मेंबर हज़रत ग्रांट्स के हवाले से, एनीमल हसबेंडरी, फिशरीज आदि के ग्रांट्स के हवाले डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी खुशकिस्मती है कि इनके हालात नॉर्मल हैं। वे इस मुल्क के इक्वल सिटीजन हैं। इनके राइट्स इक्वल हैं, इनके राइट्स फर्स्ट क्लास हैं। वे इस तरह की डिबेट में हिस्सा ले पा रहे हैं। हमारे लिए यह लग्जरी नहीं है। मैं भी चाहता था कि आज के दिन इस तरह की डिबेट में हिस्सा लूँ। मेरे पास भी यह लग्जरी हो, प्रीविलेज हो, एक इक्वल सिटीजन की तरह इन मामलात पर बात करूँ। मगर आज 5 अगस्त के दिन, जो इस ऐवान में 5 साल पहले हुआ था।? (व्यवधान) हाँ ठीक है, आपके लिए ठीक हुआ था, मुल्क के लिए ठीक नहीं हुआ था। डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उधर देखकर बात मत कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : हम आपकी मर्जी के गुलाम नहीं हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, इधर देखकर बात कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : हम आपके ठीक होने और न होने के गुलाम नहीं हैं।? (व्यवधान) आपकी मर्जी के गुलाम नहीं हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय सीमित है।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : आपकी पार्टी के लिए ठीक हुआ होगा।? (व्यवधान) इस मुल्क की जम्हूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ।? (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं हुआ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को ऐड्रेस कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Aga Syed *Saheb*, kindly address the Chair.

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : ऑनरेबल चेयरमैन, 5 साल पहले जिस दिन इस ऐवान में वह काला कारनामा किया गया।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बजट पर बोलिए। कृपया, आप बजट पर बोलिए। आपके पास बहुत से अवसर हैं, जब आप ये बातें बोल सकते हैं। आप बजट पर बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : 5 साल पहले, आज के दिन? (व्यवधान) सुनने की हिम्मत भी रखा करो।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बजट पर बोलिए। आपका समय समाप्त हो जाएगा। कृपया, बजट पर बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : डिक्टेटर्स की यह खुसुसियत होती है, वे सुनने से डरते हैं।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बजट पर बोलिए।

? (व्यवधान)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : 5 साल पहले आज के दिन जम्मू-कश्मीर की ... *?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : मजे उठा रहे थे।? (व्यवधान) आज के दिन जम्मू-कश्मीर के आवाम को, जम्मू-कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था और हमसे हमारा स्टेट्स, जम्हूरी हुकूक, हमारे राइट्स।? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You have already taken three minutes.

Shri Gurmeet Singh Meet Hayer.

? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : गुरमीत सिंह जी, आप थोड़ा रूकिए।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। 5 अगस्त के दिन जम्मू-कश्मीर के संबंध में धारा 370 हटाने का जो निर्णय मोदी सरकार ने लिया था, वह देश की एकता, अखंडता और समप्रभुता के लिए था। ये उसे ... कह रहे हैं।

महोदय, उसे रिकॉर्ड से हटवाइए।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हम उसको दिखवा लेते हैं। हमने कह दिया है कि वह रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : गुरमीत जी, एक मिनट रूकिए।

अगर आप बजट पर कुछ कहना चाहें तो मैं एक मिनट और आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी आपके 3 मिनट हो गए हैं। मैंने कहा है कि सभी स्पीकर को 3 मिनट का समय मिलेगा।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर आप बजट पर कुछ कहना चाहें तो मैं आपको एक मिनट और दे रहा हूँ। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक मिनट का समय और दे रहा हूँ, लेकिन आप बजट पर बोलें।

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : मैं बजट पर ही बोल रहा था।? (व्यवधान) मैं बजट पर ही बोल रहा था।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : बोलिए। आप उधर क्यों ऐड्रेस कर रहे हैं?

? (व्यवधान)

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI: Sir, making of Budget is a part of democracy. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

? (*Interruptions*)

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी : हमारे पास इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री गुरमीत सिंह मीत जी, आप बोलिए।

SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER (SANGRUR): I thank you, Hon. Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministries of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the year 2024-25.

Sir, Punjab is a predominantly agricultural State. In agriculture, Punjab has reached saturation point. Farmers are dependent on allied areas. The farmers of Punjab are dependent on dairy industry. Sir adulteration is wreaking havoc on the farmers in the dairy sector.

Today?s Times of India has published a news report. In Maharashtra, adulterated items worth 25 lakh rupees have been seized. This is what is happening in the entire country. Spurious milk, cheese etc. is being seized throughout the country. Lakhs and crores of people are facing health issues due to this rampant adulteration.

Sir, it had been recommended in National Health Policy that Health budget should be increased to 2.5% of the G.D.P. The increase is hardly .5%. We should try to increase the income of the farmers. Also, a severe crackdown on the sale of such spurious products is the need of the hour.

Sir, these people go scot-free after paying a penalty of just Rs. 20,000/- or Rs. 25,000/-. After one or two months, these people again start selling spurious milk etc. So, stringent laws should be framed. Severe punishments should be given to such shady elements.

Sir, Government must bail out farmers who are dependent on sectors allied to agriculture. Due to a disease some time back, over 18,000 cattle perished. The Government should bring a scheme whereby all cattle should be insured.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in one line.

SHRI GURMEET SINGH MEET HAYER: Secondly Sir, big companies purchase milk and milk products at cheap rates. After processing the same, they sell it to consumers at exorbitant price. Milk is a perishable item and the dairy farmers have to sell it on the same day. Sir, if a State level Government processing unit is set up, the farmers will be able to sell the milk and get it processed directly. The farmer will then be linked directly to the market and dairy farmers will get remunerative prices. Give me just a minute, Sir. Last point?

HON. CHAIRPERSON: I have my own limitations. There are 20 more Members to speak on this particular topic. I have my own limitations.

? (*Interruptions*)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, which stands at Rs. 7,137 crore for the financial year 2024-25.

The fisheries sector is crucial to India?s national income, exports, food and nutritional security, and employment generation. India is the third largest fish producing country in the world contributing eight per cent of the global production.

I represent the Machilipatnam Parliamentary Constituency. Everybody knows that ?Machli? means fish. So, I will mention some of the issues being faced by the fishermen community in my Constituency also.

HON. CHAIRPERSON: Kindly do it in three minutes.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Sir, kindly give me five minutes to speak.

As regards dairy farmers, we all know that there are millions of small and marginal dairy farmers in our country. These farmers, who typically own just two to three animals and produce an average of five litres of milk per day are an important part of India's dairy industry.

There was a NABARD Scheme called the Dairy Entrepreneurship Development Scheme. It was one of the most successful schemes. Now, the Government of India has stopped this Scheme. I would request the hon. Minister to start this Scheme again so that

many farmers will get benefitted from this Scheme. This scheme also helped dairy farmers from falling into the debt trap of moneylenders. So, I would request the hon. Minister for his consideration to reinstate the DED Scheme by NABARD.

As regards research in fishery sector, ICAR established various fishery research institutes. I would like the hon. Minister to explain to this House how many technologies and research works have been commercially transferred to the field level? What is their annual budget allocation?

To my knowledge, there has been no significant research on the transportation of live or fresh fish. Countries like China, Turkey, and Australia are successfully exporting live fish by air, sea, and rail.

HON. CHAIRPERSON: Please do not compare with any other country. Kindly conclude now.

? (*Interruptions*)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: However, we do not have a Live Fish Carrier System in our country. So, I would request the Government to address this gap and encourage research in this crucial area so that the fishermen community gets benefitted from it.

Regarding shrimp production and its export, in the seafood export market, shrimp export accounts for two-third of the exports. ? (*Interruptions*) MPEDA has set a target to export seafood products worth Rs. 1 lakh crore from the country by the year 2025 with a major contributor being shrimp. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I allowed you to speak to just conclude your speech.

? (*Interruptions*)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Now, there is only Rs. 65,000 crore worth of shrimp export. What would happen to the remaining Rs. 35,000 crore worth of exports? What is the plan for it? ? (*Interruptions*) How are they going to export shrimps?

HON. CHAIRPERSON: Thank you. I am calling the name of the next Member to speak.

? (*Interruptions*)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI: Finally, countries like Indonesia, Vietnam and China have already achieved 15 to 20 metric tonnes of shrimp production per hectare.

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं केन्द्रीय बजट 2024-25 के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसमें हमारे देश के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यह बजट न केवल हमारे कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, इसलिए मैं तीन मुख्य विषयों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कुछ महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत करना चाहूंगा - पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन।

महोदय, बागपत में पशुपालन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य साधन है। इस बजट में पशुपालन के लिए किए गए प्रावधानों की मैं सराहना करता हूं और अनुरोध करता हूं कि पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हमारे पशुधन की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक पशु चिकित्सालय और मोबाइल वेटेरनरी क्लीनिक की स्थापना की जाए। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले चारे और पोषण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि पशुओं की उत्पादकता बढ़ सके। बागपत में उन्नत प्रजनन तकनीकों और कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की जाए, ताकि पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो।

सभापति महोदय, बागपत में डेयरी उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। डेयरी विकास के लिए किए गए बजट प्रावधानों की मैं सराहना करता हूं और आग्रह करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कूलिंग सेंटर और मिनी डेयरी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएं। डेयरी किसानों के लिए आधुनिक डेयरी प्रबंधन और उत्पादन तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सहकारी डेयरी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे किसानों से उचित मूल्य पर दूध खरीद सकें और उन्हें बेहतर सेवाएं दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, बागपत में नए मत्स्यपालन तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाए।

महोदय, बागपत के किसानों और ग्रामीणों की जीवन शैली में सुधार लाने के लिए यह पहल अत्यंत आवश्यक हैं। मैं एक बार फिर से इस बजट की प्रशंसा करता हूं, जिसमें हमारे क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट के माध्यम से हमारे क्षेत्र के विकास की गति और तेज होगी और हमारा बागपत एक आदर्श ग्रामीण क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा।

महोदय, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत में अमल का एक डेयरी प्लांट की घोषणा की गई थी, जिसका कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अमूल डेयरी प्लांट, जिसकी घोषणा की गई है, उसकी शीघ्र स्थापना की जाए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। धन्यवाद ।

DR. D. RAVI KUMAR (VILUPPURAM): Hon Speaker, Vanakkam. Fishermen?s welfare is a department which is so important for our economy. Approximately 3 Crore people are engaged in this Sector. The Union Government is planning to export 1 lakh Crore worth products and generate revenue to this country. I wish to urge that it is the duty of the Union Government to provide protection to our fishermen who are engaged in this Sector. In order to allow the fishes to reproduce, the Government puts a ban to fishermen on fishing during this period. The lean period was also decided when the fishermen cannot venture into sea due to cyclones and heavy rains. A compensation is being provided to the fishermen. This was fixed at Rs 3000 by the Union Government. Tamil Nadu Government has increased this compensation amount to Rs 6000. Since the period of fishing ban is for 60 days, this amount is inadequate for them. They demand that at least the minimum wage decided under the MGNREGA should be given to them for 60 days of fishing ban. I urge that the Hon Minister should think about this demand and try to fulfil. Not only that the fishermen want them to be included in the list of Scheduled Tribes. This is a long pending demand. Those who live in mountainous areas live as dependants of that area. Similarly, those who live a life dependant of sea life should be included in the list of Tribes. I request that Hon Minister should consider this demand during his term and come to a good solution ate the earliest. When our Indian fishermen go into sea for fishing, the Sri Lankan Navy attack them more often. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu has brought this issue to the notice of Hon Foreign Minister. In this scenario, recently a fisherman named Malaisamy has been killed. Hundreds of fishermen have been arrested by Sri Lankan Navy and are languishing in the prisons of Sri Lanka. Hon Foreign Minister has already assured for a smooth decision in this regard. I urge that the Union Government should act swiftly and protect Tamil fishermen. This should be done for the welfare of fishermen. There are 18 to 19 fishermen villages in my Viluppuram Parliamentary Constituency.

I urge that a fishing harbour should be set-up at Marakkanam of my constituency. This is a long pending demand. The State Government has completed all the preliminary works. Union Government should extend all possible help in setting up of this fishing harbour at Marakkanam in Viluppuram Constituency. Thank you,

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, एक बात मैं कह दूं कि जब कोई भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अभी माननीय सदस्य डी. रविकुमार जी बोल रहे थे, यह अच्छा नहीं लगता है कि बार-बार लोग उनके सामने से क्रॉस कर रहे हैं। स्पीकर साहब भी कई बार कह चुके हैं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनके और चेयर के बीच में या उनके सामने से कृपया मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट क्रॉस न करें।

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सभापति महोदय, फसलों के बाद पशुपालन किसानों की आमदनी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। उस लिहाज से बजट में और ज्यादा प्रावधान होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, जो पशु क्रूरता कानून बना है, उसकी समीक्षा की जाए। उसने सचमुच में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को कम किया या बढ़ाया, हम यह महसूस कर रहे हैं कि उसने बढ़ाया है। पशुओं का व्यापार घट गया है। किसानों की आमदनी घट गई है। वह भारी मात्रा में प्रभावित हुई है। पशुओं के साथ-साथ व्यापार के क्रम में आदमियों पर भी खतरे बढ़े हैं। इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। आवारा पशुओं से पूरे देश में किसान परेशान हैं। पहले वे जंगली जानवरों से परेशान थे, लेकिन अब आवारा पशुओं से परेशान हैं। हमारा यह कहना है कि हम बाहर से जो दूध या दूध उत्पादक चीजों का आयात करते हैं, उसे भारतीय किसानों के हित को ध्यान में रख कर और सेंटर में रख कर किया जाए। ऐसा न हो कि यहां पर हमारा डेयरी उद्योग प्रभावित होने लगे।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आग लगने से इस बार भी बड़े पैमाने पर जानवरों की मौत हुई है, लेकिन उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हम लेजिस्लेशन करें, उन पर ध्यान दें और इंश्योरेंस की व्यवस्था करें। गाय पर तो बात हुई है, गाय पर राजनीति बहुत हुई है, लेकिन गाय के संरक्षण के उपाय हो। यहां अभी ट्रेजरी बेंचों से दोनों तरह के विचार आए हैं। एक तरफ जर्सी गायों के संरक्षण का मामला आया, तो दूसरी तरफ देशी गायों का भी आया। आप इधर आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों की नीतियों की वजह से ऐसा हुआ। आप देशी गायों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति या डायरेक्शन लीजिए। आप उनके संरक्षण का विशेष प्रावधान कीजिए। आप उनके लिए इंश्योरेंस का प्रावधान कीजिए। आप इन सभी चीजों पर गौर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI K. GOPINATH (KRISHNAGIRI): *Hon Speaker, Vanakkam. Thank you for this opportunity to take part in this today?s debate. Sir, this is my maiden speech. I extend my heartfelt thanks to the Party Leader Hon. Smt. Sonia Gandhi, and our youthful leader, future of India, Hon Thiru Rahul Gandhi and the Leader of INDIA Alliance in Tamil Nadu and Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathy M.K. Stalin for my election to this august House. I also thank the leaders of the INDIA Alliance, District leaders, and the voters of Krishnagiri parliamentary constituency for such a great victory accorded to me. Thank you from the core of my heart.

Hon Chairman Sir, my mother tongue is Telugu. I took oath in Telugu in this august House. A leader of a Political party has criticized this. I want to say my mind through you to that leader who criticized me. Annan Thiru Thalapathy M.K. Stalin is ruling the State of Tamil Nadu in the Dravidian Model of Governance. His father and Great leader late Dr. Kalaignar during the term of his Chief Ministership, had declared a holiday for Ugadi festival in the interest of Telugu speaking and Kannada-speaking people, on my demand in the State Assembly when I was serving as a Member of Tamil Nadu Legislative Assembly. This move was to protect the Dravidian languages and the people living in Tamil Nadu who speak these Dravidian languages. This was the magnanimity of Dr. Kalaignar. Even today we have declared Holiday for Ugadi in Tamil Nadu

HON. CHAIRPERSON: Kindly come to the Budget. Maybe, it is your maiden speech, but there is a time constraint.

SHRI K. GOPINATH: Sir, I am going to conclude in two minutes.

@During Oath taking as Member of Parliament, I took oath in Telugu which is my mother tongue. It was criticized by a political party in Tamil Nadu.@

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI K. GOPINATH: Sir, this is my first speech.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude in one minute.

SHRI K. GOPINATH: Hon. Chairman Sir, I have been sitting in this House since morning. You have given 10 to 12 minutes to my friends. I don?t want to in that. Please give me some more time. In my Constituency, in Hosur, there is a 160-acre cattle farm which is the largest in

India. There is a need for constructing a compound wall for a length of 18 kilometres for this farm. A meagre amount of just Rs 4000 Crore is allocated in this Budget for this Department. This is totally inadequate.

I urge that a Veterinary college should be set up in this area with all the facilities provided by this department. I request that this demand should be considered favourably. I urge that a Railway line should be set up between Hosur and Jolarpettai. This genuine demand has been pending for almost 30 long years. I request the Hon Finance Minister and Hon Railway Minister that Hosur-Jolarpet rail route via Krishnagiri is needed. I thank you for this wonderful opportunity. Thank you.

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): Hon. Chairperson, Sir, thanks a lot for giving me an opportunity to speak before this august house on the Demands for Grants with respect to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. I would also like to extend my heartfelt gratitude to our *Yashaswi* Prime Minister Narendra Modi ji and our Party because of whom I am standing here today before the temple of democracy.

This year?s Budget for the Department of Fisheries has witnessed more than 49 per cent rise over the Actual Expenditure recorded in 2022-23, and 65 per cent increase over the Revised Estimates of 2023-24. The Fisheries Department has enormous opportunity for growth. Our Government has seen this opportunity and with the *sankalp* of *?Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas?*, the Department of Fisheries is all set to try to ensure *Sabka Viswas* by assuring adequate and timely coordination with all the coastal States and Union Territories. The time has come to understand and underscore the issues in implementation and address the critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernization, traceability, production, productivity, post-harvest management, and quality control.

In the double engine sarkar regime, Odisha is all poised to grow along with the other developed States as far as the development in its fisheries sector is concerned.

Under the able leadership of the hon. Chief Minister of the State of Odisha, the recently announced State budget has allocated Rs. 344 crore for the Odisha Matsya Mission, and Rs. 220 crore for the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. We have a dream to realise making 480 kilometres long coastline vibrant with marine fishing activities and reviving and harnessing a total of 1,81,837 water bodies in the State of Odisha.

Hon. Chairperson, Sir, while extending deep gratitude from the bottom of my heart, I take this opportunity to urge the hon. Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to become a friend, philosopher, and a guide of Odisha, and support the State in its strive for attaining a glorious status of Viksit Odisha by 2047.

Hon. Chairperson, Sir, I appreciate the Government?s initiative in which the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund and the Dairy Infrastructure Development Fund have been merged into one single fund. The schemes for supporting the dairy cooperatives and the Farmers Producer Organisation are subsumed into it. This is an apt decision of the Government to ensure efficiency in programme administration.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI: Hon. Chairperson, Sir, all of us know that the majority of the country?s poor lives on milch cattle rearing. My State of Odisha has an immense potential to grow as far as the dairy development is concerned. I hope this Budget will support and guide 19 lakh dairy farmers of my State in ensuring increased contribution to the State?s Gross Domestic Product. This year, Odisha has kept a provision of Rs. 102 crore to be spent on Dughdha Banya Yojana and Rs. 65 crore for Ksheer Dhara Mission.

HON. CHAIRPERSON: Now, kindly conclude. Panigrahi ji, thank you.

Now, Shri Selvaraj ji.

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI: Hon. Chairperson, Sir, I will propose one or two last points.

I would like to lay before you some of my suggestions for ensuring an overall development of the dairy sector in India, which includes: organise more and more dairy farmers by forming dairy cooperatives, federating them into district level milk unions, and linking them with the State Cooperative Federations; mapping dairy production, livestock presence and identifying potential areas for better programmatic interventions; ensuring animal healthcare services right up to the community level; and bringing in innovation, technology and good collection practices and manufacturing practices.

HON. CHAIRPERSON: Thank you, Panigrahi ji. Your points are well-taken.

Now, Shri Selvaraj ji.

SHRI SELVARAJ V. (NAGAPATTINAM): Hon Speaker, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in this Discussion. Particularly, as per the recommendation of the National Agricultural Organisation in the year 1976, it was suggested to have one veterinary dispensary for every 5000 cattle. I urge that this recommendation should be considered by the Union Government as one dispensary for 3000 cattle as a new demand and be fulfilled. As a result the rural economy will get a boost besides improving the livelihood of our farmers. Funds are provided by the Union Government to the States under the National Disease Control Programme NDCP for varying out vaccination and data entry operations. I urge that this should be improved at the Block level. The veterinary doctors should be given scales of pay and promotion benefits. Assured Career progression and promotion should be ensured to these Veterinary Doctors. In every Assembly constituency, there is an ambulance facility available to these cattle. This should be revised. Ambulance facility for animals should be at the Panchayat Union level. Our Tamil poets have talked so great about the Tamil pride. ?Let us call as Tamil; and take pride in that?, says Namakkal Kavingar Ramalingam Pillai. He also says, ?Tamil is a special race; which has a distinct character in its own?. The valour of Tamil women is exemplary. Particularly of a Tamil lady. If we say Tamizhachi, it denotes extreme courage. We have our sister Tamizhachi Thangapandiyan a Member of Parliament here in this august House. The main theme of Sangam literature was love and valour. There is a history portraying a Tamil lady using a winnow to let the tiger go away from the habitation. In Tamil Nadu, there was a custom followed by young men in ancient times who wish to marry. Only when men lift heavy spherical stones called the ?Ilavattakkal? they become eligible to marry women. Actor Sivaji Ganesan would have portrayed this in the film titled ?Muthal Mariyadhai?. Jallikattu, the bull sport is also famous in Tamil Nadu. Umblachery is an Indian breed of cattle belonging to our area which needs to be nurtured and protected with necessary aid and financial assistance.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude Mr. V. Selvaraj.

SHRI V. SELVARAJ: Veterinary sub centres should be improved as Hospitals. I urge that adequate staff members should be appointed in such veterinary hospitals with supply and availability of all medicines. Loans up to an

amount of One Crore are provided for purchasing Goats and Cows or bulls. I urge that these loans should be made as minimum as 1 lakh or 2 lakh rupees. Particularly, the lives of fishermen are in deep distress. There is a film song which intensely portrays their sorrows.

?God gave us birth on this land;

But He made us to live dependant on water:

He made us to wait on the shore:

He made our women immersed in tears.

God gave us birth on this land;

Wife and children-all on shore but the man, (the fisherman) is on sea.

We are the ones whose lives are in shaky waters and rising waves

Sea is our house where the moon is lit like a light

If it is ended; it ends and if it is continued it continues

This is our uncertain life.?

HON. CHAIRPERSON: Now, you have expressed your sentiments. Thank you.

Shri K. Eswarasamy ji.

SHRI V. SELVARAJ: This film song explains the troublesome life of our fishermen. Our Hon Member Shri Thanga Tamil Selvan spoke here very well.

HON. CHAIRPERSON: Shri Eswarasamy, you start speaking.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You will get another opportunity.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your poem is very good. Everybody here has given patient hearing.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Selvaraj ji, you just complete your poem.

? (*Interruptions*)

SHRI V. SELVARAJ: Sir just one minute. I will conclude. Sir 170 boats of Tamil fishermen confiscated by Sri Lankan Navy should be brought back to India. Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathy M.K. Stalin has given a compensation of Rs 6 lakh each for these boats to the affected fishermen families. I urge that the Union Government should give Rs 20 lakh for small boats and Rs 50 lakh for big boats. The glass-fibre reinforce plastic boats are being taken away by the Sri Lankan Navy. I urge that there should be relief for such loss faced by Indian fishermen. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Already you have given your speech.

? (*Interruptions*)

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): Hon Speaker, Vanakkam. I thank you for allowing me to make my maiden speech in this august House while taking part in the discussion on Demands for Grants pertaining to the Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Ministry. I bow my head towards the direction where the world leader of Tamils still living in the hearts of millions of Tamils, Muthamizh Arignar Dr. Kalaignar is having his deep sleep. I was born in Karuppasamy Puthur village where there was no bus facility at that time. Now I have been elected as a People?s Representative, a Member of Parliament of the Pollachi parliamentary constituency known for its extensive serene beauty. I thank the luminary leader of DMK and Hon Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathyar and the future of Tamil Nadu Hon Minister of Youth Welfare and Sports Development in Tamil Nadu Thiru Chinnavar for giving this opportunity. I wholeheartedly thank the voters of my Pollachi parliamentary constituency for electing me to this House. Pollachi is a place on the Western Ghats with mountainous beauty and everlasting fame. I begin my speech by saying that this Union Budget has totally ignored Tamil Nadu.

There are no schemes aimed at the development of Tamil Nadu. This Budget will give revenue to the Union Government rather there is only expenditure on the part of Tamil Nadu. I wish to pinpoint how Tamil Nadu has been betrayed. During last 5 years, there was inordinate delay in the construction work of AIIMS in Madurai. There is delay in allocating funds to Chennai Metro. The Government of Tamil Nadu is in a state to accept the expenditure relating to Chennai Metro. I urge that the Union Government should allocate adequate funds to Chennai Metro. During the year 2024-25, only an amount of Rs 4527 Crore has been allocated to Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Ministry. This is very much less. Tamil Nadu Government has been implementing several Schemes for the welfare Tamil Nadu fishermen. The State Government has been fulfilling the basic needs of the fishermen and their families during the period of fishing ban in Tamil Nadu. Fishermen of Tamil Nadu are time and again arrested by Sri Lankan Navy and their assets are confiscated by them. The Indian fishermen are attacked and arrested by the Sri Lankan Navy personnel. Indian Government should try to stop such occurrences of attacks by Sri Lankan Navy besides getting back the confiscated boats and other assets of our fishermen. I urge the Union Government to create a separate fund to meet such compensation requests. In Tamil Nadu the cattle rearing is profitable than farming. Rural people are having cattle rearing as their livelihood. India is in topmost place among the world countries in milk production. As regards the quantity and value, milk production exceeds rice and wheat cultivation and production. Therefore, I request that the Union Government should allocate additional funds for animal husbandry and management besides helping to improve the livelihood of our farmers.

HON. CHAIRPERSON: Kindly conclude.

SHRI K. ESWARASAMY: Sir, Since I am speaking for the first time, I may be given two more minutes to complete my speech. I am elected as the People?s representative of Pollachi parliamentary constituency. I kindly request you the Union Government to consider the demands of the people of my constituency which is known for agriculture and farming. I urge that a training centre should be set-up in the Veterinary Management department complex in Pollachi. Those who have more than milching cows should be given with milching device with 50 per cent subsidy. If the Union Government provides Water Sprinkler device with subsidy from the centre in areas under local bodies for the use of cattle rearing farmers, it will help in Chaff cutting. Fodder cultivation can be increased by way of distributing fodder seeds free of cost in Pollachi constituency. And also as part of entrepreneurship development, 50 percent subsidy should be provided by the Union Government for setting up of sheds for poultry farming activities besides providing equipment.

HON CHAIRPERSON: Thank you. Please conclude.

SHRI K. ESWARASAMY: Sir, I am concluding in one minute. In Udumalaipettai, a Central Institution should be set-up for the development of cattle of that area. Thank you.

SHRI OMPRAKASH BHUPALSINH *ALIAS* PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon?ble Chairman, I rise to discuss the demand for grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Today, I would like to draw the attention of Union Government towards the issues and challenges faced by milk producing farmers of Maharashtra. The rate at which cow milk is being purchased is Rs 23 to 29 per litre and buffalo milk at the rate Rs 31 to 36 per litre.

These farmers also have to purchase costly fodder and cattle feed. The Central Government should consider the plight of the milk producing farmers as they are facing financial losses and hardships and that is why they are compelled to commit suicide. Milk and bottle of mineral water are being sold at the same price and this is very unfortunate. I can show you this receipt of milk collection centre issued to one farmer and it shows that the purchasing rate of milk is only Rs 25.74 per litre.

Sir, around 70% population of this country is solely dependent on farming, and farm related businesses which help them to earn their bread and butter. In last year's budget, R. 4328 crore were allocated for Animal Husbandry and Dairing but it has been reduced to the tune of Rs 3914 crore only. For Fisheries, it was around Rs 2248 crore during last year but now it is only Rs 1701 crore.

On one hand, Government is talking about doubling the income of famers, but on the other hand, it is reducing the budget allocation for farmers. Then, how will it be doubled? Can anybody explain?

Government needs to consider this reality. Kindly allow me to speak one more minute, please.

I can recall, the then UPA Government had waived off the farmers debts worth Rs 72,000 crore. It is pertinent to mention here that this Government has waived off the debts of big corporate hours and Industrialists worth Rs 16 lac crore.

This Government takes care of big businessmen and not of the poor farmers. This is very unfortunate. If you are giving this step motherly treatment to our farmers, this is a sad state of affairs.

Lastly, through you, I would like to request Union Government to take concrete steps to provide a kind of relief to the milk producing farmers.

Thank you.

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI (GUWAHATI): Thank you, Sir. I rise today to express my heartfelt appreciation and commendation for the Union Budget 2024-25 presented by our esteemed Finance Minister Nirmala Sitharamanji under the guidance of our visionary Prime Minister, hon. Narendra Modiji.

This Budget is a testament to the Government's unwavering commitment to the welfare of various sectors that form the backbone of our nation, particularly, in a State like Assam. Assam, with its rich natural resources and diverse economy, stands to benefit significantly from the forward-thinking measures outlined in this Budget. The initiatives and allocations presented are poised to drive growth, enhance livelihoods, and ensure sustainable development across multiple sectors.

One of the most significant highlights of this Budget is the robust support extended to the fisheries sector. Our vision is to elevate Assam to a net fish exporting State and establish it as the ?aqua hub? of South East Asia and India.

In recent years, we have witnessed a remarkable increase in fish production from 3.73 lakh metric tonnes in 2019-20 to 4.74 lakh metric tonnes in 2023-24. This growth is a clear reflection of the dedication and hard work of our fish farmers and the supportive policies of

our Government. Furthermore, fish seed production has also seen a significant growth by reaching 20,843 million in 2023-24 from 9,519 million in 2019-20. This increase is crucial for sustaining and expanding our fish farming activities and ensuring a steady supply of quality fish seeds to meet the growing demand.

As far as the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana is concerned, a significant allocation for the fisheries sector at the national level is expected to channel substantial resources towards Assam's fisheries development. This increased investment will propel us towards our goal of significantly enhancing fish production and creating numerous job opportunities in the sector.

Infrastructure development is another key area of focus. Projects like the establishment of modern integrated fish landing centers and fish hatcheries are underway. These facilities, coupled with the Government's emphasis on cold chain infrastructure, will significantly boost our capacity and efficiency in fish production and marketing, ensuring that our fish products reach a wider market. We are aware of the challenges such as the shortage of quality fish seed and feed, and the need for better hatchery management.

Sir, moving beyond the fisheries sector, I want to address the significant impact of this year's floods on livestock in Assam. The devastating floods have affected 35 districts and 199 revenue circles, impacting a total of 41,34,054 livestocks. This includes 11,18,038 small animals and 12,89,597 ducks, and poultry.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, kindly conclude your speech now.

? (*Interruptions*)

17.00 hrs

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI: Sir, this is my maiden speech.

Tragically, we have lost 2,521 animals, including 885 large animals, 736 small animals, and 900 ducks and poultry, which is a considerable blow to our rural economy.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Kalita ji, there are so many new Members who would like to deliver their maiden speeches. But due to time constraint, I cannot provide more time to you. Thank you.

SHRIMATI BIJULI KALITA MEDHI: Sir, I will conclude in one minute.

In response to these challenges, our Government has taken swift and effective relief measures to mitigate the impact of floods. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, Shrimati Geniben Nagaji Thakor.

SHRIMATI GENIBEN NAGAJI THAKOR (BANASKANTHA): Hon. Speaker Sir, I thank our leader Shri Rahulji for giving me this opportunity to take part in the discussion on demands for grants under the control of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the year 2024-25. Rs. 7137.68 crore has been allocated for this department. This amount should be increased. Hon?ble Speaker Sir, many members of this House talked about Gaumata. I also want to talk about Gaumata. Many religious leaders, saints, mahants and Sankaracharya of Jyotirpith Swami Avimukteshwaranand Sarasvati Maharaj have carried out a padyatra and demanded from the government that Gaumata should be given the status of Rashtra Mata. I also demand that a law should be brought in Lok Sabha to give

status of Rashtra Mata to Gaumata and to stop slaughtering of Gaumata. For looking after the cows, all Gaushalas should be given Rs.100/- per day for each cow.

Hon. Speaker Sir, the products made from cow milk are very much beneficiary to our health. Cow dung is used as manure in natural farming. Hon?ble Speaker sir, 18% GST is charged at the time of taking insurance of cattle. I demand that this GST should be removed.

Hon. Speaker Sir, I also demand that names of the political parties should be declared who have taken election funds from the companies running slaughter houses in India. The amount of funds should also be revealed. Most of the grazing land has been given to the industrialists and this has caused difficulties for animals and cattle farmers. Hon?ble Speaker Sir, through you I demand that grazing land should not be handed over to industrialists. Hon?ble Supreme Court has also put ban on giving grazing lands to industrialists. I request that this ban should continue. My district is a border district and it is a very sensitive zone. In this area, land has been allotted for wild animals but some industries like salt industries have been set up on this land. I request that such industries should be banned in this area.

Hon. Speaker Sir, my district is associated with animal husbandry. Dhanera, Dantiwada and Palanpur blocks of Banaskantha district do not have irrigation facility. I demand that irrigation facility should be developed in these blocks.

Sir, only one representative is entitled to cast vote in the elections of milk co-operative societies. I demand that instead of one representative, all the members of the co-operative society should be allowed to vote to elect board of directors of the society.

माननीय सभापति : श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद जी। आप केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : माननीय पीठासीन महोदय, आपने मुझे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मत्स्यपालन एवं पशुपालन देश में सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। मछली खाना मनुष्य शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, वहीं मछली जल्दी भी पकती है और पचती भी जल्दी है। मछली खाने से मनुष्य को ओमेगा-3 से लेकर सभी विटामिंस और प्रोटीन्स मिलते हैं। शरीर को जितने तत्व की जरूरत होती है, वह सब मछली से मिल जाता है। हमारे देश में करीब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं और सरकार 80 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल और खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। केवल गेहूं-चावल खाने से आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। उसको मौसमी फल, मौसमी सब्जियां और दूध भी मिलना चाहिए, लेकिन गरीब अपनी गरीबी के कारण यह सब नहीं खरीद सकता।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और प्रदेश की सरकार जलमग्न भूमि में मत्स्यपालन हेतु लगान कृषि भूमि की अपेक्षा सौ प्रतिशत ज्यादा है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में निषाद मछुआरा समुदाय को पट्टा देने का अधिकार था, उसे बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया है। मत्स्य पर सौ प्रतिशत लगान बढ़ाने से मत्स्यपालक और मछुआ समुदाय के लोग इकट्ठा रुपया नहीं दे सकते हैं। बीजेपी की सरकार ने मेरे समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं निंदा करता हूं।

माननीय सभापति : मेरे पास श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री पप्पू यादव, श्री असाद्दुदीन ओवैसी, उमेशभाई पटेल, चन्द्रशेखर जी, हनुमान बेनिवाल जी, राजकुमार रोत जी के नाम हैं। इसके अलावा मंत्री जी का रिप्लायी भी होना है। आप दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

निषाद जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद : महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए किसान को दो लाख रुपये ब्याज रहित दिये जाएं। आज केमिकल और सिंथेटिक दूध देश में बिक रहा है।

माननीय सभापति : मनीष जी, आप तीनों लोग कृपया आपस में बात न करें।

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद : महोदय, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए देसी खाद का उपयोग किया जाए, रसायनिक खाद का उपयोग कम हो। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। यही मैं सरकार से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. ....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray ji, your party leader has already mentioned this issue. I have already given him an opportunity to speak.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Shri N.K. Premachandran will go in record.

*....(Interruptions) ?**

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, please continue your speech.

....(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. By virtue of Demand Nos.43 and 44, a total amount of Rs.7138 crore have been allocated in the Budget for the financial year 2024-25, which is 27 per cent more than that of the Revised Estimates of 2023-24. Kindly note that 0.15 per cent is the total allocation for the two Departments by virtue of Demand Nos. 43 and 44.

Sir, I am confining my speech only to Demand No.43, that is, Department of Fisheries. I would like to say that the Department of Fisheries is responsible for the development and promotion of fisheries sector. The people who are engaged in the fisheries sector are from the vulnerable communities. They are down-trodden people and are just like the people from Scheduled Tribe communities who live in forest areas.

Sir, in 2023-24, India was the third largest fish producing country in the world. Fisheries sector plays an important role in export, nutrition, food security and employment generation. So, my first point is that a separate Ministry is required for fisheries. That is the persisting demand of all the people living in coastal areas. A separate Ministry for fisheries is highly essential.

Secondly, in 2024-25, the Standing Committee on Agriculture has submitted its Report. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

....(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: This is bullying. *....(Interruptions)* This is not fair. *....(Interruptions)* If you do not want me to speak, I will sit. *....(Interruptions)* You were silent when the other hon. Member was delivering his speech. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please finish your speech in one minute only.

....(Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I am concluding my speech in a minute. *....(Interruptions)*

Sir, in 2024, the full potential of the Indian fisheries sector is yet to be realised due to gap in the production inputs, investment, infrastructure and skilled manpower, and also due to over-fishing, pollution, disease outbreak and climate change.

17.11 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, my point is that these major issues have to be addressed for which the budgetary allocation made for the fisheries sector is not ? (*Interruptions*) My point is that the budgetary allocation is not ? (*Interruptions*)

Sir, the Budget allocation for the year 2024-25 is not sufficient to address the concerns which I have already expressed.

My third point is about the CRZ mapping. With respect to the 2019 notification, the Kerala State has submitted the proposals. I would request the Government to expedite the process for CRZ notification. The second thing is about the anti-sea erosion activities. The anti-sea erosion activities were formally included in the Finance Commission proposals, but there is no fund. So, I urge upon the Government to have anti sea-erosion works with groynes, that is, construction of sea walls with groynes, using tripods and tetrapods.

Now, I come to the issue of shrimp export. The USA and the EU have put a ban on import of shrimp from India. The US had put a ban in the year 2019 on shrimp import from India on the basis of sea turtle issue. I request the hon. Minister and the Ministry to intervene in this matter. The US Marine Mammal Protection Act specifically states that turtle excluder device or tech is to be provided; otherwise the fish will not be taken by them. That is the reason for which export to the US is banned. Kindly persuade the US Ministry to relax the norms.

My last point is that the Right to Forest Act is there. Similarly, I urge upon the Government to have a Right to Sea Act for the fishermen so that this issue can be addressed as whole.

With these words, I conclude. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के अलावा किसी की कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

? (*Interruptions*) ?*

माननीय अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था दे दी गई है।

माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): अध्यक्ष महादेय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चल रही चर्चा में 37 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। ? (व्यवधान) मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि उन्होंने जो भी सकारात्मक सुझाव मंत्रालय के कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए दिए हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। ? (व्यवधान)

मुख्य तौर पर जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, उनमें से अधिकांश माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में मत्स्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर और उनकी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। ? (व्यवधान) कई राज्यों की जो मांग रही हैं, मैं पहले उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में ?ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम? के तहत 41.44 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। उसका आधा हिस्सा, 27.20 करोड़ रुपये, जो कि केन्द्र सरकार का हिस्सा है, उसे पंश्चिम बंगाल की सरकार को जारी कर दिया गया है। ? (व्यवधान) अब जहां तक ?प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना? की चर्चा माननीय सदस्यों ने की है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ?प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना? वर्ष 2020 में शुरू की गई थी और पश्चिम बंगाल की सरकार ने वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में इस योजना का लाभ उठाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनको लाभ नहीं मिल पाया था। ? (व्यवधान)

अब उन्होंने इसके महत्व को समझा है और इसके महत्व को समझकर उन्होंने अब इसे स्वीकार किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए केन्द्र सरकार की जो भी हिस्सेदारी है, उसके तहत केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी मदद करेगी।

आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी किसी भी राज्य के साथ कोई भेद-भाव नहीं करते हैं। उनका ध्यान समग्र देश के विकास और समग्र राज्य के विकास की ओर केन्द्रित होता है। इसीलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वेटेरनरी के लिए एमवीयू की बात हुई है। पश्चिम बंगाल में 218 एमवीयू यूनिट्स चलाने के लिए पहली किश्त 674.78 लाख रुपए जारी कर दी गई है और उसका लाभ पश्चिम बंगाल सरकार उठा रही है।

महोदय, यहां चर्चा हुई है कि अमेरिका को भारत झींगा आयात कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने झींगा के आयात को बंद कर दिया है, जो पूर्णत: सही नहीं है। श्रिम्प एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की बात है, तो यह उल्लेखनीय है कि केवल समुद्र से पकड़े जाने वाले श्रिम्प, जो कि मात्र दस प्रतिशत है, उसे अमेरिका की सरकार ने बैन किया है। इनलैंड और एक्वा कल्चर के माध्यम से जो श्रिम्प का उत्पादन हो रहा है, वह आज की तारीख में भी अमेरिका में निर्यात किया जा रहा है। हम आपको यह बता देना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने केरल के बारे में चर्चा की है। 10 वर्षों में फिशिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अब तक 1385.82 करोड़ रुपए सिर्फ केरल राज्य के लिए स्वीकृत किए गए हैं। हम आपको यह बता देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस पैसे से फिशिंग हार्बर, आर्टिफिशियल रिफ्स, डीप शी फिशिंग वेशल्स और 700 केज कल्चर, ऑरनामेंटल फिशरीज रैस के 646 सिस्टम्स और बायोफ्लॉक यूनिट्स भी स्वीकृत किए गए हैं। हम आपको यह बता देना चाहते हैं। इसके अलावा कई माननीय सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा की है। देश में आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सबसे ज्यादा योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा पिछले दस सालों में अकेले नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में 1853 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। इसके अलावा अरविंद सावंत, जो शिव सेना के साथी हैं, उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में 18 हार्बर एवं फिशिंग लैंडिंग सेक्टर में 1482.10 करोड़ रुपए लागत की योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इनके अलावा वहां और भी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि पशुओं की संख्या कम हो रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 और 2019 के बीच में गायों की संख्या 19.30 करोड़ से बढ़ कर 19.90 करोड़ हो गई है, जो कि बढ़ोतरी है। पशुओं की संख्या घटी नहीं है। वर्ष 2012 और वर्ष 2019 के बीच 10.8 करोड़ से बढ़ कर 11 करोड़ हो गई है। मैं यह भी उनको बताना चाहता हूं। इसीलिए पशुओं की संख्या बढ़ी है।

कई माननीय सदस्यों ने श्रीलंका के साथ जो मछली पकड़ने के संबंध में विवाद होता है, के बारे में कहा है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हां, ऐसा होता है। कई बार हमारे मछुआरे श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं और श्रीलंका के मछुआरे हमारी सीमा में आ जाते हैं। विदेश मंत्रालय के अधीन इसके लिए श्रीलंका सरकार और विदेश मंत्रालय के बीच एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, जो समय-समय पर उस पर विचार करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि अब बोट में इसरो की मदद से ट्रांसपॉंडर लगाया गया है। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। जब हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे तब हम उसकी चर्चा करेंगे। ट्रांसपोंडर में मछुआरे भाइयों को और जो मछली उत्पादन के साथ लगे लोग हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं। अगर वे इसका लाभ उठाएंगे तो इस तरह की समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज मत्स्य उत्पादन, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र की चर्चा हो रही है। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह संकल्प है कि हम विकसित भारत का निर्माण करें, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। इस अकेले मत्स्य उत्पादन के साथ लगभग 2.8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी

जी ने ?प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना? को चलाकर मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति पिछले दस वर्षों में हुई है, वह इस बात का संकल्प है, वह संकल्पित है कि देश के हर क्षेत्र को हम विकसित करेंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं।

महोदय, आज मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा है। हम फिशरीज प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2013-14 में, अब ये लोग बात तो बहुत लम्बी-लम्बी करते हैं, लेकिन वर्ष 2013-14 तक ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप पहली बार चुनकर आई हों। आप बैठे-बैठे टिप्पणी मत करो।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह तरीका ठीक नहीं है।

माननीय मंत्री जी।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अब ये चेयर से बहस नहीं कर सकती हैं। हम बता रहे हैं कि वर्ष 2013-14 में, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनको आइना दिखा रहे हैं कि आपने वर्ष 2013-14 तक क्या किया? आपने आज़ादी के बाद 60 साल तक शासन किया। आपने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दस वर्षों में जो काम करके दिखाया है, वह हम आपको आइना दिखाना चाहते हैं। वर्ष 2013-14 में इस देश का मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था। जब तक ये शासन में थे, तब तक मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 174.45 लाख टन हो गया। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 वर्षों में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो काम किया, उससे उत्पादन दोगुना हो गया। अब आपको कौन सा आइना चाहिए, यह आप बताइये। आपको आइना दिखाने के लिए उसके लिए अलग से कोई मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाएगा? ? (व्यवधान) आपने 73 साल में शासन करके जो काम नहीं किया, उन्होंने वह काम किया। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया। यह एक बड़ा क्षेत्र था, जहां तीन करोड़ लोग इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया और ध्यान केन्द्रित करके उन्होंने जो योजनाएं चलाईं, उसका यह परिणाम है। कई लोग चर्चा कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने फरवरी, 2019 में मत्स्य उत्पादन को विभाग बनाया और जून, 2019 को उसके साथ डेयरी और पशुपालन को जोड़ने का काम किया। उन्होंने वर्ष 2015 से 38,572 करोड़ रुपये की नई योजना और कार्यक्रम चलाएं, आज उसके कारण मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा उत्पादन बढ़ा है।

महोदय, आज हम जो मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन का है, उसमें उसका 75 प्रतिशत योगदान है और 25 प्रतिशत का योगदान सिर्फ कोस्टल के इलाकों का है। हमारा मत्स्य उत्पादन जो इनलैंड वाटर में है, वह वर्ष 2013-14 में 61.36 लाख टन था। जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 131.30 लाख टन हो गया। इसमें 114 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब उनको कौन-सा आइना चाहिए, यह हमारी समझ से बाहर है।

आज जो खारा पानी है, उसमें झींगा का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इसमें जो हस्तक्षेप केन्द्र की सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, यह उसके कारण हुआ। आज आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में झींगा के उत्पादन में उछाल आया है और झींगा का उत्पादन बड़ी संख्या में बढ़ा है।

इसके अलावा, झींगा के लिए 9 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किये गये हैं। इसमें सपोर्टेड है- hatcheries, Brood Bank and BMC for enhancing availability of quality seeds, यह क्वालिटी सीड्स के लिए भी किया। टेक्नोलॉजी इंफ्यूजन किया गया। As for stocking in reservoirs, 50 हजार केजेज़ के रिज़र्वायर्स बनाये गये हैं। स्टॉकिंग इन वेटलैंड्स है, river ranching है, स्पीशीज डायवर्सिफिकेशन है। ये सारे काम किये गये हैं, उनके कारण आज झींगा का इतना उत्पादन हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान ब्लू रिवोल्यूशन नम्बर-1 का है। उसके अलावा, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का निर्माण, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसने इसमें योगदान किया।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी गई। जो फिशरीज उत्पादन के साथ जुड़े हुए मछुआरे हैं, मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े हुए जो किसान हैं, उनके लिए उन्होंने जो किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई, उसने मछली के उत्पादन में उछाल

लाने का काम किया। इन नीतिगत निर्णयों के कारण ही व्यापक पहुंच हुई। लोग इसके साथ बड़ी संख्या में जुड़े। इससे जुड़ने के कारण फिशरीज के सेक्टर में जो प्रोडक्शन बढ़ा, उसका परिणाम यह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर रहे हैं और उसे विदेशों में भेज रहे हैं। वर्ष 2013-14 में भी यह बात कर रहे थे। वर्ष 2013-14 में जहाँ 30,213 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा था, वहीं वर्ष 2023-24 में 60,523.89 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम फिशरीज सेक्टर में कर रहे हैं, हम विदेशों में भेज रहे हैं। इसलिए केवल हमारा उत्पादन ही दो गुना नहीं हुआ, हमारा एक्सपोर्ट भी दो गुना हुआ और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि है।

महोदय, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डेवलपमेंट फंड का जो निर्माण हुआ, इसके तहत हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक 7,522.48 करोड़, जिसे वर्ष 2025-26 तक फिशरीज एंड डेवपलमेंट फंड की अवधि को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया और 7,522.8 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

इस फंड के तहत हम व्यक्तिगत मछुआरों, मात्सिकी उद्यमियों, मत्स्य सहकारी समितियों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत, नाबार्ड भी राज्य सरकारों को कार्यान्वित योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। विभिन्न राज्यों के लिए अब तक 122 परियोजनाओं की स्वीकृति इसके तहत दी गई है। उसमें 22 फिशरीज हार्बर्स हैं, जिसकी लागत 4,905.77 करोड़ रुपए लागत है। इसके अलावा, 24 फिशिंग लैंडिंग सेन्टर्स हैं, जिसकी लागत 122.20 करोड़ रुपए है। इसमें 21 राज्य मत्स्य बीज पार्क्स का आधुनिकरण भी है, जिसकी लागत 81.70 करोड़ रुपए है। यह इसके अंतर्गत अब तक स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा नीली क्रांति और मत्स्य संपदा योजना का फिजिकल, भौतिक लक्ष्य है, भौतिक लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है, उसकी लंबी सूची है। यदि, अध्यक्ष महोदय, आप अनुमति देंगे, तो मैं इस सूची को सदन के पटल पर रख देने का काम करूंगा, इसलिए, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, काफी लंबी सूची है, जो फिजिकल वैरिफिकेशन अलग-अलग क्षेत्रों में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बताना चाहता हूं। 20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020 में लागू की गई थी, जो 2024-25, अर्थात पांच वर्षों के लिए लागू की गई है। वह वर्ष 2025 तक चलेगी। 9,407 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश, सेंट्रल शेयर, 4,880 करोड़ रुपए का राज्य का अंश और 5,763 करोड़ रुपए लाभार्थियों यानी बेनिफिशरीज का अंश है। यह टोटल योजना वर्ष 2025 तक चलने वाली है। इसकी शानदार प्रतिक्रिया मिली है, सफलता भी शानदार हुई है। ? (व्यवधान) चार वर्षों के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एवं अन्य एजेंसियों के लिए 7,716.78 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 18,721.03 करोड़ रुपए की परियोजना की अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। ? (व्यवधान)

इस योजना के तहत हम टैक्नोलॉजी समावेषण को अपनाते हैं और इसे लोकप्रिय बनाया गया। ? (व्यवधान) टैक्नोलॉजी समावेषण को अपनाया गया, टैक्नोलॉजी को डेवलप किया गया और टैक्नोलॉजी को डेवलप करके इसको लोकप्रिय बनाया गया। ? (व्यवधान) हम बायोफ्लॉक का निर्माण इसके अधीन करते हैं। ? (व्यवधान) Recirculatory Aquaculture System, पेन-एंड-केज कल्चर को विकसित करने का काम प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया। ? (व्यवधान) चार वर्षों में 50,710 जलाशयों में केज का निर्माण कराने के कारण आज हमारा मत्स्य उत्पादन बढ़ा है। ? (व्यवधान) 11,995 Recirculatory Aquaculture System (RAS) को हम लोगों ने डेवलप करने का काम किया है। ? (व्यवधान) बायोफ्लॉक और पेन-सी-केजेज़ की भी स्वीकृति दी गई, जिसने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर उसकी लागत को कम करने का काम किया। ? (व्यवधान) यह काम प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया गया है। ? (व्यवधान) यूपी, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र को आरएएस की कुल 86 परसेंट इकाइयां प्राप्त हुई हैं। ? (व्यवधान) यह हमारी प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपलब्धि है। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले आग्रह किया, अगर आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगे, तो मत्स्य संपदा योजना के तहत जो फिजिकल अचीवमेंट्स हैं, उनको मैं सदन के पटल पर रख दूंगा, ताकि वह इसका पार्ट बन जाए, क्योंकि वह बहुत लंबी सूची है। ? (व्यवधान) यह मैंने आपसे आग्रह किया है। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे मत्स्य उत्पादन को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में विकसित करने का काम किया है। ? (व्यवधान) प्राथमिक व्यवसाय के रूप में हमने इसको विकसित करने का काम किया, उद्यमियों को इस मत्स्यपालन को अपने व्यवसाय में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उसमें हम लोगों को सफलता हासिल हुई है। ? (व्यवधान) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में इनलैंड जलीय कृषि के लिए 21,998.41 हैक्टेयर तालाब क्षेत्रों का उपयोग किया गया, जिससे इसकी उपलब्धि बढ़ी है। ? (व्यवधान)

इसके अलावा और भी कई विषय हैं, जैसे केसीसी सुरक्षा है। मैंने आपसे जैसा कहा कि सामाजिक सुरक्षा, मत्स्य उत्पादकों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। पहली बार, यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि मत्स्यपालन से जुड़े मछुआरा भाइयों को और उसके साथ जुड़े अन्य तीन करोड़ लोगों को उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से

जोड़ने का काम किया। ? (व्यवधान) उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के कारण आज उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। ? (व्यवधान) कमर्शियल बैंक, कोआपरेटिव बैंक और रीजनल बैंक्स उनको लोन दे रहे हैं। 2477.95 करोड़ रुपये की राशि के साथ 4.27 लाख केसीसी कार्ड अब तक मछली उत्पादन के साथ जुड़े लोगों को वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी में, सामाजिक सुरक्षा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य उत्पादन के साथ जुड़े मछुआरा भाइयों को बीमा की गारंटी दी है। अगर कोई आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता प्राप्त करता है तो 5 लाख रुपये, अगर आंशिक विकलांगता प्राप्त करता है तो 2.5 लाख रुपये और अगर कोई बीमार है, चिकित्सारत है, अस्पताल में है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है तो उसको 25 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यह प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है। उन्होंने कई क्षेत्रों में ऐसा काम किया है। उन्होंने हिमालयन इलाकों में ट्राउट को विकसित करने का काम किया है। अलग-अलग क्षेत्रों में जो भी मछली पायी जाती हैं, उनको विकसित करने के लिए पूरा विभाग, मंत्रालय काम कर रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, उससे हम लोग उसको आगे लाभ पहुँचाने का काम करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ट्रांसपोंडर की सुविधा दी गई है, ट्रांसपोंडर बोट में लगाया गया है, उसका लाभ यह है, जो सबसे बड़ी सुविधा उसमें प्राप्त है, इस प्रोजेक्ट से मछुआरे टू-वे सिस्टम में अपने परिवार, कोस्ट गार्ड या अन्य सम्पर्क सूत्रों से सूचना का आदान-प्रदान कर सकते हैं। इस ट्रांसपोंडर सिस्टम से मछुआरों को चक्रवात, मौसम, समुद्री तूफान या टरबोलियंस के अलर्ट की सूचना दी जाती है। यह ट्रांसपोंडर हर बोट में लगा हुआ है। पोटेंशियल फिशिंग जोन, जहाँ पर मछलियाँ बहुतायत में पायी जाती हैं, ऐसे स्थलों की पूर्व सूचना मछुआरा भाइयों को रियल टाइम बेसिस पर दी जाती है। यह ट्रांसपोंडर की सुविधा दी गई है। मछुआरे जब इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि श्रीलंका की सीमा में हमारे मछुआरे चले जाते हैं, ऐसे समय में उन्हें उस बोट में ट्रांसपोंडर के माध्यम से ऑटोमेटिक अलर्ट जारी किया जाता है ताकि वे यह समझ लें कि हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर गए, मेरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर गए हैं। इससे उन्हें लाभ होगा। उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षित करके उनके साथ उनको जोड़ा जा रहा है। अगर इसका लाभ हमारे मछुआरे भाई उठाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि वे मेरीटाइम बॉर्डर, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको कभी क्रॉस कर पाएंगे। यह प्रोजेक्ट टेंडर के बाद तीन एजेंसीज को दिया गया है और लगभग एक लाख वेसल्स में अब तक लगाया जा चुका है। यह सुविधा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के लगभग 9 करोड़ लोग पशुपालन और डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं। इन 9 करोड़ में से 90 प्रतिशत लोग लघु एवं सीमांत किसान हैं और गरीब वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा इनका जो उत्पादन मूल्य है, वह लगभग 11.16 लाख करोड़ रुपये है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप धान और गेहूं के पूरे मूल्य को जोड़ लें तो यह उससे ज्यादा है। 11.16 करोड़ रुपये उनका उत्पादन मूल्य है। इसके अलावा डेयरी और पशुपालन से जुड़ी अन्य संस्थाओं को भी जोड़ लें तो लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग डेयरी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। डेयरी का कारोबार 17 लाख करोड़ रुपये का है। मैंने बताया कि मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन में हमारा दुनिया में दूसरा स्थान है लेकिन डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में नम्बर ?एक? पर हैं। 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने 58 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 2014-15 में जब आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यह गद्दी संभाली थी, उस समय 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन था जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 230.6 मिलियन टन हो गया है। इसमें छह परसेंट की वृद्धि हम प्रतिवर्ष कर रहे हैं। दुनिया में जो औसत वृद्धि है वह केवल दो प्रतिशत है और हमारे देश की वृद्धि छह प्रतिशत है, यह हमारी उपलब्धि है। हमारे दूध की उपलब्धता 9 वर्षों के अंदर 43 परसेंट बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में 322 ग्राम दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 459 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। यह आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है लेकिन इन्हें यह दिखाई नहीं देता है तो पता नहीं इन्हें कौन-सा आईना चाहिए, यह हम लोगों की समझ से बाहर है।

अध्यक्ष जी, डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया और उस मिशन की सफलता है कि आज हम इस ऊंचाई तक विश्व के सामने खड़े हुए हैं। कई सदस्य नस्ल सुधार की बात कह रहे थे। हम बताना चाहते हैं कि देसी गायों की नस्ल के सुधार पर सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कार्यक्रम चला रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्र व्यापी कृत्रिम गर्भाधारण को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पीछे हम लोग आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें दो चीजें मुख्य तौर पर हैं। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन और दूसरा आईवीएफ टेक्नोलॉजी को हम विकसित कर रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन को आज हम लोग घर-घर तक पहुंचा रहे हैं। हमने मैत्रिका बहाली की है। हम मैत्री के स्वयं सेवकों को शिक्षित कर रहे हैं। वे किसान के दरवाजे तक सेक्स सॉर्टेड सीमेन की खुराक लेकर जा रहे हैं और ऑन लाइन अपलोड कर रहे हैं ताकि पूरे देश में इसे विकसित किया जाए। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उपयोग से पशुओं की नस्ल की क्वालिटी सुधरती है चाहे वह मेल या फीमेल हो, उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नस्ल सुधार का काम करते हैं। 90 परसेंट हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं और कई माननीय सदस्यों ने आवारा पशुओं की चर्चा की। आवारा पशुओं का मुख्य कारण यही है कि हमारे मेल पशु जैसे बछड़ा है, इसका उपयोग लोग कुछ दिन तक करते हैं, उसके बाद उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। अगर सेक्स सोर्टेड सीमेन के माध्यम से उनकी क्वालिटी को हमने इम्प्रूव कर दिया तो आवारा पशुओं पर भी हम नियंत्रण करने का काम कर सकेंगे। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।

हम आई.वी.एफ. की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर रहे हैं। आई.वी.एफ. का जो इंजेक्शन है, वह कॉस्टली है। आज की तारीख में उसके तीन शॉट्स का कॉस्ट लगभग 20,000 रुपये हैं, लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने उस पर भी रिसर्च किया और उसके बाद उसकी कीमत 20,000 रुपये से घट जाएगी। उनका मानना है कि अब वह टेस्टिंग में है और अगर वह टेस्ट सफल हुआ तो मात्र 10,000-12,000 रुपये के अन्दर हमें आई.वी.एफ. के इंजेक्शंस मिल जाएंगे। केन्द्र सरकार उसमें

5,000 रुपये का अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। तब वह सभी किसानों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। तब हमारी पशुओं का नस्ल सुधार होने का काम होगा। हम जब सात पीढ़ी तक सुधार नहीं कर सकते, लेकिन आई.वी.एफ. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर एक बार इसके तीन शॉट्स दिए गए तो एक पीढ़ी में हम उस नस्ल का सुधार कर सकते हैं। यह उसकी विशेषता है। आज हमारे देश में 22 आई.वी.एफ. लैब्स कार्यरत हैं और वे सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन, चूंकि उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए हर किसान तक उसकी पहुंच नहीं है, क्योंकि डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में जो लोग हैं, वे सीमान्त किसान हैं, छोटे किसान हैं, गरीब हैं, तो यह आई.वी.एफ. इंजेक्शन उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। हम कटिबद्ध हैं कि इस देश के लोगों को सस्ते दरों पर आई.वी.एफ. टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस को भी उपलब्ध कराएंगे।

महोदय, जैसा कि हमने ?मैत्री? की बात कही, तो हम सेक्स-सॉर्टेड सीमेन और आई.वी.एफ. की सुविधा जो उपलब्ध करवाते हैं, उसमें आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन कार्यक्रम के तहत ?मैत्री? के लोगों को जोड़ा। उसमें हम उन्हें 90 दिनों की ट्रेनिंग देते हैं और 90 दिनों की ट्रेनिंग के बाद वहां भेजते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूध उत्पादन और डेयरी में जो समस्या है, उसमें हमारे कुल उत्पादन की 37 प्रतिशत खपत स्थानीय स्तर पर होती है। जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, वे अपने घरों में इसकी 37 प्रतिशत तक खपत करते हैं और 63 प्रतिशत संगठित और असंगठित क्षेत्रों में दूध का उत्पादन जाता है। लेकिन, उस 63 प्रतिशत में 68 प्रतिशत ऐसा उत्पादन है, जो अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाता है। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है कि हम पूरे असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करें, ताकि दूध उत्पादन के साथ जुड़े लोगों का विकास हो सके। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी के साथ बैठक की है और बैठक करके इस असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ के माध्यम से कैसे विकसित करें और उन्हें संगठित क्षेत्र में लाएं, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि इसको शीघ्र संगठित क्षेत्र में लाएंगे और जैसे ही इसे संगठित क्षेत्र में लाएंगे, हमारे डेयरी उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं, उन किसानों को इसका लाभ मिलने लगेगा और वे खुशहाल होंगे। इसके तहत हम लोग और कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। उसमें कई को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से हम उन्हें संगठित क्षेत्र में लाने का काम करेंगे और उसके बाद हम गुणवत्तापूर्ण दूध देने का काम करेंगे। जो टेस्ट की बात हुई तो दूध को हम दरवाजे पर टेस्ट करेंगे और उसको चिलिंग प्लांट में ले जाएंगे, ताकि उसकी उत्पादकता बढ़े। हम लोग इस आधार पर काम करेंगे।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने रोग नियंत्रण की भी बात कही। हम लोग रोग नियंत्रण पर भी काम कर रहे हैं। एफ.एम.डी., पी.पी.आर., काउ स्वाइन फीवर पर हम लोग टीका देने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव तक टीकाकरण करने का काम कर रहे हैं। रोग नियंत्रण में 100 फीसदी केन्द्रीय सहायता के साथ हम टीकाकरण का काम कर रहे हैं। एफएमडी में हमारा प्रयास है, कई सदस्यों ने बात की है, कोई सदस्य कहीं से बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि गाय का माँस? मैं बताना चाहता हूँ कि गाय का माँस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। यह आप जान लीजिए। आप अपने आपको करेक्ट करने का काम कीजिए। हम बफैलो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं। गाय का माँस का एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ? (व्यवधान) यह आप लोग करते हैं। ? (व्यवधान) अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे। ? (व्यवधान) यह आपका धंधा है। ? (व्यवधान) हम लोग इस काम को नहीं करते हैं। अगर आप लोग चोरी-छुपे भी कर रहे होंगे तो आप समझिए। हम लोग एमवीयू, मोबाइल वैन भी लोगों को दे रहे हैं। वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 4,340 एमवीयू विभिन्न राज्यों को दे चुके हैं। 21 राज्यों में आज भी 3,165 एमवीयू चालू स्थिति में हैं। ? (व्यवधान) 41 लाख किसान अब तक एमवीयू की सुविधा से लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित पशुओं की संख्या 86 लाख है। ? (व्यवधान)

दादा, इसके अलावा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। ? (व्यवधान) आज-कल आप कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं न। ? (व्यवधान) अधीर रंजन चौधरी जी को तो आप लोगों ने विदा करवा दिया। ? (व्यवधान) उनसे तो छुट्टी पा ली है। ? (व्यवधान) यह आप ही लोगों के दबाव का परिणाम है। 60 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं की तो इन तीन करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते? इसलिए आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प विकसित भारत बनाने का लिया है, उन्होंने तीन पर्सेंट लोगों की चिंता की है। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे, तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम कीजिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाले काम था। ये लोग 60 सालों तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में देखें, जिस भी क्षेत्र में देखिए, उस क्षेत्र में आप कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता ज़रूर प्राप्त की है कि पूरे 60 सालों में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो अंबार लग जाएगा, लंबी लाइन लग जाएगी। ? (व्यवधान) इसमें आपने सफलता ज़रूर हासिल की है। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने दस वर्षों में कर के दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर किसी भी काम का बीड़ा उठाया जाए, तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो

उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वे चल रहे हैं, अगले पांच सालों में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और वर्ष 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरी दुनिया के सामने सिर उठा कर खड़े रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में हम लोगों के साथ लग जाइएगा।

यही आग्रह और अपील करते हुए, अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

***m125 माननीय अध्यक्ष:** श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल, श्री लालजी वर्मा, श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, श्री हनुमान बेनीवाल, प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2024-2025 की अनुदानों की मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

?कार्य-सूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 43 और 44 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों के भुगतान के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाएं?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।